रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-73

REGISTERED No. D.(D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 6, 1980/अग्रहायण 15, 1902

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 6, 1980/AGRAHAYANA 15, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

उप-राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1980

का० आ० 3331—भारत के उप-राष्ट्रपति, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के कुलाधिपति की हैसियत से पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-13 की उप-धारा (1)(जे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को 1/11/1980 से 1 मास की अवधि के लिए साधारण पार्षद मनोनीत करते है —

1 प्रो० एम० आर० वर्मा,
8-ए, देशमेश नगर, पुलिस लाइन्स के पीछे, पटियाला

2. प्रो० गुरबचन सिंह तालिब,
80-बी, माडल टाउन, पटियाला

3 डा० रविकान्त शर्मा, एम० एड०, पी० एच० डी,०
जी० डी० सीनियर माडल स्कूल फार ब्वाईज एण्ड गर्ल्स, अबोहर

4 एस० मुबारक सिंह,
44, माडल टाउन, अमृतसर

5 श्रीमती सुरिन्द्र चानना,
द्वारा, डा० चरनजीत चानना (यूनियन मिनिस्टर आफ स्टेट फार इन्डस्ट्री),
नई दिल्ली

6. मिस्टर जस्टिस एम० आर० सोंधी,
भू० पू० जज, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट,
34, सेक्टर-4,
चंडीगढ़

7. डा० गुरदयाल सिंह ढिल्लो,
हाईकमीशनर, भारत सरकार,
ओटावा (कनाडा)

8 प्रो० अब्दुल मजीद खां,
मंझोली (शिमला)

9. डा० श्रीमती साजदा अमद,
1275, बल्लीमारान,
दिल्ली-110006

10 एस० सूजन सिंह,
1310, सेक्टर-19,
चंडीगढ़

11. प्रिन्सिपल आर० एस० बावा,
गवर्नमेन्ट कालेज,
होशियारपुर

12 मि० जस्टिस बी० आर० तुली,
भू० पू० जज, पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट,
111, सेक्टर-9,
चंडीगढ़

13. प्रिन्सिपल त्रिलोकी नाथ,
डारेक्टर, भारतीय विद्याभवन, चंडीगढ़ केन्द्र,
चंडीगढ़

14 श्री आर० एस० चितकारा,
(रिटायर्ड डारेक्टर, यूनिवर्सिटी एजूकेशन मिनिस्ट्री, आफ एजूकेशन एण्ड सोशल वेल्फेयर),

बी-2/59 सफदरजंग इन्क्लेव
नई दिल्ली

15 श्री जगन नाथ कौशल,
मेम्बर पार्लियामेन्ट,
221 सेक्टर-9,
चंडीगढ़

16 श्रीमती गुरबिन्दर कौर बरार, एम० पी०,
64 लोदी एस्टेट
नई दिल्ली

17 श्री सुधाकर पाण्डेय,
गोला दीना नाथ
वाराणसी (उ० प्र०)

18 प्रो० ए० के० शर्मा,
रिजिनल कालेज आफ एजूकेशन,
मैसूर

19 प्रो० बी० बी० लाल
डारेक्टर, इन्स्टीट्यूट आफ एडवान्स स्टडी,
राष्ट्रपति निवास,
शिमला

20 प्रो० एम० आर० चौधरी
रीडर इन माडर्न अरैबिक डिपार्टमेन्ट आफ अरैबिक,
दिल्ली यूनिवर्सिटी,
दिल्ली

21 प्रिन्सिपल जसवन्त कौर
गवरनमेन्ट कालेज फार वीमेन,
चंडीगढ़

22 डा० एल० आर० गोबो,
प्रिन्सिपल, क्रिश्चियन मेडिकल कालेज,
लुधियाना

23 डा० मिस एस० श्रीवास्तव,
प्रिंसिपल देव समाज कालेज आफ एजूकेशन फार वीमेन
फिरोजपुर सीटि।

24 डा० मिस राम राजपूत
लेक्चरार इन पोलिटिकल साइन्स पंजाब यूनिवर्सिटी,
चंडीगढ़

25 डा० रमेश कपूर
रीडर इन केमिस्ट्री,
डिपार्टमेन्ट आफ कैमिस्ट्री, पंजाब यूनिवर्सिटी
चंडीगढ़

26 प्रो० बी० घोष
डिपार्टमेन्ट आफ कैमिकल इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी
पंजाब यूनिवर्सिटी
चंडीगढ़

27 प्रो० जी० पी० शर्मा
505 सेक्टर-36
चंडीगढ़

28 प्रो० वी० एस० डिसोजा,
डिपार्टमेन्ट आफ सोशियालाजी,
पंजाब यूनिवर्सिटी,
चंडीगढ़

29 प्रो० टी० एन० कपूर,
डिपार्टमेन्ट आफ कामर्स एण्ड बिजनेस मैनेजमेन्ट
पंजाब यूनिवर्सिटी,
चंडीगढ़

30 प्रो० गुरदेव सिंह गोसाल
डिपार्टमेन्ट आफ जियाग्राफी,
पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़

31 [illegible]
पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़

32 डीन आफ स्टूडेंट्स वेल्फेयर,
पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़

33 आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद
विद्या निकेतन, खरार,
नजदीक चंडीगढ़

34 मि० जस्टिस वी० एस० देशपाण्डे,
2, डुप्लेक्स लेन,
नई दिल्ली।

[सं० 10-वी० पी०/डी० एस०)]

अमर नाथ भार्गव, भारत के उप-राष्ट्रपति एवं पंजाब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के सचिव

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 1st November, 1980

S.O. 3331.—The Vice-President of India, in his capacity as Chancellor of the Punjab University, Chandigarh, in exercise of his powers under sub-section 1(j) of Sec. 13 of the Panjab University Act, is pleased to nominate the following persons as Ordinary Fellows of the Punjab University for the term commencing November 1, 1980, for a period of four years —

1 Professor M. R. Verma, 8A, Deshmesh Nagar, behind Police Lines, Patiala

2 Professor Gurbachan Singh Talib, 80-B, Model Town, Patiala

3 Dr. Ravi Kant Sharma, M.Ed., Ph. D., G.O. Senior Model School for boys and Girls, Abohar.

4 S. Mubarak Singh, 44, Model Town, Amritsar

5 Mrs Surinder Chanana, C/o Dr. Charanjit Chanana, Union Minister of State for Industry, New Delhi

6 Mr Justice H. R. Sodhi, Former Judge, Punjab and Haryana High Court, 34, Sector 4, Chandigarh

7 Dr Gurdial Singh Dhillon High Commissioner, Government of India, Ottawa (Canada)

8 Professor Abdul Majid Khan, Sanjauli (Simla)

9 Dr Mrs Majida Asad, 1275, Ballimaran, Delhi-6

10 S. Sujan Singh, 1310, Sector 19, Chandigarh

11 Principal R. S. Bawa, Government College, Hoshiarpur

12 Mr Justice B. R. Tuli, Former Judge, Punjab and Haryana High Court 111, Sector 9, Chandigarh

13 Principal Triloki Nath, Director, Bharatiya Vidya Bhavan, Chandigarh Kendra, Chandigarh

14 Shri R. S. Chitkara, (Retired Director, University Education, Ministry of Education and Social Welfare), B-2/59, Safdarjung Enclave, New Delhi

15 Shri Jagan Nath Kaushal, Member Parliament, 221, Sector 9, Chandigarh

16 Shrimati Gurbinder Kaur Brar, Member Parliament, 64, Lodhi Estate, New Delhi.

17 Shri Sudhakar Pandey,
Gola Dina Nath, Varanasi (U.P.)

18 Professor A. K. Sharma,
Rgional College of Education,
Mysore

19 Professor B. B. Lal,
Director, Institute of Advanced Study,
Rastrapati Niwas, Simla

20. Professor S. R. Chowdhury,
Reader in Modern Arabic,
Department of Arabic, Delhi University.
Delhi.

21. Principal Jaswant Kaur,
Government College for Women,
Chandigarh.

22. Dr. I. H. Lobo,
Principal, Christian Medical College,
Ludhiana.

23. Dr. Miss S. Srivastava.
Principal, Dev Samaj College of Education for Women,
Ferozepur City.

24. Dr. Miss Pam Rajput.
Lacturer in Political Science,
Panjab University, Chandigarh.

25. Dr. Ramesh Kapoor,
Reader in Chemistry,
Department of Chemistry, Panjab University,
Chandigarh

26. Professor B. Ghosh.
Department of Chemical Engineering & Technology,
Panjab University, Chandigarh.

27. Professor G. P. Sharma,
505, Sector 36, Chandigarh.

28. Professor V. S. D'Souza,
Department of Sociology,
Panjab University, Chandigarh

29. Professor T. N. Kapoor,
Department of Commerce & Business Management,
Panjab University, Chandigarh.

30. Professor Gurdev Singh Gosal,
Department of Geography,
Panjab University, Chandigarh.

31. Dean of University Instruction,
Panjab University, Chandigarh

32. Dean of Student Welfare,
Panjab University, Chandigarh.

33. Acharya Prithvi Singh Azad,
Vidya Niketan, Kharar, near Chandigarh.

34. Mr. Justice V. S. Deshpandey,
2, Duplex Lane, New Delhi.

[No 10-VC/DS]
A. N. OBEROI, Secy.
to the Vice-President of India & Chancellor,
Panjab University, Chandigarh.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1980

का० आ० 3332.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स ट्रिची स्टील रौलिंग मिल्स लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या 1288/76) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं० 16/32/80-एम3]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 15th November, 1980

S.O. 3332.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies & Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of Messrs Trichy Steel Rolling Mills Limited under the said Act (Certificate of Registration No. 1288/76).

[No. 16/32/80-M. III]

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1980

का० आ० 3333.—एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स सायनामिड इंडिया लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1227/75) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं० 16/28/80-एम-3]
सी० खुशाल दास निदेशक

New Delhi, the 20th November, 1980

S.O. 3333.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies & Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Cyanamid India Limited under the said Act (Certificate of Registration No 1227/75.

[No. 16/28/80-M. III]
C. KHUSHALDAS, Director

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली 11 नवम्बर, 1980

का० आ० 3334.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में गृह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालय को जिस के कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. आयुक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कार्यालय, रामाकृष्ण पुरम, नई दिल्ली।

[संख्या 12017/1/80-हिन्दी]
अशोक कुमार वर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 11th November, 1980

S.O. 3334.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of the Ministry of Home Affairs, the Staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Office of the Commissioner for Scheduled Castes & Scheduled Tribes, Ramakrishna Puram, New Delhi.

[No. 12017/1/80-Hindi]
A. K. VARMA, Dy. Secy.

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1980

का० आ० 3335.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट, इर्नाकुलम के न्यायालय में मैसर्स निमस एक्सपोर्टस, कोचीन मेथा 3 अन्यों के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 9/ई/77 मद्रास में अभियोजन का संचालन करने के लिए श्री एम० बी० रुप, अधिवक्ता, इर्नाकुलम को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 225/65/80-ए० वी० डी० (II)]

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 17th November, 1980

S.O. 3335.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri M. B. Kurup, Advocate, Ernakulam, as Special Public Prosecutor for conducting the prosecution of case No. RC. 9/E/77/Madras, against M/s. Nimas Exports, Cochin and 3 others in the Court of the Chief Judicial Magistrate, Ernakulam.

[No. 225/65-80-AVD-II]

का०आ० 3336.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अहमदाबाद (ग्रामीण), नरोल के न्यायालय में मैसर्स वीरजी शिवदास एण्ड सन्स अमरेली (गुजरात) के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 4/77/सी०आई०यू० (ई०) 1, नई दिल्ली में अभियोजन का संचालन करने के लिए श्री जी०पी० मोटवानी, अधिवक्ता, अहमदाबाद को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 225/67/80-ए० वी० डी० (II)]
टी०के० सुब्रमणियन, अवर सचिव

S.O. 3336.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri G. P. Motwani, Advocate, Ahmedabad as Special Public Prosecutor for conducting the prosecution of Case No. RC. 4/77/CIU(E)-I, New Delhi against M/s. Virji Shivdas and Sons, Amreli (Gujarat) in the Court of the Chief Judicial Magistrate, Ahmedabad (Rural) Narol.

[No. 225/67/80-AVD-II]
T. K. SUBRAMANIAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1980

आयकर

का० आ० 3337.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) का अनुसरण करते हुए तथा भारत सरकार के राजस्व विभाग की 3 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना सं० 3232 (फा०सं० 404/113/क०व०अ०-रोहतक/79-आ०क०स०क०) का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एस०पी० महाजन को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री एस०पी० महाजन द्वारा कर वसूली अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 3720 (फा०सं० 398/13/80-आ०क०स०क०)]
एच० वेंकटरामन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 3rd November, 1980

INCOME TAX

S.O. 3337.—In pursuance of sub-clause (iii) of Clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3232 (F. No. 404/113/TRO-Rohtak/79-ITCC) dated 3rd April, 1980, the Central Government hereby authorises Shri S. P. Mahajan being a gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri S. P. Mahajan takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 3720 (F. No. 398/13/80-ITCC)]
H. VENKATARAMAN, Dy. Secy.

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1980

स्टाम्प

का०आ० 3338—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा गुजरात राज्य पथ परिवहन निगम को, बयासी हजार पाच सौ रुपये मात्र का वह समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति देती है, जो उक्त निगम द्वारा 1 करोड़ दस लाख रुपये के अंकित मूल्य वाले ऋण पत्रों के रूप में जारी किये जाने वाले बंध पत्रों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क के रूप में प्रभार्य है।

[सं० 21/80/स्टाम्प/फा०सं० 33/21/80 बि० क०]
जी० एस० मेहरा, अवर सचिव

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 18th November, 1980

STAMPS

S.O. 3338.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Gujarat State Road Transport Corporation to pay consolidated stamp duty of eighty two thousand five hundred rupees only, chargeable on acount of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the face value of One crore and ten lakhs of rupees to be issued by the said Corporation.

[No. 21/80-Stamps- F. No. 33/21/80-ST]
G. S. MEHRA, Under Secy.

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1980

का०आ० 3339.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित वित्तीय संस्था को, जिसके कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:—

"भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) के अधीन निर्गमित), बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16 संसद मार्ग, पोस्ट बाक्स संख्या 363 नई दिल्ली-110001।"

[संख्या ई०-11017/3/80—हिन्दी]
बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 11th November, 1980

S.O. 3339.—In pursuance of sub-rule 4 of rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following financial institution, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

Industrial Finance Corporation of India [Incorporated under the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (XV of 1948)], Bank of Baroda Building, 16 Sansad Marg, New Delhi-110001.

[No. E-11017/3/80-Hindi]

BALDEV SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली 15 नवम्बर, 1980

का० आ० 3340.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 15(1) के उपबन्ध वर्ष 1979 के लिए 5 प्रतिशत का लाभांश (कर मुक्त) घोषित करने के प्रयोजन के लिए पूर्वांचल बैंक लिमिटेड, गौहाटी पर लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15/34/80-बी० ओ०-III]

New Delhi, the 15th November, 1980

S.O. 3340.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 15(1) of the said Act, shall not apply to the Purbanchal Bank Ltd., Gauhati, for declaration of dividend of 5 per cent for the year 1979 (subject to tax).

[No. 15/34/80-B.O. III]

का० आ० 3341.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि, उक्त अधिनियम की धारा 10ख की उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध रत्नाकर बैंक लि०, कोल्हापुर पर 6 दिसम्बर, 1980 तक अथवा जब तक उक्त बैंक में पूर्वकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती, इनमें से जो भी पहले हो, लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15/35/80-बी०ओ०-III]

S.O. 3341.—In exercise of powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-sections (1) and (2) of Section 10B of the said Act, shall not apply to Ratnakar Bank Ltd., Kolhapur, upto 6th December 1980, or till the appointment of the next whole-time Chairman of that bank, whichever is earlier.

[No. 15/35/80-B. O. III]

का० आ० 3342.—जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि :—

(क) स्टेट बैंक आफ पटियाला की पालमपुर शाखा के प्रबन्धक श्री हरद्वारी लाल ने, जिनकी नियुक्ति भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 38 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा हिमालय बैंक लिमिटेड के पुरातन कोष (ओल्ड फंड) के पदेन प्रबन्धक के तौर पर, इसके कार्यकलापों में एवं परिसम्पत्ति के वितरण आदि के परिसमापन के लिए की गई थी, पालमपुर कार्यालय से अपने स्थानान्तरण के फलस्वरूप, 10 जुलाई 1980 से उस पदभार को छोड़ दिया।

(ख) श्री वी०पी० साही ने, जिनकी नियुक्ति स्टेट बैंक आफ पटियाला की पालमपुर शाखा में श्री हरद्वारी लाल के उत्तरवर्ती के रूप में प्रबन्धक के पद पर की गई थी, हिमालय बैंक लि० के पुरातन कोष के पदेन प्रबन्धक का पद भार 10 जुलाई 1980 से संभाल लिया।

[संख्या 4/41/80-बी० ओ०-III]

एन० डी० बत्रा, अवर सचिव

S.O. 3342.—It is hereby notifies for the information of the general public that

(a) Shri Hardwari Lal, Manager of Palampur branch of the State Bank of Patiala, who was appointed by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (9) of Section 38 of the State Bank of India (Subsidiary banks) Act, 1959 (38 of 1959) as the Manager Ex. Officio of the Old Fund of the Himalaya Bank Ltd., for the purposes of winding up of its affairs and distributing its assets, ceased to hold that office with effect from 10th July, 1980 consequent on his transfer from Palampur.

(b) Shri V. P. Sahi, who was appointed as Manager of the Palampur branch of the State Bank of Patiala in succession to Shri Hardwari Lal, took charge of his office as the Manager, Ex-officio of the Old Fund of the Himalaya Bank Ltd., on the 10th July, 1980.

[No. 4/41/80-B.O.-III]

N. D. BATRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1980

का० आ० 3343.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की दिनांक 23 जून, 1980 की एस संख्या अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त करती है। इसके परिणामस्वरूप, मयूराक्षी ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंगाल राज्य के बीरभूम जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ० 2-7/79-आर० आर० बी०]

दिनेश चन्द्र, निदेशक

New Delhi, the 21st November, 1980

S.O. 3343.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby rescinds the amendment made vide this Department's notification of even number dated 23rd June, 1980. Consequently Mayurakshi Gramin Bank shall operate within the local limits of the district of Birbhum in the State of West Bengal.

[No. F. 2-7/79-RRB]

DINESH CHANDRA, Director.

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1980

का० आ० 3344.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री शक्तिपद पाणिग्रही को वर्धमान ग्रामीण बैंक वर्धमान का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 25-11-1980 से प्रारम्भ होकर 24-11-1983 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री शक्तिपद पाणिग्रही अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 1-24/80-आर० आर० बी०]

इन्द्राणी सेन, अवर सचिव

New Delhi, the 24th November, 1980

S.O. 3344.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Saktipada Panigrahi as the Chairman of the Bardhaman Gramin Bank, Burdwan and specifies the period commencing on the 25th November, 1980 and ending with the 24th November, 1983 as the period for which the said Shri Saktipada Panigrahi shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-24/80-RRB]

INDRANI SEN, Under Secy.

(आयकर आयुक्त का कार्यालय विदर्भ)

नागपुर, 10 नवम्बर, 1980

का० आ० 3345.—चूंकि केन्द्रीय सरकार की राय में यह आवश्यक और उचित है कि तारीख 31-3-1980 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की अवधि में कर के बकायादार निर्धारितियों, जिनके मामलों में एक लाख से अधिक रुपयों का भुगतान दो वर्ष या उससे अधिक समय से नहीं हुआ है, उनके नाम और पतों को लोक हित में प्रकाशित किया जाएगा ।

और चूंकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 287 (1961 का 43) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा ऐसी अन्य सभी शक्तियों द्वारा जिसके लिए उनको समर्थ किया गया हो, प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार अपने ता० 10 अगस्त, 1977 के आदेश फा० सं० 385/63-आयटी (बी) द्वारा आयकर आयुक्त को प्राधिकृत करती है और निदेश देती है कि ऐसे कर बकायादार चूक कर्ताओं के नाम और पतों को प्रकाशित करें ।

अतः मैं आयकर आयुक्त, विदर्भ, नागपुर अब एतद्द्वारा विदर्भ, प्रभार के वित्तांक 31-3-1980 तक के वित्तीय वर्ष 1979-80 के कर बकायादारों के नाम और पतों को प्रकाशित करता हूं ।

क्र० सं०	बकायादारों का नाम और पता	हैसियत	31-3-1980 को बकाया रही मांग
1	2	3	4
			रु०
1.	श्री बनवारी लाल लोहिया, कामठी	हि०अ० कु०	2,11,894
2.	मे० बिड़ी एण्ड अलाइड टोबैको प्राडेक्ट्स कं० (प्रा०) लिमिटेड, कामठी ।	कम्पनी	6,99,782
3.	मे० भारत माइनिंग एण्ड ट्रेडिंग कं० प्रा० लिमिटेड, विशाखापट्टनम् ।	कम्पनी	2,93,609
4.	श्री सूरमल अग्रवाल, तुमसर	व्यष्टि	5,36,889
5.	श्री चन्द्रकान्त मोर, तुमसर	व्यष्टि	8,46,288
6.	श्री चन्द्रकान्त मोर, तुमसर	हि०अ०कु०	12,26,445
7.	मे० सेन्ट्रल हिन्दुस्थान इटालियन ट्रेडिंग कं० (प्रा०) लि० नागपुर ।	कम्पनी	2,85,008
8.	श्री दुर्गाप्रसाद सराफ, तुमसर	व्यष्टि	5,20,212
9.	मे० डिलर्स एण्ड कं० प्रा० लि०, जयपुर ।	कम्पनी	5,16,407
10.	स्व० श्री फतेचन्द मोर द्वारा वि० उ० श्री रामनारायण मोर, तुमसर ।	व्यष्टि	21,71,022
11.	मे० गुप्ताघाट माईन्स, तुमसर	पं० फर्म	2,35,000
12.	श्री गुलाबदास रामविलास अग्रवाल, नागपुर	व्यष्टि	4,32,055
13.	श्री जी० व्ही० रानडे, नागपुर	व्यष्टि	1,69,515
14.	श्री हालिमभाई, द्वारा मे०के०एम०एम० हुसनजी ऐण्ड सन्स, नागपुर ।	व्यष्टि	1,57,090
15.	मे० जैपुरिया ब्रदर्स, तुमसर	पं० फर्म	20,0000
16.	मे० के०एम०एम० हुसनजी ऐण्ड सन्स, नागपुर	व्यष्टि	4,89,177
17.	मे० लोहिया ब्रदर्स, कामठी	पं० फर्म	9,87,953
18.	स्व० श्री नरसिंगदास मोर, द्वारा श्री चन्द्रकान्त मोर, तुमसर ।	व्यष्टि	25,75,,613
19.	श्री पी० बी० मुधड़ा, नागपुर	व्यष्टि	10,83,949
20.	मे० आर० आर० लोहिया सन्स, कामठी	अं० पी० फर्म	4,10,395
21.	श्री राधाकृष्णन लोहिया, कामठी	हि०अ०कु०	4,31,790
22.	मे० रामकृष्णन रामनाथ (हि०अ०कु०) कामठी	हि०अ०कु०	6,58,742
23.	श्री रमाकान्त लोहिया, कामठी	हि०अ०कु०	2,04,960
24.	श्री रामचन्द्र मोटर ट्रान्सपोर्ट कं० प्रा० लि० अमरावती ।	कम्पनी	3,46,057
25	मे० रामविलास मुरलीधर एण्ड बलराम लोखुराम,तुमसर	पं० फर्म	127,357
26.	मे० आर० एस० गोपिकिसन अग्रवाल (शीपर्स) कं० प्रा० लि०, तुमसर ।	कम्पनी	15,17,549
27.	श्री रामकुमार रामगोपाल बोहरा द्वारा मे० आर० बी० श्रीराम एण्ड कं० तुमसर ।	व्यष्टि	2,41,659
28.	मे०रामविलास गुलाबदास, तुमसर	हि०अ०कु०	31,22,123
29.	मे० आर०बी० श्रीराम रिलिजियस ट्रस्ट एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, तुमसर।	ट्रस्ट	2,05,167
30.	मे० आर० बी० श्रीराम दुर्गाप्रसाद प्रा० लि०, तुमसर ।	कम्पनी	2,34,29,049
31.	मे० रामकृष्ण रामनाथ (बीडी (प्रा०) लि०, कामठी ।	कम्पनी	5,46,292
32.	मे० रामेश्वरदास रामदास, जयपुर	व्यष्टि	18,13,242
33.	श्री रामनारायण मोर, तुमसर	हि०अ०कु०	21,37,405
34.	मे० आर० आर० अग्रवाल (प्रा० लि०) नागपुर ।	कम्पनी	1,23,228
35.	मे० रामकृष्ण रामनाथ, कामठी	पं० फर्म	2,59,603
36.	श्री संतोषकुमार, अग्रवाल, तुमसर	व्यष्टि	3,28,765
37.	श्री शंकरराव डी० धनवटे, नागपुर	हि०अ०कु०	1,05,000
38.	स्व० श्रीराम डालुराम द्वारा वि०उ० श्री दुर्गाप्रसाद सराफ, तुमसर ।	व्यष्टि	3,69,975
39.	मे० श्रीराम दुर्गाप्रसाद, तुमसर	हि०अ०कु०	14,46,515
40.	मे० शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्कस, नागपुर ।	हि०अ०कु०	2,11,000
41.	स्व० श्रीमती सुनीदेवी सराफ द्वारा वि० उ० श्री दुर्गाप्रसाद सराफ, तुमसर ।	व्यष्टि	10,32,227
42.	मे० व्ही० डी० सराफ कान्मांडु	हि०अ०कु०	2,60,535
43.	श्री वाय० डी० धनवटे, नागपुर	हि०अ०कु०	1,38,000

[एफ० सं० वसूली (64)/79-80]

डी० सी० अग्रवाल, आय-कर आयुक्त

Office of the commissioner of Income-tax Vidarbha

Nagpur, the 10th November, 1980

S.O. 3345.—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to publish the names and addresses hereinafter specified relating to the tax defaulters who were in default of payment of tax of Rs. 1 lakhs and above for the period of two years or more at the end of the financial year ending 31-3-1980.

2. And whereas in exercise of the powers conferred by Section 287 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in this behalf the Central Government by its order F. No. 385/63-IT(B) dated 10th August, 1977, authorised and directed Commissioner of Income-tax to publish the names and addresses of such tax defaulters.

3. Now therefore, I ,Commissioner of Income-tax, Vidarbha, Nagpur hereby publish the names and addresses of the defaulters in Vidarbha Charge as on 31-3-1980 relating to the financial year 1979-80.

Sl. No.	Name & Address of the Defaulter	Status	Demand Outstanding 31-3-1980
1	2	3	4
			Rs.
1.	Shri Banwarilal Loiya, Kamptee	HUF	2,11,894
2.	M/s. Bidi & Allied Tobacco Products Co. (Pvt.) Ltd., Kamptee.	Co.	6,99,782
3.	M/s. Bharat Mining and Trading Co. Pvt. Ltd., Vishakhapatnam.	Co.	2,93,609
4.	Shri Bhoormal Agarwal, Tumsar.	Indl.	5,36,889
5.	Shri Chandrakant Mor, Tumsar.	Indl.	8,46,288
6.	Shri Chandrakant Mor, Tumsar.	HUF.	12,26,445
7.	M/s. Central Hindustan Italian Trading Co. (P) Ltd., Nagpur.	Co.	2,85,008
8.	Shri Durgaprasad Saraf, Tumsar.	Indl.	5,20,212
9.	M/s. Dealers & Co. Pvt. Ltd., Jaipur	Co.	5,16,407
10.	Late Shri Fatechand Mor through L/H Shri Ramnarayan Mor, Tumsar.	Indl.	21,17,02
11.	M/s. Gudraughat Mines, Tumsar.	R.F.	2,35,000
12.	Shri Gulabdas Rambilas Agarwal, Nagpur.	Indl.	4,32,055
13.	Shri G.V. Ranade, Nagpur.	Indl.	1,69,515
14.	Shri Hatimbhai, C/o M/s. K.S. M. Hassonjee & Sons, Nagpur.	Indl.	1,57,090
15.	M/s. Jaipuria Brothers, Tumsar.	R.F.	2,00,000
16.	M/s. K.S.M. Hassonjee & Sons, Nagpur.	Indl.	4,89,177
17.	M/s. Loiya Brothers, Kamptee.	R.F.	9,87,953
18.	Late Shri Narsingdas Mor, through Shri Chandrakant Mor, Tumsar.	Indl.	25,75,613
19.	Shri P.B. Mundhada, Nagpur.	Indl.	10,83,949
20.	M/s. R.R. Loiya Sons, Kamptee.	URF.	4,10,395
21.	Shri Radhakishan Loiya Kamptee	HUF	4,31,790
22.	M/s. Ramkrishna Ramnath (HUF), Kamptee.	HUF.	6,58,742
23.	Shri Ramakant Loiya, Kamptee.	HUF.	2,04,960
24.	Shri Ramchandra Motor Transport Co. Pvt. Ltd., Amravati.	Co.	3,46,057
25.	M/s. Rambilas Murlidhar & Balarram Toluram, Tumsar.	R.F.	1,27,357
26.	M/s. R.S. Gopikishan Agarwal (Shippers) Co. Pvt. Ltd., Tumsar.	Co.	15,17,549
27.	Shri Ramkumar Ramgopal Bohra through M/s. R.B. Shriram & Co., Tumsar.	Indl.	2,41,659
28.	M/s. Rambilas Gulabdas, Tumsar.	HUF.	31,22,123
29.	M/s. R.B. Shreeram Religious & Charitable Trust, Tumsar.	Trust	2,05,167
30.	M/s. R.B. Shreeram Durgaprasad Pvt. Ltd., Tumsar.	Co.	2,34,29,049
31.	M/s. Ramkrishna Ramnath Bidi (P.) Ltd., Kamptee.	Co.	5,46,292
32.	M/s. Rameshwardas Ramdas, Jaipur.	Indl.	18,13,242
33.	Shri Ramnarayan Mor, Tumsar.	HUF.	21,37,405
34.	M/s. R.R. Agarwal (P) Ltd., Nagpur.	Co.	1,23,228
35.	M/s. Ramkrishna Ramnath, Kamptee.	R.F.	2,59,603
36.	Shri Santoshkumar Agarwal, Tumsar.	Indl.	3,28,766
37.	Shri Shankarrao D. Dhanwatey, Nagpur.	HUF.	1,05,000
38.	Late Shreeram Doluram through L/H Shri Durgaprasad Saraf, Tumsar.	Indl.	3,69,975 3,69,975
39.	M/s. Shreeram Durgaprasad, Tumsar.	HUF.	14,46,515
40.	M/s. Shivraj Fine Arts Litho Works, Nagpur.	HUF.	2,11,000
41.	Late Smt. Sugnidevi Saraf through L/H. Shri Durgaprasad Saraf, Tumsar.	Indl.	10,32,227
42.	M/s. V.D. Saraf, Kathamandu.	HUF.	2,60,535
43.	Shri Y.D. Dhanwatey, Nagpur.	HUF.	1,38,000

[F. No. Recy. (64)/79-80]

D.C. AGGARWAL, Commissioner of Income-tax

(आयकर आयुक्त का कार्यालय, हरियाणा)

रोहतक 21 नवम्बर, 1980

आयकर

का० आ० 3346.—यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि ऐसे करदाताओं के नाम तथा उनसे सम्बन्धित अन्य विशिष्टियां प्रकाशित की जाएं, जिन पर वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान 5,000 रु० से अधिक का जुर्माना लगाया गया था।

और यत: आयकर अधिनियम, (1961 का 43) की धारा 287 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने अपने विनांक 10

अगस्त, 1977 के आदेश द्वारा सभी आयकर आयुक्त को, उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर ऐसे करदाताओं के नाम, पते, हैसियत, कर निर्धारण वर्ष तथा लगाए ऐसे जुर्माने का ब्यौरा जिस में करदाताओं से सम्बन्धित जुर्माने की राशि तथा प्रकृति (प्रकार) भी शामिल होगी तथा जिन पर वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान 5,000 रु० से अन्य का जुर्माना लगाया गया था, प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत किया है ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके दिनांक 10 अगस्त, 1977 के पूर्वोक्त आदेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इससे संलग्न अनुसूची में पूर्वोक्त करदाताओं के नाम तथा अन्य विशिष्टियों एतद्द्वारा प्रकाशित करता हूं :

अनुसूची

आयकर विभाग, हरियाणा, रोहतक

ऐसे करदाता, जिन पर वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान आय की विवरणी फाइल न करने के कारण 5,000 रु० से अन्यून का जुर्माना लगाया गया था (i) हैसियत के लिए 'एफ' फर्म के लिए (ii) कर निर्धारण वर्ष के लिए तथा (iii) लगाए गए जुर्माने के लिए है ।

(1) मैसर्स हरियाणा एजेन्सी, फरीदाबाद (i) 'एफ' (ii) 1977-78 (iii) 5,220 रु०

[फा० सं० 418(2)/79-80/मुख्य०]

टी० आर० अग्रवाल, आयकर आयुक्त

(Office of the Commissioner of Income Tax, Haryana)

Rohtak, the 21st November, 1980

INCOME-TAX

S.O. 3346.—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to publish the names and other particulars relating to assessees on whom penalty of not less than Rs. 5,000 was imposed during the financial year 1979-80.

And whereas in exercise of the powers conferred by section 287 of the Income-tax Act (43 of 1961), and all other powers enabling them in this behalf, the Central Government has by its order dated 10th August, 1977 authorised all Commissioners of Income-tax to publish the names, addresses, status, assessment year and details of penalties levied which would include the amounts and nature of penalties relating to assessees, within their jurisdiction and on whom a penalty of not less than Rs. 5,000 was imposed during the financial year 1979-80.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by the Central Government by its aforesaid order dated 10th August, 1977, I hereby publish in schedule hereto annexed, the names and other particulars of the assessees aforesaid.

SCHEDULE

Income Tax Department, Haryana, Rohtak

Assessees on whom a penalty of not less than Rs. 5,000 was imposed for late filing of return during the financial year 1979-80 (i) is for status 'F' for firm (ii) for assessment year and (iii) for penalty imposed

1. M/s. Haryana Agencies, Faridabad (i) 'F' (ii) 1977-78 (iii) Rs. 5,220.

[F. No. 418(2)/79-80/HQ]

T. R. AGGARWAL, Commissioner of Income-Tax

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1980

का० आ० 3347—केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि ट्रांसफार्मर निर्यात से पूर्व निरीक्षण के अधीन होंगे ,

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और वे निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिए हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार उक्त उप-नियम के अनुसरण में और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2274 तारीख 9 जुलाई, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए उक्त प्रस्ताव को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है ।

2. सूचना दी जाती है कि यदि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई व्यक्ति कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है तो उन्हें उसे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, "वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर", 14/1बी०, एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-700003 को भेज सकता है ।

प्रस्ताव

(1) अधिसूचित करना कि ट्रांसफार्मर निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे ;

(2) इस आदेश के उपाबंध-I में उपवर्णित ट्रांसफार्मर निर्यात (क्वालिटी-नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980 के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व ऐसे ट्रांसफार्मरों को लागू होगा ;

3. (क) आयातकर्ता या आयातकर्ता का अभिकर्ता या उप ठेकेदारों के संविदात्मक विनिर्देशों को, सुनिश्चित परिचालन विशेषताएं और/या सुनिश्चित यांत्रिक संरचना अनुबंधित करते हुए तथा जहां आवश्यक हो सुनिश्चित सेवा की परिस्थितियों वाले, विशेष उपयोगों को अनुबंधित करते हुए परन्तु यह तब जब कि संविदात्मक विनिर्देशों में सुख्त परामीटर यदि कोई हो नीचे के (ख) या (ग) या (घ) या (ङ) के अनरूप होंगे ,

या

(ख) भारतीय या किसी अन्य राष्ट्रीय मानक विनिर्देश को,

या

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग की सिफारिसों को ;

या

(घ) किसी देश के सरकारी विभाग या लोक उपयोगी संस्था द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों को,

या

(ङ) किसी यूनिट के तकनीकी सहयोगियों द्वारा अनुरक्षण किए जाने वाले विनिर्देशों को मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना ।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे ट्रांसफार्मरों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरणों में से किसी एक अभिकरण

द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि ट्रांसफार्मरों का परेषण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करता है और निर्यात योग्य है।

3 इस आदेश में "ट्रांसफार्मर" से लगातार चलने वाले पुर्जों से रहित एक ऐसा साधित्र अभिप्रेत है जो एक या अधिक कुण्डलन में प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा का विद्युत् चुम्बकीय प्रेरणा द्वारा सामान्यतः वोल्टता और धारा के विभिन्न मानों पर और एक ही आवृत्ति पर एक या अधिक कुण्डलनों में परिवर्तित कर देता है। इसके अन्तर्गत घरेलू प्रयोजनों और रेडियो दूरसंचार परिपथों में प्रयोग किए गए ट्रांसफार्मर नहीं हैं।

उपाबंध-1

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —इन नियमों का संक्षिप्त नाम ट्रांसफार्मरों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980 है।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "ट्रांसफार्मर" से लगातार चलने वाले पुर्जों से रहित एक ऐसा साधित्र अभिप्रेत है जो एक या अधिक कुण्डलन से प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा को विद्युत्—चुम्बकीय प्रेरणा द्वारा सामान्यतया वोल्टता एवं धारा के विभिन्न मानों पर और एक ही आवृत्ति पर एक या अधिक कुण्डलनों में परिवर्तित कर देता है। इसके अंतर्गत घरेलू प्रयोजनों और रेडियो दूरसंचार परिपथों में प्रयोग किए गए ट्रांसफार्मर नहीं हैं।

3. क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण :—(1) विनिर्माता ट्रांसफार्मर की क्वालिटी इन नियमों की अनुसूची 1 में संलग्न सारणी में विनिर्दिष्ट विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रमों पर नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए सुनिश्चित करेगा।

(2) उप-नियम (1) में वर्णित विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रमों पर नियंत्रण निम्नलिखित है :—

(i) क्रय की गई सामग्री और घटकों का नियंत्रण :—

(क) प्रयोग की जाने वाली सामग्री या घटकों के गुणों और सहयताओं सहित उनके सविस्तार विशदों को समाविष्ट करते हुए विनिर्माता क्रय विनिर्देश अधिकथित करेगा।

(ख) प्रदायकर्ता के परीक्षण प्रमाण-पत्र कच्ची सामग्री जैसे कोरशीट, कुण्डलन तार, ट्रांसफार्मरों का तेल और प्रेस बोर्ड के लिए और बुशिंग, आयल टी० सी० पम्प, पंखे, रेडियेटर, उपकरण वारित्र जैसे घटकों के लिए पेश किए जाएंगे। जब कच्ची सामग्री या घटकों के लिए प्रदायकर्ता के परीक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाते हैं तब प्रदायकर्ता की परीक्षण रिपोर्टों की प्रतिजांच की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदायकर्ता की परीक्षण रिपोर्ट न होने की दशा में प्रत्येक परेषण में से नमूनों का क्रय विनिर्देशों से उनकी अनुरूपता की जांच करने के लिए नियमित रूप से परीक्षण किया जाएगा।

(ग) खंड (ख) में वर्णित घटकों से भिन्न आवक घटकों का परीक्षण और निरीक्षण सांख्यिकीय नमूना योजना के विपरीत क्रय विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

(घ) निरीक्षण या परीक्षण या दोनों किए जाने के पश्चात् दोषों का उचित पृथक्करण और निपटान के लिए व्यवस्थित पद्धति अपनाई जाएगी।

(ङ) विनिर्माता उपरोक्त नियंत्रणों के संबंध में पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखेगा।

(2) प्रक्रिया नियंत्रण

(क) विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए विनिर्माता द्वारा विस्तृत प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देशों में अधिकथित प्रक्रिया नियंत्रण के लिए उपस्करों या उपकरण की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणों व सत्यापन करने के लिए विनिर्माता पर्याप्त अभिलेख रखेगा।

(3) उत्पाद नियंत्रण :

(क) मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का परीक्षण करने के लिए विनिर्माता के पास या तो स्वयं की परीक्षण सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच वहां तक होगी जहां ऐसी परीक्षण सुविधाएं विद्यमान हैं। विनिर्माता उसके पर्याप्त अभिलेख रखेगा।

(4) मौसम संबंधी नियंत्रण—परीक्षण में प्रयुक्त विद्युत मापी उपकरणों और प्रक्रिया नियंत्रण के लिए प्रयुक्त नाजुक उपकरणों की समय-समय पर जांच की जाएगी या उनका अंशशोधन किया जाएगा और विनिर्माता बुककार्ड के रूप में अभिलेख रखेगा।

(3) निरीक्षण :

निर्यात के लिए आशयित ट्रांसफार्मरों का निरीक्षण इसके साथ उपाबन्ध अनुसूची 2 तथा अनुसूची 3 के अनुसार परेषण में से नमूने लेकर इस दृष्टि से उनका परीक्षण तथा जांच करने के लिए किया जाएगा कि परेषण अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

4 निरीक्षण का आधार —निर्यात के लिए आशयित ट्रांसफार्मरों का निरीक्षण यह देखने की दृष्टि से कि वे अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य विनिर्देशों के अनुरूप हैं;

या

(क) यह सुनिश्चित करके कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान नियम 3 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट क्वालिटी नियंत्रण क्रियों का प्रयोग किया गया है :

या

(ख) नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार किए गए निरीक्षण के आधार पर :

(ग) या दोनों द्वारा,
किया जाएगा।

5 प्रक्रिया नियंत्रण—(1) ट्रांसफार्मरों के परेषणों का निर्यात करने का इच्छुक निर्यात कर्ता संविदात्मक विनिर्देश के ब्यौरे उपवर्णित करते हुए अभिकरण को लिखित रूप में सूचित करेगा तथा ऐसी सूचना के साथ यह घोषणा भी भेजेगा कि निर्यात के लिए आशयित ट्रांसफार्मरों के परेषण का विनिर्माण नियम 3 में अधिकथित क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग करके किया गया है तथा इस परेषण प्रयोजन के लिए मान्य विनिर्देश की अपेक्षाओं के अनुरूप है। निर्यातकर्ता उसी समय ऐसी सूचना की एक प्रति निर्यात निरीक्षण परिषद् के निकटतम कार्यालय को पृष्ठांकित करेगा। परिषद् के कार्यालयों के पते निम्न प्रकार हैं :—

मुख्य कार्यालय : निर्यात निरीक्षण परिषद्,
'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर,
14/1बी० एज़रा स्ट्रीट, 8वीं मंजिल,
कलकत्ता-700001

प्रादेशिक कार्यालय : निर्यात निरीक्षण परिषद्,
'अमन चैम्बर्स' 5 वी मंजिल,
113, महर्षि कार्वे रोड,
मुम्बई-400004
निर्यात निरीक्षण परिषद्,
मनोहर बिल्डिंग,
महात्मा गांधी रोड,
एर्नाकुलम
कोचीन-682011
निर्यात निरीक्षण परिषद्,
म्युनिसिपल मार्केट बिल्डिंग,
5वीं मंजिल, 3, सरस्वती मार्ग,
करोल बाग, नयी दिल्ली-110005

(2) निर्यातकर्ता अधिकरण को प्ररेषण पर लगाए गए पहचान चिन्ह भी देगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना और घोषणा विनिर्माता के परिसर के परेषण के भेजे जाने से कम से कम दस दिन पहले अभिकरण के कार्यालय में और निर्यात निरीक्षण परिषद् के पास पहुंच जाए।

(4) नियम (3) के अधीन सूचना और घोषणा प्राप्त होने पर,

(1) अधिकरण अपना यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान नियम 3 में उपबंधित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया गया है तथा इस संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा जारी किए गए कोई अनुदेशों का, यदि कोई हों, पालन किया गया है। अभिकरण की परेषण की मान्य विनिर्देश से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए इससे उपाबद्ध अनुसूची 2 के अनुसार नमूने लेकर ट्रांसफार्मरों का निरीक्षण करेगा तथा निर्यातकर्ता अभिकरण को ऐसा निरीक्षण करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देगा: उपलब्ध करेगा;

(2) जब अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान नियम 3 में उपबंधित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग नहीं किया गया है तो अभिकरण नियम 4 के उपखंड (ख) के उपबंधों के और मान्य विनिर्देश से परेषण की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को यदि कोई हों, के अनुसार निरीक्षण करेगा।

(5) निरीक्षण के पूरा होने के पश्चात्, अभिकरण ट्रांसफार्मरों की प्रत्येक रेटिंग प्लेट पर ट्रांसफार्मरों के परेषण संबंधी अनुमोदन को तत्काल पंच कर देगा। जब लकड़ी के बक्सों में पैक हो तब बक्सों को यह सुनिश्चित करने के लिए मोहरबंद किया जाएगा कि माल के साथ छेड़छाड़ न की जा सके। परेषण के अस्वीकार किए जाने की दशा में, यदि निर्यातकर्ता ऐसा चाहे तो परेषण अभिकरण द्वारा पंच या मोहर बंद नहीं किया जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों में निर्यातकर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा।

(6) जब अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि ट्रांसफार्मरों का परेषण मान्य विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो वह निरीक्षण के पूरा होने के पश्चात् तीन दिन के भीतर यह घोषित करते हुए निर्यातकर्ता को एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परेषण इस संबंध में क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण संबंधी शर्तों को पूरा करता है और निर्यात योग्य है:

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वहां वह उक्त तीन दिन की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने से इन्कार कर देगा तथा ऐसे इन्कार किए जाने की सूचना इसके कारणों सहित निर्यातकर्ता को देगा।

6. निरीक्षण का स्थान—इन नियमों के प्रयोजनों के लिए ट्रांसफार्मरों का निरीक्षण—

(क) विनिर्माता के परिसर पर किया जाएगा;

या

(ख) उस परिसर पर किया जाएगा जहां निर्यातकर्ता ट्रांसफार्मरों का परेषण निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करता है, परन्तु यह तब तक कि वहां निरीक्षण और परीक्षण के प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

7. निरीक्षण फीस :—

(1) यदि निरीक्षण नियम 4(क) के आधार पर किया जाता है तो फीस प्रत्येक परेषण के लिए न्यूनतम एक सौ रुपए के अधीन रहते हुए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.3% की दर से ली जाएगी;

(2) यदि निरीक्षण नियम 4(ख) के आधार पर किया जाता है तो फीस प्रत्येक परेषण के लिए न्यूनतम एक सौ रुपए के अधीन रहते हुए पोतपर्यन्त मूल्य के 0.5% की दर से ले ली जाएगी।

8. अपील—(1) नियम 5 के उपनियम (6) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने से इन्कार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इन्कार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्तियों के अपीलीय पैनल को अपील कर सकेगा।

(2) पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई सदस्य गैर-सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

अनुसूची-1

सारणी

नियंत्रण के स्तर

(नियम 3 देखिए)

क्र० सं०	निरीक्षण/परीक्षण की विशिष्टियां	अपेक्षाएं	नमूने का आकार	लॉट आकार
1	2	3	4	5
I	खरीदी गई सामग्री और संघटक			
	(क) चाक्षुष निरीक्षण (कारीगरी तथा फिनिश सहित)	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त प्रत्येक मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्राप्त किया प्रत्येक परेषण	

1	2	3	4	5
	(ख) सहायता सहित विभाए	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशो के अनुसार	प्रत्येक	प्राप्त हुआ प्रत्येक परेषण
	(i) क्रांतिक			
	(ii) अन्य	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशो के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर निश्चित किया जाना है।	प्राप्त हुआ प्रत्येक परेषण
	(ग) कोई अन्य अपेक्षा	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशो के अनुसार	—यथोक्त—	प्राप्त हुआ प्रत्येक परेषण
II	पूर्ण समुच्चय			
	(क) कुण्डलन प्रतिरोधक के माप	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशो के अनुसार।	प्रत्येक	—
	(ख) अनुपात, ध्रुवीयता तथा फज सबध	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशो के अनुसार।	प्रत्येक	—
	(ग) प्रतिबाधा वोल्टता	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशो के अनुसार।	प्रत्येक	—
	(घ) लोड हानि	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशो के अनुसार।	प्रत्येक	—
	(ङ) शून्य लोड हानि तथा शून्य लोड धारा	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशो के अनुसार।	प्रत्येक	—
	(च) विद्युत रोधन प्रतिरोध	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशो के अनुसार	प्रत्येक	—
	(छ) अति वोल्टता प्रेरित करने पर परीक्षण सहायता।	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशो के अनुसार।	प्रत्येक	—
	(ज) अलग स्रोत से आने वाली वोल्टता की परीक्षण सहायता	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशो के अनुसार।	प्रत्येक	—
	(झ) तापवृद्धि की जाच (ञ) आवेग वोल्टता की परीक्षण सहायता (ट) अन्य कोई परीक्षण	यदि उपभोक्ता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए	—	—

अनुसूची 2

अनुमोदित यूनिट की दशा में अनुरूपता का नमूना और मानदंड

[नियम 5(4)(1) देखिए]

सारणी 1

क्र०स०	विशिष्टियां	लॉट का आकार	परीक्षण किए जाने वाले नमूनो की सख्या
1	2	3	4
1	चाक्षुण जाच (बाहरीय)	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	100 प्रतिशत
2	कुण्डलन प्रतिरोधक के माप	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	न्यूनतम सं० 1 तथा अधिकतम सं० 3 के अधीन लॉट का 10 प्रतिशत।
3	अनुपात ध्रुवीयता तथा फेज सबध	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	न्यूनतम सं० 1 तथा अधिकतम सं० 3 के अधीन लॉट का 10 प्रतिशत।
4.	प्रतिबाधा वोल्टता	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	न्यूनतम सं० 1 तथा अधिकतम म० 3 के अधीन लॉट का 10 प्रतिशत।
5.	लोड हानि	उसी अकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	न्यूनतम स० 1 तथा अधिकतम स० 3 के अधीन लॉट का 10 प्रतिशत।

1	2	3	4
6	लोड हानि तथा शून्य लोड धारा	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	न्यूनतम संख्या 1 तथा अधिकतम सं० 3 के अधीन लॉट का 10 प्रतिशत।
7	विद्युत रोधन प्रतिरोध	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	न्यूनतम संख्या 1 तथा अधिकतम सं० 3 के अधीन लॉट का 10 प्रतिशत।
8	अति वोल्टता प्रेरित करने पर परीक्षण सह्यता	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	न्यूनतम सं० 1 तथा अधिकतम सं० 3 के अधीन लॉट का 10 प्रतिशत।
9	अलग स्रोत से आने वाली वोल्टता की परीक्षण सह्यता	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	न्यूनतम सं० 1 तथा अधिकतम सं० 3 के अधीन लॉट का 10 प्रतिशत।
10	ताप वृद्धि परीक्षण	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	सं० 1
11	आवेग वोल्टता की परीक्षण सह्यता	जैसा उपभोक्ता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए	
12	अन्य कोई परीक्षण		

अनुसूची 2

परेषण के अनुसार निरीक्षण की दशा में अनुरूपता का नमूना तथा मानदंड

[नियम 5(4)(2) देखिए]

सारणी 2

क्र०सं०	गुणधर्म	लॉट आकार	जांच किए जाने वाले नमूनों की सं०
1	चाक्षुण जांच (बाह्य)	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	100 प्रतिशत
2	कुण्डलन प्रतिरोधक के माप	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	नमूना सारणी III के अनुसार
3	अनुपात, ध्रुवीयता तथा फेज	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	नमूना सारणी III के अनुसार
4	प्रतिबाधा वोल्टता	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	नमूना सारणी III के अनुसार
5	लोड हानि	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	नमूना सारणी III के अनुसार
6	शून्य लोड के समय हानि तथा शून्य लोड के समय धारा	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	नमूना सारणी III के अनुसार
7	विद्युत रोधन प्रतिरोध	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	नमूना सारणी III के अनुसार
8	अतिवोल्टता प्रेरित करने पर परीक्षण सह्यता	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	नमूना सारणी III के अनुसार
9	अलग स्रोत से आने वाली वोल्टता का परीक्षण सह्यता	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	नमूना सारणी III के अनुसार
10	तापवृद्धि परीक्षण	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	
11	आवेग वोल्टता की परीक्षण सह्यता (यदि उपभोक्ता द्वारा अपेक्षा की जाए)	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मर	नमूना सारणी III के अनुसार यदि उपभोक्ता द्वारा विनिर्दिष्ट हो।

सारणी 3

क्र०सं०	उसी आकार तथा रेटिंग के ट्रांसफार्मरों की सं०	परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की सं०	अनुज्ञेय दोष की सं०
1	8 तक	2	कुछ नहीं
2	9 से 15	3	कुछ नहीं
3	16 से 25	5	कुछ नहीं
4	26 और अधिक	8	कुछ नहीं

[सं० 6(6)/80-नि०नि० तथा नि०उ०]
सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 29th November, 1980

S.O. 3347.—Whereas the Central Government is of opinion, that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient so to do for the development of the Export trade of India that the Transformers should be subject to inspection prior to export ;

And whereas the Central Government has formulated the proposal specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce S.O. 2274 dated the 9th July, 1977, the Central Government hereby publishes the said proposal for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within forty five days of the date of publication of this notification to the Export Inspection Council, "World Trade Centre, 14/1B, Ezra Street, Calcutta-700001.

PROPOSALS

(1) To notify that Transformers shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) To specify the type of inspection in accordance with the draft Export of Transformers (Quality Control and Inspection) Rules, 1980 set out in Annexure—I to this order as the type of quality control and inspection which would be applied to such Transformers prior to export ;

(3) To recognise —

(a) Contractual specifications from the importer or importer's Agents or Sub-Contractors, stipulating definite operating characteristics and/or definite mechanical construction, and wherever necessary, stipulating particular applications having definite service conditions, provided that missing para-meters, if any, in the contractual specifications, shall comply with (b) or (c) or (d) or (e) below ;

or

(b) Indian or any other national standard specification,

or

(c) International electrotechnical commission recommendations,

or

(d) Specifications approved by a Government department or Public Utility Services of any country,

or

(e) Specifications followed by technical collaborators of any unit,

as the standard specification.

(4) To prohibit the export in the course of international trade of any such Transformers unless the same are accompained by a certificate issued by any one of the agencies established by the Central Government under section 7 of the export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the consignments of transformers satisfy the conditions relating to quality control and inspection and are exportworthy.

3. In this Order 'Transformers' shall mean a piece of apparatus without continuously moving parts, which by electromagnetic Induction transforms alternating voltage and current in one winding into alternating voltage & current in one or more winding usually at different values of voltage and current and at the same frequency. This will not include transformers used for Domestic purpose and in radio-telecommunication circuits

ANNEXURE I

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

1 Short title and commencement—These rules may be called the Export of Transformers (Quality Control and Inspection) Rules, 1980

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) "agency" means any one of the agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act.

(c) 'Transformers' shall mean a piece of apparatus, without continuously moving parts, which by electromagnetic induction transforms alternating voltage and current in one vinding into alternating voltage and current in one or more windings usually at different values of voltage and current and at the same frequency. This will not include transformers used for Domestic purposes and radio-telecommunication circuits.

3. Quality Control and Inspection.—(1) The quality of transformers shall be ensured by the manufacturer by exercising the controls at different stages of manufacture specified in sub-rule (2), together with the levels of controls specified in Table annexed to Schedule-I to these rules.

(2) The controls at different stages of manufacture mentioned in sub-rule (1) are as follows :—

(i) Bought out materials and components control :

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used and the detailed dimensions thereof with tolerances.

(b) Supplier's test certificates shall be produced for raw materials like core sheets, winding wires, transformers oil, and press board and for components like Bushings, oil T.C. Pumps, Fans, Radiators, Instruments or Relays When Supplier's certificates are obtained for raw materials or components, no counter checking of the supplier's test reports shall be required. In the absence of Supplier's test reports, samples from each consignment shall be regularly tested to check up its conformity to the purchase specifications.

(c) The incoming components other than those mentioned in clause (b) shall be inspected and tested for ensuring conformity to purchase specifications against statistical sampling plan.

(d) After the inspection or tests or both are carried out, systematic methods shall be adopted for proper segregation and disposal of defectives.

(e) Adequate records in respect of the above mentioned controls shall systematically maintained by the manufacturer.

(ii) Process Control :

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturer for various process of manufacture.

(b) Equipment or instrumentation facilities shall be adequate to control the process as laid down in the process specifications.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacturer to enable the verification of the controls, exercised during the process of manufacture.

(iii) Product Control :

(a) The manufacturer shall either have his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the standard specifications. Adequate records thereof shall be maintained by the manufacturer.

(b) Each and every assembly shall be checked against a laid down inspection check list prior to despatch.

(iv) Metrological Control :

Electrical measuring instruments used in testing, and critical instruments used for process controls shall be periodically checked or calibrated and records shall be maintained by the manufacturer in the form of history cards.

(3) Inspection :

The inspection of Transformers meant for export shall be done by drawing samples as per Schedule II and Schedule III annexed hereto from the consignment for carrying out examination and testing of the same with a view to see that the consignment conforms to the standard specification recognised by the Central Government under section 6 of the Act.

4. Basis of inspection.—Inspection of Transformers intended for export shall be carried out with a view to seeing that the same conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act,

either

(a) by ensuring that during the process of manufacture the quality control drills as specified in sub-rule (1) of rule 3 have been exercised ;

or

(b) on the basis of inspection carried out in accordance with sub-rule (2) of rule 3;

(c) by both.

5. Procedure of Inspection.—(1) The exporter intending to export consignments of Transformers shall give intimation in writing to the agency indicating the details of the contractual specification and submit along with such intimation a declaration that the consignment of Transformers intended for export has been manufactured by exercising the quality controls as laid down in rule 3, and that the consignment conforms to the requirements of the specification recognised for this purpose. The exporter shall at the same time endorse a copy of such intimation to the nearest office of the Export Inspection Council. The addresses of the Council offices are as under :—

Head Office :

Export Inspection Council
'World Trade Centre,
14/1B, Ezra Street, 7th floor,
Calcutta-700 001.

Regional Offices :

Export Inspection Council
'Aman Chambers' 4th floor,
113, M. Karve Road,
Bombay-400 004.

Export Inspection Council
Manohar Building,
Mahatma Gandhi Road,
Ernakulam,
Cochin-682011.

Export Inspection Council.
Municipal Market Building, 4th floor,
3, Saraswati Marg,
Karol Bagh,
New Delhi-110005.

(2) The exporter shall also furnish to the agency the identification marks applied on the consignment.

(3) Every intemation and declaration under sub-rule (1) shall reach the office of the agency and the Export Inspection Counted not less than ten days prior to the despatch of the C nsı. ment ir m the premises of the manufacturer.

(4) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule 3 :—

(i) the agency on satisfying itself that during the process of manufacture adequate quality control as provided in rule 3 have been exercised and the instructions, if any issued by the Export inspection Council in his regard have been observed, shall carry out the inspection of Transformers by drawing samples as per Schedule II annexed hereto to ensure conformity of the consignment to the [illegible] specification and the exporter shall provide all necessary facilities to the agency to enable it to carry out such inspection ;

(ii) when the agency is satisfied that during the process of manufacture adequate quality controls as provided in rule 3 have not been exercised the agency shall carry out the inspection according to the provisions in sub-clause (b) of rule 4 and instructions, if any, issued by the Export Inspection Council in this regard to ensure conformity of the consignment to the recognised specification.

(5) After completion of inspection, the agency shall immediately punch their approval of the consignment of Transformers on each rating plate of the Transformers. When packed in wooden cases, the cases may be sealed so as to ensure that the goods cannot be tampered with. In case of rejection of a consignment, if the exporter so desired, the consignment may not be punched or sealed by the agency. In such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

(6) When the agency is satisfied that the consignment of Transformers complies with the requirements of the recognised specifications, it shall issue within three days after the completion of inspection, a certificate to the exporter declaring that the consignment satisfied the conditions relating to the quality control and inspection in this regard and is exportworthy.

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of three days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

6. Place of Inspection.—Inspection of Transformers for the purposes of these rules shall be carried out —

(a) at the premises of the manufacturer,

or

(b) at the premises at which the consignment of Transformers is offered for inspection by the exporter, provided adequate facilities for the purpose of inspection and testing exist therein.

7. Inspection Fee :—

(i) 0.3 per cent on F.O.B. value subject to a minimum of rupees one hundred for each consignment, in case the inspection is carried out on the basis given in rule 4(a);

(ii) 0.5 per cent of F.O.B. value subject to a minimum of rupees one hundred for each consignment, in case the inspection is carried out on the basis of rule 4(b).

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (6) of rule 5, may, within ten days of the receipt of the communication

of such refusal, prefer an appeal to an Appellate Panel consisting o not less than three but not more then seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two thirds of the total membership of the panel shall consist of non-officials.

(3) The quorum for the panel shall three.

(4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

SCHEDULE I

THE TABLE

LEVELS OF CONTROL

(See rule 3)

Sl. No.	Particulars of inspection/test	Requirements	Sample size	Lot size
1	2	3	4	5
I.	Bought out materials and components :	As per Standard Specification recognised for the purpose.	Each	Each consignment received
(a)	Visual Inspection (including workmanship and finish).			
(b)	Dimensions with tolerance	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	Each consignment received
	(i) Critical			
	(ii) Others	As per standard specification recognised for the purpose.	To be fixed on the basis of a standard AQL.	Each consignment received
(c)	Any other requirements	As per standard specification recognised for the purpose.	—do—	Each consignment received
II.	Complete Assembly :			
(a)	Measurements of winding resistance	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	—
(b)	Ratio, Polarity and phase relationship	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	—
(c)	Impedance Voltage	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	—
(d)	Load Losses	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	—
(e)	No load losses and no load current.	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	—
(f)	Insulation resistance	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	—
(g)	Induced over voltage withstand test	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	—
(h)	Separate source voltage withstand test	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	—
(j)	Temperature rise test	If specified by the customer.	—	—
(k)	Impulse voltage withstand test			
(m)	Any other test			

SCHEDULE II

Sampling and criteria of conformity in case of an approved unit

(See rule 5(4) (i))

TABLE I

S. No.	Characteristics	Lot size	No. of samples to be tested
1	2	3	4
1.	Visual check (External).	Transformers of same type and rating.	100%
2.	Measurement of winding resistance.	Transformers of same type and rating.	10% of the lot subject to a minimum of 1 no. and maximum of 3 nos.

1	2	3	4
3.	Ratio, Polarity and phase relationship.	Transformers of same type and rating	10% of the lot subject to a minimum of 1 no. and maximum of 3 nos
4	Impedance voltage	Transformers of same type and rating	10% of the lot subject to a minimum of 1 no and maximum of 3 nos
5	Load Losses	Transformers of same type and rating	10% of the lot subject to a minimum of 1 no and maximum of 3 nos.
6	No-load losses and no-load current	Transformers of same type and rating.	10% of the lot subject to a minimum of 1 no. and maximum of 3 nos.
7.	Insulation resistance	Transformers of same type and rating.	10% of the lot subject to a minimum of 1 no. and maximum of 3 nos.
8.	Induced over voltage	Transformers of same type and rating.	10% of the lot subject to a minimum of 1 no. and maximum of 3 nos.
9.	Separate sources voltage withstand test	Transformers of same type and rating.	10% of the lot subject to a minimum of 1 no. and maximum of 3 nos
10.	Temperature rise test	Transformers of same type and rating.	1 No.
11.	Impulse voltage test	As specified by the customer.	
12.	Any other test		

SCHEDULE III

Sampling and criteria of conformity in case of consignmentwise inspection

[See rule 5 (4) (ii)]

TABLE II

S. No.	Characteristics	Lost size		No. of samples to be tested.
1	2	3	4	5
1.	Visual Check (External).	Transformers of same type and rating.		100%
2.	Measurements of winding resistance.	Transformers of same type and rating.		As per the Sampling Table III.
3.	Ratio, Polarity and phase relationship.	Transformers of same type and rating.		As per the Sampling Table III.
4.	Impedance Voltage.	Transformers of same type and rating.		As per the Sampling Table III
5.	Load Losses.	Transformers of same type and rating.		As per the Sampling Table III.
6.	No-load losses and no-load current.	Transformers of same type and rating.		As per the Sampling Table III.
7.	Insulation resistance.	Transformers of same type and rating.		As per the Sampling Table III.
8.	Induced over voltage withstand test.	Transformers of same type and rating.		As per the Sampling Table III.
9.	Separate source voltage withstand test.	Transformers of same type and rating.		As per the Sampling Table III.
10.	Temperature rise test.	Transformers of same type and rating.		1
11.	Impulse voltage withstand test. (If required by the customer).	Transformers of same type and rating.		If specified by the customer. As per sampling Table III.

TABLE III

S. No.	No. of Transformers of same type and rating	No. of samples to be tested	No. of permissible defective
1	2	3	4
1.	Upto 8	2	Nil
2.	9 to 15	3	Nil
3.	16 to 25	5	Nil
4.	26 & above.	8	Nil

[No. 6(6)/80 EL&EP]

C. B. KUKRETI, Jo Director

(मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1980

का०आ० 3348.—सर्वश्री भारत फ्रिटज वर्नर (प्रा०) लि० बंगलौर को पूंजीगत माल के लिए डी एम 35 मिलियन पश्चिम जर्मनी क्रेडिट के अन्तर्गत एक नग इन्टरनल ग्राइंडिंग मशीन के आयात के लिए 14,757,32 रुपये (चौदह लाख, पिचहत्तर हजार, सात सौ बत्तीस रुपए मात्र) का एक आयात लाइसेंस सं० पी०/सी०जी०/2030426/एस/जी/एन/74/एच/79/सी०जी० 1 दिनांक 5-3-80 प्रदान किया गया था। बाद में आयात लाइसेंस का मूल्य बढ़ा कर 14,82,693 रुपए कर दिया गया था। फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस को मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई अथवा अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह बताया गया है कि लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाई गई है। और इसकी सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाई गई थी और इसलिए सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक दिल्ली के सम्मुख स्टाम्प कागज पर विधिवत शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि फर्म द्वारा आयात लाइसेंस सं० पी/सी जी/2030426 दिनांक 5-3-80 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 के उप धारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री भारत फ्रिटज वर्नर (प्रा०) लि० बंगलौर को जारी की गई उक्त मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति सं० पी/सी जी/2030426 दिनांक 5-3-80 एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. पार्टी का उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं० 1386/79/9/ सी०जी०1]

जी०एस० ग्रेवाल, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 13th November, 1980

S.O. 3348.—M/s. Bharat Fritz Werner (P) Ltd., Bangalore were granted an import licence No. P|CG|2030426|S|GN|74|H|79|CG.I dated 5-3-80 for Rs. 14,75,732 (Rupees Fourteen Lakh, Seventyfive thousand, seven hundred and thirtytwo only) for import of One No. Internal Grinding Machine under DM. 35 Million West German Credit for Capital Goods Subsequently rupee value of the Import Licence was enhanced to Rs. 14,82,693. The firm has applied for issue of a Duplicate copy of Exchange Control purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original Exchange control purpose copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Exchange control purposes copy of the licence has not been utilised at all and that its Customs purpose copy was not registered with any Customs authority and as such the value of Customs purpose copy has not been utilised at all.

2. In support of their contention, the licencee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public Delhi. I am accordingly satisfied that the original Exchange control purpose copy of import licence No. P/CG/2030426 dated 5-3-80 has been lost/or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9 (cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Exchange control purposes copy No. P/CG/2030426 dated 5-3-80 issued to M/s. Bharat Fritz Werner (P) Ltd., Bangalore is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control purpose copy of the said licence is being issued to the party separately.

[No. 1386/79/9/CG.I]

G. S. GREWAL,

Dy. Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1980

का०आ० 3349.—उत्प्रवासन अधिनियम, 1922 (1922 का 7) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सहायक पासपोर्ट अधिकारी श्री बी० साहा के अवकाश लेने पर, उनके स्थान पर जन सम्पर्क अधिकारी श्री के०एल० शर्मा को 3-10-79 से 21-11-80 तक उनके अपने कार्य के अतिरिक्त पासपोर्ट एवं उत्प्रवासन कार्यालय, जालन्धर में उत्प्रवासी संरक्षक नियुक्त करती है।

[सं० सी पी ई ओ/10/80]

एस०एस० भटनागर, विशेषाधिकारी (पी वी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 30th October, 1980

S.O. 3349.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Emigration Act, 1922 (VII of 1922), the Central Government hereby appoint Shri K. L. Sharma, Public Relations Officer as Protector of Emigrants in the Passport and Emigration Office, Jullundur, in addition to his own duties, from 3-10-79 to 21-11-80 vice Shri B. Saha, Assistant Passport Officer proceeded on leave.

[No. CPEO/10/80]

S. S. BHATNAGAR, Officer on Special Duty (PV)

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1980

का०आ० 3350.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1322 तारीख 16-4-80 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है

कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

डबका-14 से जी०सी०एस० तक पाइप लाइन बिछाने के लिये ।

राज्य : गुजरात जिला बड़ोदरा तालुका . पादरा

गांव	सर्वे सं०	हेक्टेयर	एआर	सेन्टीयर
गामेठा	497/2	0	07	15
	500	0	03	90
	503	0	19	89
	502	0	00	65
	517	0	15	86
	516	0	06	50
	513	0	06	76
	514/1	0	03	90
	514/2	0	04	29
	557	0	11	05
	556	0	03	90
	553	0	08	45
	42/1	0	05	20
	43/1	0	13	39
	44/1	0	06	50
	70	0	05	20
	69/2	0	06	50
	86/1	0	03	90
	86/2	0	01	30
	87	0	05	85
	88	0	01	30
	89	0	00	65
	93	0	14	56

[सं० 12016/14/80-प्रो०-1]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZER

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 10th November, 1980

S.O. 3350.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1322 dated 16-4-80 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Dabka—14 to GCS

State : Gujarat District : Baroda Taluka : Padra

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Gametha	497/2	0	07	15
	500	0	03	90
	503	0	19	89
	502	0	00	65
	517	0	15	86
	516	0	06	50
	513	0	06	76
	514/1	0	03	90
	514/2	0	04	19
	557	0	11	05
	556	0	03	90
	553	0	08	45
	42/1	0	05	20
	43/1	0	13	39
	44/1	0	06	50
	70	0	05	20
	69/2	0	06	50
	86/1	0	03	90
	86/2	0	01	30
	87	0	05	85
	88	0	01	30
	89	0	00	65
	93	0	14	56

[No. 12016/14/80-Prod. I]

का०आ० 3351.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ०सं० 1314 तारीख 16-4-80 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग

का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० डबका-14 से जी सी एस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा तालुका : पादरा

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सेंटीयर
गेवासद	153	0	07	80
	154	0	07	15
	155	0	09	75
	158	0	09	10
	159	0	11	70
	162	0	02	60
	161	0	03	90
	163	0	09	49
	165	0	07	80
	166/1	0	07	80
	140	0	03	64
	124	0	10	40
	123	0	01	04
	122	0	06	50
	126	0	08	45
	113/2	0	02	60
	113/1	0	07	80

[सं० 12016/14/80 प्रो० II]

S.O. 3351.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1314 dated 16-4-80 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from Dabka—14 to GCS

State : Gujarat District : Baroda Taluka : Padra

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Gawasad	153	0	07	80
	154	0	07	15
	155	0	09	75
	158	0	09	10
	159	0	11	70
	162	0	02	60
	161	0	03	90
	163	0	09	49
	165	0	07	80
	166/1	0	07	80
	140	0	03	64
	124	0	10	40
	123	0	01	04
	122	0	06	50
	126	0	08	45
	113/2	0	02	60
	113/1	0	07	80

[No. 12016/14/80-Prod. II]

का०आ० 3352—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एन०के० बी० ओ० से जी०जी० एस० कम सी०टी०एफ० कडी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप न० एन०के०बी०ओ० से जी०जी०एस० कम सी०टी०एफ० कडी

राज्य—गुजरात जिला—अहमदाबाद तालुका—विरमगाम

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए आर ई०	सेंटीयर
बालसासण	169	0	09	00
	175	0	09	48
	174/112	0	13	56
	176/3	0	07	00
	176/5	0	01	50
	176/7	0	06	84
	176/4	0	06	00

[सं० 12016/61/80—प्रो०]

S.O. 3352.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKBO to GGS Cum CTF kodi in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara—390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. from Well No. NKBO to GCS-Cum-CTF Kadi

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Balsasan	169	0	09	00
	175	0	09	48
	174/12	0	13	56
	176/3	0	07	00
	176/5	0	01	50
	176/7	0	06	84
	176/4	0	06	00

[No 12016/61/80-Prod.]

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1980

का०आ० 3353,—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 972 तारीख 2-3-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० एम०टी०बी० से मोटवान तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका—अंकलेश्वर

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए आर ई०	सेंटीयर
मोटवान	217	0	04	55
	218	0	11	05
	219	0	30	55
	212	0	21	84
	211	0	44	85
	210	0	01	95
	207	0	01	95
	208	0	13	00
	37	0	10	40
	38	0	24	44
	145	0	16	90
	144	0	14	36
	35	0	03	90
	48	0	09	10
	49	0	08	45
	50/ए	0	05	20
	50/बी	0	07	15
	56	0	23	40
	113	0	11	70
	109	0	13	65
	116	0	01	82
	117	0	01	82
	357	0	09	75
	104	0	11	70
	103/ए	0	08	84
	103/बी	0	06	50

[सं० 12016/14/79-प्रो०]

New Delhi, the 12th November, 1980

S.O. 3353.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 972 dated 2-3-79 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

ROU for Well No. MTB to Motwan-1

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Motwan	217	0	04	55
	218	0	11	05
	219	0	30	55
	212	0	21	84
	211	0	44	85
	210	0	01	95
	207	0	01	95
	208	0	13	00
	37	0	10	40
	38	0	24	44
	145	0	16	90
	144	0	14	36
	35	0	03	90
	48	0	09	10
	49	0	08	45
	50/A	0	05	20
	50/B	0	07	15
	56	0	23	40
	113	0	11	70
	109	0	13	65
	116	0	01	82
	117	0	01	82
	357	0	09	75
	104	0	11	70
	103/A	0	08	84
	103/B	0	06	50

[No. 12016/14/79-Prod.]

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1980

का०आ० 3354.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 1326 तारीख 25-4-80 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

नार्थ कडी जी०जी०एस० 1 से नार्थ कडी सी० टी० एफ० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—अहमदाबाद तालुका—विरमगाम

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सेंटीयर
भटारीया	58/3	0	02	85
	58/2	0	04	50
	58/1	0	08	25
	72/3	0	09	30
बालसासण	215	0	02	25

[सं० 12016/2/80-प्रो०]

New Delhi, the 13th November, 1980

S.O. 3354.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1326 dated 23-4-80 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

ROU from North Kadi GGS-I to North Kadi CTF

State : Gujarat District - Ahmedabad Taluka : Viramgam

Villages	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Bhataria	58/3	0	02	85
	58/2	0	04	50
	58/1	0	08	25
	72/3	0	09	30
Balsasan	215	0	02	25

[No. 12016/2/80-Prod.]

का०आ० 3355.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 1310 तारीख 14-4-80 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० डी०बी०एन० (डबका–14) से गवासद जी०सी० एस० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—जंबुसर

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सेंटीयर
कामवा	789	0	02	34
	781	0	09	10
	782	0	11	05
	752	0	12	00
	749	0	09	75
	744	0	16	25
	745	0	16	25
	741	0	23	40
	695	0	13	00
	700	0	08	45
	701	0	09	75
	696	0	07	80
	691	0	07	80
	690	0	03	77
	677	0	04	16
	670	0	16	90

[सं० 12016/21/80–प्रो०]

S.O. 3355.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1310 dated 14-4-80 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appendd to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

R.O.U. for laying Pipeline from well No. DBN (Dabka-14) to Gavasad GCS

State : Gujarat District : Broach Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Kanva	789	0	02	34
	781	0	09	10
	782	0	11	05
	752	0	12	00
	749	0	09	75
	744	0	16	25
	745	0	16	25
	741	0	23	40
	695	0	13	00
	700	0	08	45
	701	0	09	75
	696	0	07	80
	691	0	07	80
	690	0	03	77
	677	0	04	16
	670	0	16	90

[No. 12016/21/80-Prod.]

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1980

का० आ० 3356.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1316 तारीख 19-9-80 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० एम०टी०डी० से एस०एन०के०-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुक—हांसोट

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सेन्टी-यर
रोहिव	501	00	05	85

[सं० 12016/3/80–प्रो०]

New Delhi, the 14th November, 1980

S.O. 3356.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1316 dated 19-4-80 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline:

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

ROU from Well No. MTD to SNK-1

State : Gujarat District : Broach Taluka : Hansot

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Rohid	501	0	05	85

[No. 12016/3/80-Prod. I]

का० आ० 3357—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 1375 तारीख 26-4-80 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० डब्लू०एम०बी० से कूप नं० 30 तक फ्लो लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—हांसोट

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एआर ई	सेन्टीयर
कलम	201	0	18	20
	205	0	15	60
	206	0	10	40
	215	0	26	00
	227	0	26	00
	228	0	31	200
	272	0	14	30
	270	0	11	70
	269	0	10	40
	268	0	06	50
	267	0	14	30

[सं० 12016/6/80-प्रो० I]

S.O. 3357.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1375 dated 26-4-80 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

R.O.U. for flow line from Well No. WMB to Well No. 30

State : Gujarat District : Broach Taluka : Hansot

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kalam	201	0	18	20
	205	0	15	60
	206	0	10	40
	215	0	26	00
	227	0	26	00
	228	0	31	20
	272	0	14	30
	270	0	11	70
	269	0	10	40
	268	0	06	50
	267	0	14	30

[No. 12016/6/80-Prod. I]

का० आ० 3388.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1378, तारीख 24-4-80 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सहकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० डब्लू० एम० ए० से एम० एन०के०-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—अंकलेश्वर

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	एआर ई	सेन्टीयर
मोटवान	215	0	04	55

[सं० 12016/6/80-प्रो० II]

S.O. 3358.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1378 dated 24-4-80 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by subsection (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

ROU from Well No. WMA to SNK-1

State : Gujarat District : Broach Taluka : Ankleshvar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Motwan	215	0	04	55

[No. 12016/6/80-Prod. II]

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1980

का० आ० 3359—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 1377, तारीख 24-4-80 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० एस० डी० के० से एम० डी० एफ० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—मेहसाणा तालुका—मेहसाणा

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	एआर ई	सेन्टीयर
हेबुवा	87	0	03	00
	83	0	04	20
	82	0	00	50
	84/ए	0	05	75
	81	0	04	80
	77	0	05	75
	कार्ट ट्रैक	0	00	60
	228	0	03	42
	227	0	03	42
	236	0	08	40
	237	0	03	00
	238	0	07	40
	234	0	00	50
	233	0	07	80
	241	0	03	12

[सं० 12016/7/80-प्रो०]

New Delhi, the 15th November, 1980

S.O. 3359.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1377 dated 24-4-80 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

ROU for SDK to SDF

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Hebova	87	0	03	00
	83	0	04	20
	82	0	00	50
	84/A	0	05	75
	81	0	04	80
	77	0	05	75
	Cart track	0	00	60
	228	0	03	42
	227	0	03	42
	236	0	08	40
	237	0	03	00
	238	0	07	40
	234	0	00	50
	233	0	07	80
	241	0	03	12

[No. 12016/7/80-Prod.]

का० आ० 3360.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1317 तारीख 21 अप्रैल, 1980 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० कानावाडा 2 से चांगडा-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—खेडा तालुका—खम्बात

गांव	सर्वे नं०	हैक्टेयर	एआर्ड	सेन्टीयर
कानावाडा	79	0	12	35
	98	0	04	07
	94	0	14	02
	95/2	0	11	70

[सं० 12016/5/80-प्रो०-I]

S.O. 3360.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1317 dated 24-4-80 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

R.O.U. for laying pipeline from Kanawada-2 to Changada-1.

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Cambay

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kanawada	79	0	12	35
	98	0	04	07
	94	0	14	02
	95/2	0	11	70

[No. 12016/5/80-Prod. I]

का० आ० 3361—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1318 तारीख 24 अप्रैल, 1980 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, उस अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कानावाडा-2, से चांगडा-1, तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : खेडा तालुका : खंम्भात

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एआई ई	सेन्टी-यर
चांगडा	34/35/44	0	07	28
	43	0	09	10
	41	0	09	10
	40	0	06	50
	37	0	04	81
	38	0	14	43
	सी-ट्री	0	00	65
	631/1 और 2	0	03	90
	632	0	42	90
	633	0	11	70
	612	0	11	44
	611	0	17	94
	सी-टी	0	00	78
	652/1	0	07	41
	652/2	0	03	90

[सं० 12016/5/80-प्रो०-II]

किरन चड्ढा, अवर सचिव

S.O. 3361.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1318 dated 24-4-80 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

For laying pipeline from Kanawada-2 to Changada-1

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Cambay

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Changada	34/35/44	0	07	28
	43	0	09	10
	41	0	09	10
	40	0	06	50
	37	0	04	81
	38	0	14	43
	Cart-track	0	00	65
	631/1 & 2	0	03	90
	632	0	42	90
	633	0	11	70
	612	0	11	44
	611	0	17	94
	Cart-track	0	00	78
	652/1	0	07	41
	652/2	0	03	90

[No. 12016/5/80-Prod. II]

KIRAN CHADHA, Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1980

का० आ० 3362.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अधीन बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो (बिहार) को, जिसके कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है ।

[संख्या ई० 11011/2/80-हिन्दी]

एम० एम० हुसैन, अवर सचिव

MINISTRY OF STEEL & MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 22nd October, 1980

S. O. 3362 .—In pursuance of sub-rule (4) rule 10 of the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies Bokaro Steel Plant, Bokaro (Bihar) under the Steel Authority of India Ltd., the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. 11011/2/80-Hindi]

M. M. HUSSAIN, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1980

शुद्धीपत्र

का०आ० 3363--भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2), तारीख 8 अप्रैल, 1978 के पृष्ठ 1035 पर प्रकाशित भारत सरकार के कृषि और सिचाई मंत्रालय, कृषि विभाग, की अधिसूचना सं० का०आ० 1004 तारीख 23 मार्च, 1978 के स्तंभ 2, पंक्ति 26 में "रावी" के स्थान पर "रासी" पढ़े ।

[सं० 27012/2/8-एस डी]

एम० डी० अस्थाना, निदेशक (बीज)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th November, 1980

S.O. 3363 .—In the notification of the Government of India in the Minitry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture), No. S.O. 1004, dated the 23rd March, 1978, published in the Gazette of India, Part II-Section 3—Sub-Section (ii) dated the 8th April, 1978, at page 1035, in column—2, in line 26, for "Ravi" read "Rasi".

[No. 27012|2|80-SD]

M. D. ASTHANA, Director (Seeds)

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

कापी-राइट कार्यालय

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1980

का० आ० 3364.—केस संख्या 1980 का 36 —कापीराइट नियमावली, 1958 के नियम 7 के अनुसरण मे कापीराइट बोर्ड एतद्द्वारा "बेली एण्ड लव्ज शार्ट प्रैक्टिस आफ सर्जरी" नामक साहित्यिक कृति का मराठी अनुवाद प्रकाशित करने के लिए कापीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 32 के अन्तर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र की सूचना देता है ।

2 आवेदक पत्र के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(क) आवेदक पत्र की तारीख .	6 अगस्त, 1980
(ख) आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता	डा० रानाडे मधुकर, ए, 17 शंकर शेट रोड बम्बई,-400007 (भारतीय)
(ग) अनुदित की जाने वाली कृति के ब्यौरे	चिकित्सा विषय— श्री बेली और श्री लव कृत "शार्ट प्रैक्टिस आफ सर्जरी"
(घ) कृति के प्रथम प्रकाशन की तारीख और देश का नाम	1932--इंगलैण्ड (युनाइटेड किंगडम)
(ङ) कापीराइट रखने वाले का नाम, पता और राष्ट्रीयता जैसा कि आवेदन पत्र मे उल्लेख किया गया है।	मे० एच० के० लूयूइस एण्ड क० लिमि०, पो० बाक्स 66, 136, गावर स्ट्रीट, लदन, डब्ल्यू सी० आई० ई० 6 बी० एस० (ब्रिटिश)
(च) भाषा जिसमें अनुवाद किया जाना है ; और	मराठी
(छ) यदि कापीराइट रजिस्टर में पंजीकरण हो तो उसकी सख्या	

3. ऐसा कोई व्यक्ति जो उपर्युक्त कार्य में रुचि रखता हो और ऐसा लाइसेंस दिए जाने में उसे कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास भारत के राजपत्र में इस नोटिस के प्रकाशित होने की तारीख से एक सौ बीस दिन समाप्त होने से पहले प्रस्तुत कर सकता/सकती है ।

[सं० एफ० 26-1/80-का०का०]

कापीराइट बोर्ड के आदेश से,

(कु०) कला थैरानी,

सचिव, कापीराइट बोर्ड

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(Department of Education)

Copyright Office

PUBLIC NOTICE

COPYRIGHT

New Delhi, the 25th November, 1980

S.O. 3364 :—Case No. 36 of 1980. In pursuance of Rule 7 of the Copyright Rules, 1958, the Copyright Board hereby gives notice of an application for a licence under Section 32 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957) to produce and publish Marathi translation of the literary work, namely "Bailey & Love's Short Practice of Surgery".

2. The particulars of the application are given below :—

(a) The date of the application	6th August, 1980
(b) The name, address and nationality of the applicant	Dr. Ranade Madhukar A. 17, Shankar Shet Road, Bombay-400007. (Indian)
(c) Particulars of the work which is to be translated	Medical subject-"Short Practice of Surgery" by Mr. Bailey & Mr. Love.
(d) The date and country of the first publication of the work	1932 – England (United Kingdom)
(e) The name, address and nationality of the owner of the copyright as stated in the application	M/s. H.K. Lewis & Co. Ltd., P.O. Box 66, 136, Gower Street, London, WCIE6BS (British)

(f) The language in which the work is to be translated; and — Marathi

(g) The Registration Number of the work in the Register of Copyrights; if any.

3. Any person who claims any interest in the Copyright of the above work and who has any objection, to the grant of such licence may submit his/her objections in writing to the undersigned on or before the expiry of one hundred and twenty days from the date of publication of this notice in the Gazette of India.

[No.F. 26-1/80 C.O.]

By order of the Copyright Board

Miss, KALA THAIRANI Secy., Copyright Board.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1980

का० आ० 3365.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) नियम, 1973 के नियम 3 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के द्वारा श्री एस० मलयाचामी, परिवहन निदेशक, दिल्ली प्रशासन को दिल्ली परिवहन निगम का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० का० 238 (अ०), दिनांक 1 मई, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में मद (1) के सामने निम्नलिखित मद जोड़ी जाए :—

"श्री एम० मलयाचामी,
निदेशक (परिवहन),
दिल्ली प्रशासन।"

[फा० सं० टीजीडी (9)/79]

बी० आर० चव्हाण, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 18th November, 1980

S.O. 3365 .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950), read with rule 3 of the Delhi Transport Corporation (Members) Rules, 1973, the Central Government hereby appoints Shri S. Malaichamy, Director of Transport, Delhi Administration as a member of the Delhi Transport Corporation and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 238(E) dated the 1st May, 1979, namely :—

In the said notification in Para 1 against the item (vi), the following shall be inserted :

"Shri S. Malaichamy Director (Transport), Delhi Administration."

[File No. TGD(9)/79]

B. R. CHAVAN, Dy. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1980

का० आ० 3366.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की सं० 61) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा निदेश देता है कि दि० वि० प्रा० या भूतपूर्व दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा निष्पादित किए गए पट्टे या पट्टों के अनुबन्धों के सम्बन्ध में "पट्टादाता" के रूप में बिक्री या हस्तान्तरण हेतु अनुमति प्रदान करने की दिल्ली विकास प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग वि० वि० प्रा० के उपाध्यक्ष द्वारा भी किया जाए।

[संख्या एम-2(9)/80एम०सी०]

ह० अपठनीय
सचिव,
दि० वि० प्रा०

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 12th November, 1980

S.O. 3366 .—In exercse of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) the Delhi Development Authority hereby directs that its powers to grant permission for sale or transfer in its capacity as "Lessor" in respect of the agreement for Lease or Leases, executed by it or by the Erstwhile Delhi Improvement Trust, be also exercised by its Vice-Chairman.

[File No. M. 2(9)/80-M.C.]

Sd/- ILLEGIBLE

Secretary,
Delhi Development Authority.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1980

का० आ० 3367.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एल० ओ० 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबंध के अंतर्गत, जारी किए गए आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एतद्द्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपांतरों सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम० सं०	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई (मीटर में)	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामायिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1.	अराइवल	1795 फुट	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24-पैडर रोड, बम्बई।		डाकुमेंट्री फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)

[फा०सं० 808/7/80-एफ(सी)]

रत्न स्वरूप शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDER

New Delhi, the 11th November, 1980

S.O. 3367—In pursuance of the direction issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No S.O. 3/2 dated the 2nd December, 1965 the Central Government after considering recommendations of the Film Advisory Board Bombay hereby approves the film specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its language versions to be of the description specified against it in each column 6 of the said schedule.

SCHEDULE

Sl. No	Title of the film	Length of the film in ft.	Name of the applicant	Name of the Producer	Brief whether a synopsis scientific film or for educational purpose of a film dealing with news current events or documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Arrival	1795 ft	Films Division, Govt of India 24-Peddar Road, Bombay.		Documentary General Release

[File No 808/7/80-F(C)]

R S SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1980

का० आ० 3368—चलचित्र (सेन्सर) नियम, 1958 के नियम 10 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां) की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारी श्री के० जी० रामकृष्णन को 3-11-1980 के अपराह्न से अगले आदेश तक, प्रादेशिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड, मद्रास के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करती है। यह नियुक्ति श्री के० स्वामीनाथन जिनका स्थानान्तरण हो गया है, के स्थान पर की गई है।

[फा० संख्या 802/30/80- फ(सी)]

के० एस०, वेंकटरामन,

डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th November, 1980

S.O. 3368—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the C[illegible] Act 1952 (37 of 1952) read with rule 10 of [illegible] (Censorship) Rules 1958 the Central Government is pleased to appoint Shri K. G. Ramakrishnan, an officer of the Central Information Service to officiate as Regional Officer, Central Board of Film Censors, Madras with effect from 3rd November, 1980 A N until further orders vice Shri K Swaminathan transferred

[F No 802/30/80-FC]

K S VENKATARAMAN, Desk Officer

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1980

का० आ० 3369—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, पंजाब सरकार, पुनर्वास विभाग में बन्दोबस्त अधिकारी (बिक्री), श्री एस० मोहन सिंह को, पंजाब राज्य के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9(क) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए, बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या-1(17)/वि०सैल/80-एसएस०-II]

एन० एम० वाधवानी, अवर सचिव

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 5th November, 1980

S.O. 3369—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Displaced persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (No. 44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri S. Mohan Singh, Settlement Officer (Sales) in the Rehabilitation Department, Government of Punjab, as Settlement Officer for the purpose of performing the functions assigned to such Officer under Section 9(a) of the said Act in the State of Punjab

[No 1(17)/Spl. Cell/80-SS. II]

N M WADHWANI, Under Secy

बन्दोबस्त खण्ड

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1980

का० आ० 3370—पुनर्वास विभाग के बन्दोबस्त खण्ड के सहायक बन्दोबस्त अधिकारी श्री एम० सी० जैन को दिनांक 7-9-1979 को निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर निर्माण आवास, पूर्ति एवं पुनर्वास मंत्री के अतिरिक्त व्यक्तिगत सचिव पद पर की गई नियुक्ति पर उनको सेवा अवधि में दिनांक 13-2-1980 तक के लिए बढ़ोतरी प्रदान कर दी गई थी।

2 श्री एम० सी० जैन की सेवा अवधि में की गई वृद्धि के समय के समाप्त हो जाने पर, उन्हें दिनांक 13-2 1980 के दोपहर बाद से सेवा निवृत्त कर दिया गया था।

3 यह अधिसूचना इस विभाग की समसंख्या अधिसूचना दिनांक 23-10-1979 का अतिक्रमण करती है।

[संख्या 28(236)/आर०एस०सी०(सी) एडमिन/74/एस०डब्लू]

बी० सी० शर्मा, सचिव

(Settlement Wing)

New Delhi, the 18th November, 1980

S.O. 3370—Shri M C Jain, Asst Settlement Officer in the Settlement Wing of the Department of Rehabilitation who attained the age of superannuation on 7th September, 1979 was granted extension in service upto 13th February, 1980 on his appointment as Additional Private Secretary to the Minister of Works, Housing Supply and Rehabilitation

On the expiry of this period of extension in service Shri M C Jain retired from service on the after-noon of 13th February, 1980

3. This supersedes this Department's Notification of even No dated 23rd October, 1979.

[No. 28(236)/RSC(C)/Admn./74|SW]
B B. SHARMA, Dy. Secy

संचार विभाग

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1980

का० आ० 3371—जबकि भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 (iii) (ख ख) के अनुसार अमृतसर टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली में संशोधन करने के लिए अमृतसर में प्रचलित समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करवाई गई थी जिसमें प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से नोटिस के प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर आपत्तियां तथा सुझाव मांगे गये थे ;

और जबकि उक्त नोटिस को 5-12-1979 को चंडीगढ़ के "दी ट्रिब्यून" 5-12-1979 को जालन्धर के "दी अजीत" तथा 5-12-1979 जालन्धर के "पंजाब केसरी" तथा 2-8-1980 को चंडीगढ़ के "दी ट्रिब्यून", 2-8-1980 को जालन्धर के "दी अजीत" तथा 2-8-1980 को ही जालन्धर के "दी पंजाब केसरी" समाचार पत्रों में जनता के ध्यान में लाया गया था ।

और जबकि उपरोक्त नोटिस के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया गया ,

अतः अब उक्त नियमों के नियम 434 (iii) (ख ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक तार महा निदेशक, घोषणा करते हैं कि तारीख 16-10-80 से अमृतसर का संशोधित स्थानीय क्षेत्र निम्न प्रकार होगा :—

अमृतसर के स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत अमृतसर नगर-निगम की सीमा के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले इलाके अधिसूचना की तारीख को शामिल रहेंगे, बशर्ते कि अमृतसर नगर-निगम सीमा से बाहर के टेलीफोन उपभोक्ता, लेकिन अमृतसर टेलीफोन प्रणाली से लाभ उठाने वाले उपभोक्ता तब तक स्थानीय शुल्क देते रहेंगे जबकि वे इस टेलीफोन प्रणाली के किसी एक्सचेंज के 5 कि० मी० के दायरे में स्थित हैं तथा जुड़े हुए हैं ।

[सं० 3-3/79-पी० एच० बी०]
एम० बी० रामामूर्ति, निदेशक फोन्स (ई)

DEPARTMENT OF COMMUNICATION

(P & T BOARD)

New Delhi, the 18th November, 1980

S.O. 3371 .—Whereas a public notice for revising the local area of Amritsar Telephone Exchange System was published as required by rule 434(III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Amritsar, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers ;

And whereas the said notice was made available to the public on 5th December, 1979 in "The Tribune" Chandigarh, on 5th December, 1979 in "The Ajit" Jullundur and on 5th December, 1979 in "Punjab Kesari" Jullundur and on 2nd August, 1980 in "The Tribune" Chandigarh on 2nd August, 1980 in "The Ajit" Jullundur and on 2nd August, 1980 in "The Punjab Kesri" Jullundur

And where objections and suggestions received from the public on the said notice have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434(III)(bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 16th October, 1980 the revised local area of Amritsar shall be as under :—

Amritsar Telephone Exchange System.

The local area of Amritsar shall cover an area falling under the jurisdiction of Amritsar Municipal Corporation (As existing on the date of notification) provided that the telephone subscribers located outside Amritsar Municipal Corporation Limits but who are served from Amritsar Telephone Exchange System shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 KMs of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-3/79-PHB]
M. B. RAMAMURTHY, Director of Phones (E)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1980

का० आ० 3372.—रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1950 के नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पढ़े जाने वाले भारतीय रेलवे अधिनियम (1890 का 9) की धारा 82ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के रेल मंत्रालय के दिनांक 25-1-74 के सं० आ० स० 522 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उपर्युक्त अधिसूचना के साथ अनुबंधित अनुसूची में, तमिलनाडु राज्य से संबंधित क्रम संख्या 20 के सामने कालम सं० 2 में इन्दराजों के लिए, निम्नलिखित इन्दराजों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	उत्तरी अर्काट (वेल्लोर में मुख्यालय)
2.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	कोयम्बतूर नीलगिरी (कोयम्बतूर में मुख्यालय)
3	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	पेरियार जिला (ईरोड़ में मुख्यालय)
4	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	मदुरै (मदुरै में मुख्यालय)
5	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	तन्जाऊर (पूर्व) (नागापट्टनम् में मुख्यालय)
6	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	तन्जाऊर (पश्चिम) (तन्जाऊर में मुख्यालय)
7	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	रामनाथपुरम् (मदुरै में मुख्यालय)
8	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	धर्मापुरी (कृष्णागिरी में मुख्यालय)
9	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	तिरुनेलवेलि (तिरुनेलवेलि में मुख्यालय)
10.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	कन्याकुमारी (नागरकोइल में मुख्यालय)
11	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	सेलम (सेलम में मुख्यालय)
12	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	चिंगलपेट (चिंगलपेट में मुख्यालय)
13	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	तिरुचिरापल्ली (तिरुचिरापल्ली में मुख्यालय)

14	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	दक्षिण अर्काट (वुड्डलूर में मुख्यालय)
15	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	पुदुक्कोटै (पुदुक्कोटै में मुख्यालय)
16	मुख्य न्यायिक अधिकारी	कोयम्बतूर (कोयम्बतूर में मुख्यालय/ समुचा कोयम्बतूर और नीलगिरी राजस्व जिले)
17	प्रधान न्यायाधीश	सिटी सिविल कोर्ट मद्रास सिटी"

[सं० 70/टी०जी०II/1026/29/वाल्यूम-II]

के० बालचन्द्रन, सचिव, रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 4th November, 1980.

S.O. 3372.—In exercise of the powers conferred by Sec. 82 B of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), read with sub-rule (1) of rule 4 of the Railway Accidents (Compensation) Rules, 1950, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Railways, No. S.O 522, dt. the 25th Jan.'74 namely:—

In the Schedule annexed to the said notification, against serial No. 20 relating to the State of Tamil Nadu, for the entries in Col. 2, the following entries shall be substituted, namely :—

"1.	District and Sessions Judge,	North Arcot (H.Q. at Vellore).
2.	District and Sessions Judge,	Coimbatore & Nilgiris. (H.Q. at Coimbatore)
3.	District and Sessions Judge,	Periyar District (H.Q. at Erode)
4.	District and Sessions Judge,	Madurai (H.Q. at Madurai)
5.	District and Sessions Judge,	Thanjavur (East) (H.Q. at Nagapattinam)
6.	District and Sessions Judge,	Thanjavur (West) (H.Q. at Thanjavur)
7.	District and Sessions Judge,	Ramanathapuram (H.Q. at Madurai)
8.	District and Sessions Judge,	Dharmapuri (H.Q. at Krishnagiri)
9.	District and Sessions Judge,	Tirunelveli (H.Q. at Tirunelveli)
10.	District and Sessions Judge,	Kanny kumari (H.Q. at Nagercoil)
11.	District and Sessions Judge,	Salem (H.Q. at Salem)
12.	District and Sessions Judge,	Chengalpattu (H.Q. at Chengalpattu
13.	District and Sessions Judge,	Tiruchirappalli (H.Q. at Tiruchirappalli)
14.	District and Sessions Judge,	South Arcot (H.Q. at Quddalore)
15.	District and Sessions Judge,	Pudukko'tai (H.Q. at Pudukkottai)
16.	Chief Judicial Magistrate	Coimbatore (H.Q. at Coimbatore. Entire Coimbatore and Nilgiris Revenue Districts)
17.	The Principal Judge.	City Civil Court, Madras City."

[No. 70/TGII/1026/29/Vol II]

K. BALACHANDRAN, Secy, Railway Board.

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 17th November, 1980

S.O. 3373 .—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Karuna Mines, Salem and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Sudarsanam Daniel shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Karuna Mines, Salem in terminating the services of 31 workmen mentioned below employed in the Mangarangampalayam Lime Stone Mine with effect from 16th May, 1979 and their subsequent refusal to employ them in Palakhapalayam and Varudhampatti Limestone Mines is justified ? If not, to what relief the workmen concerned are entitled to ?"

Sarvashri

1. K. P. Kandaswami.
2. P. Palaniswamy.
3. C. Seerangam.
4. S. Kuppudasan.
5. P. Kandaswami.
6. N. Karuppan.
7. R. Doraiswami.
8. R. Thailan.
9. K. Sreerangan.
10. K. Subramani.
11. N. Natesan.
12. E. Mani.
13. K. Arumugham.
14. C. Rathinam
15. A. Veydichi.
16. A. Chinnathambi
17. C. Chinnapayyan.
18. I. Chinna Kannu.
19. P. Chinnaswami.
20. C Kannupayyan.
21. M. Nallappan.
22. P. Seerangan
23. K. Thangavelu.
24. S. Perumal.
25. C. Ammasi.
26. S Sengodan.
27. V. Kandaswami.
28. C. Ramaswami.
29. C.Kaveri.
30. V.Muthu.
31. P. Venkatachalam.

[No. L. 29011/47/80-D.III(B)]

SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

New Delhi, the 18th November, 1980

S.O. 3374.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Arbitrator in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Coalfields Limited, Pench Area,

Post Office Parasia, District Chhindwara and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th November, 1980.

BEFORE SHRI P. G. BHAVE, REGIONAL LABOUR COMMISSIONER (CENTRAL) ARBITRATOR, BOMBAY

Reference No. 2 of 1979

In the matter of Industrial Dispute between the Management of Western Coalfields Ltd., Pench Area, P.O. Parasia, District Chhindwara (Madhya Pradesh) and their workmen represented by Madhya Pradesh Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh (INTUC), P.O. Chandametta, District Chhindwara (Madhya Pradesh) regarding improper categorisation of Shri C. B. Bhojne, X-Ray Technician, Burkui Hospital.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—(1) Dr. B. L. Athaley, (2) Shri N. V. Pavgi, Sr. Personnel Officer.

On behalf of workmen—Shri S. S. Bhardwaj, Secretary, Madhya Pradesh Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh (INTUC).

STATE : Madhya Pradesh INDUSTRY : Coal Mining.

AWARD

The authorities of the Western Coalfields Ltd, Pench Area and Madhya Pradesh Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh (INTUC) signed an agreement on 8th January, 1979 under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 7 of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957 agreeing to refer the dispute to arbitration under the Act. Accordingly, the Central Government referred the following dispute for my arbitration vide their Order No. L. 22013(1)/79-D-IV(B) dated the 9th February, 1979 published in the relevant Gazette of India :

"Looking to the nature of jobs done by Shri C. B. Bhojne, X-Ray Technician Burkui Hospital, whether the demand of the union that he should be given Technical Gr. 'B' is justified, and if justified, to what relief the workman is entitled ?"

2. According to the terms of the written agreement dated 8th January, 1979 the Award was to be given within a period of two months or within such further time as extended by mutual agreement between the parties in writing. This time limit was extended from time to time by the parties and it was last extended upto 31st October, 1980.

3. Hearings were held on 18th June, 1979 ; 26th June, 1980 and the last hearing on 8th & 9th September, 1980. The Personnel Manager of Western Coalfields Ltd., Pench Area hereinafter called the 'employers') filed written statement on 18th May, 1979 and the Secretary, Madhya Pradesh Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh (INTUC) (hereinafter called the 'union') filed its written statement on 3rd April, 1979 and a rejoinder on 16th May, 1979. The Union filed three documents on 18th June, 1979 (W1, W2 & W3) and produced one witness Shri C. B. Bhojne. On 26th June, 1980, the employers filed one documents (marked E1) and examined one witness Dr. B. L. Athley. The union filed further three documents (marked W4, W5 & W6). The union filed one more document by post on 1st July, 1980 giving statement of total technical cases (with break-up) handled at the Burkui Hospital between 1969 and 1979 (Ex. W7). Both the parties argued their case at length on 8th & 9th September, 1980 at Bombay and at their request both were given time to file their written arguments so as to reach the Arbitrator on or before 27th September, 1980. Neither party's written statement reached even till 30th September, 1980.

4. The basic facts of the case as disclosed in the written statement and in the subsequent elaboration made by the management are that Shri C. B. Bhojne was appointed in Burkui Hospital as X-Ray Technician in Technical Gr. 'D' on 16th November, 1970 (though mentioned as 16th May, 1971) and subsequently he was promoted to Technical Gr. 'C' on 1st October, 1973. According to Employers, X-Ray Technicians in the entire W. C. Ltd. have been placed in Gr. 'C', hence Shri Bhojne was placed in Gr. 'C'. In the Wage Board Recommendations for Coal Mining Industry, no scale had been recommended for X-Ray Technicians. In their written statement dated 18th May, 1979 the Employer stated that negotiations were in progress for revision of wage structure in the Coal Mining industry and decision was likely to be taken soon hence at that stage revision prayed for was not justified. In the evidence tendered by Dr. B. L. Athley it was stated that Shri C. B. Bhojne whose designation is Radiographer was earlier in the scale of Tech. Gr. 'D' but subsequently he was given Tech. Gr. 'C' and he is now working in that scale. One Shri A. Powel is assisting him and Shri Powel's designation is Nephrology Technician. One Mr. Lance was working much earlier as X-Ray Technician and he then worked for about 5 years as Radiographer in Tech. Gr. 'B'. Tech. qualifications of Mr. Lance and Mr. Bhojne were almost same. That the workload now in Shri Bhojne's time has increased manifold has come out in the cross examination.

5. The Union's case in short is that Shri C. B. Bhojne was appointed at Burkui Hospital as X-Ray Technician on 16th November, 1970 in Tech. Gr. 'D' on the basic pay of Rs. 226. He was confirmed in Gr. 'D' wef 16th May, 1971. He was promoted to Tech. Gr. 'C' on 1st October, 1973 on basic pay of Rs. 245 and was drawing basic pay of Rs. 530. He holds X. Ray Technicians Diploma (one year course). He passed B.A. Part I of University of Saugar in September-October, 1977 examinations. He had successfully completed in 1968-69 in the first attempt the X-Ray Technicians' Training Course of one year at the Medical College, Nagpur. Besides his normal work, Shri Bhojne has been operating the following apparatus :

(i) ECG Machine.

(ii) Short Wave Dia-thermy machine ;

(iii) Muscle Stimulator.

Besides, he is incharge of two X-Ray Machines. Considering the volume of work, according to the union, the Company has felt necessary to have one additional post of X-Ray Technician. Hence, union prayed that Shri Bhojne be placed and regularised in Tech. Gr. 'B' with retrospective effect.

6. In the instant terms of reference the limited question is whether looking to the nature of jobs done by Shri C. B. Bhojne, X-Ray Technician of Burkui Hospital, demand for his being given Technical Gr. 'B' is justified. On the basis of the written statements of both the parties and the evidence tendered by one witness each from either side, the facts that emerge show that Burkui Hospital of Pench Area of W.C. Ltd. is one of the biggest Hospital of the area—rather the Company, with 110 beds and is also technically well equipped. In October, 1964 one Shri Stephen Lance joined Burkui Hospital as Radiographer and he was working as X-Ray Technician. In 1968 he was promoted in clerical special grade. He was also having one-year X-Ray Technician Diploma and was only a matriculate. In March, 1970, he requested the management for higher grade (above special grade). He was promptly replied by the C.M.E. that no doubt his handling of Physio Therapy apparatus was appreciated but his request for still higher grade will be considered when DIATHERMY and other apparatus are handled by him. Mr. Lance, however, left job on his own accord on 8th September, 1970. Shri C. B Bhojne was then appointed as Radiographer in Tech. Gr. 'D' on 16th November, 1970. By virtue of his competence and ability, he was confirmed after six months, that is w.e.f 16th May, 1971. He got one promotion as Tech. Gr. 'C' just after 2 years, 4 months and 15 days. Thereafter for long 7 years, he has been in the same Tech. Gr. 'C'. Shri Bhojne having desire for learning, passed B.A. Part-I in 1977. The workload has been increasingly steadily. The evidence tendered by Shri Bhojne and relevant figures of his workload in 1971 and 1978 given by him are revealing and reproduced below :

Year	X-ray cases	Spl. investigations	Screening cases	ECG cases	SWD cases
1971	1362	53	89	78	79
1978	2301	277	3238	162	199

Only recently one assistant has been provided to Shri Bhojne who helps in clerical work only. There is also one Lab. Technician, Shri A. P. Malhotra who is in Tech. Gr. 'B'. He too is having only one year diploma.

7 What was the workload in 1970 when Shri Lance was working as Radiographer in Tech Gr B', the items of work at (a) to (e) above registered in 1970 were 1206 (X Ray cases) 35 (spl investigations), 7 (screening cases), 38 (ECG) and SWD cases nil. If with equal technical and lesser educational qualification of Mr Lance as compared with Shri Bhojne, the employers could give Tech. Gr. 'B' to Mr Lance when the workload was also comparatively far less, there is no justification in keeping Shri Bhojne in Gr 'C' only

8 Based on the written arguments, the evidence adduced by both the parties before me and the arguments advanced in the course of the hearing, I hold that the nature of job performed by Shri C B Bhojne is such and the quantum of work handled by him is so heavy that he deserves being placed in Tech Gr 'B' I, therefore, answer the term of reference in affirmative and uphold the union's demand

9. In view of the above, let me now come to the only remaining question of the reference about the relief the workman is entitled to Understand the N C W.A II has ratified the decision of the Promotion Policy Committee laying down cadre Schemes/Promotion rules for certain categories of employees Recommendations for Technicians (Cat 'C') Sr Technicians (Cat 'B') are available According to it, Gr 'C' Technician with 5 years experience can be considered for Gr 'B' The W C Ltd has received these orders in June, 1980 WCL spokesman expressed preparedness to consider the case of Shri Bhojne but only from a date subsequent to the release of the Circular in June, 1980 by the Member Secretary of Jt Bipartite Committee for Coal Industry This approach is not proper The work of Shri Bhojne has been what it is, since 1971 and all the while he has been craving for promotion, but after 1st October, 1973 when he was made Tech Gr 'C', there has been no lift for him in long seven years The Union had raised a dispute in this regard in the later half of 1978 When there was no way out they could prevail upon the employers to agree to get the issue resolved through Arbitration In view of this chronology of events, long aspiration of the involved workman and strength of the case justifice demands that Shri C B Bhojne be given Technical Grade 'B' w e f 1st January 1979 I order accordingly

10 In the result, an Award is passed holding that looking to the nature of jobs done by Shri C B. Bhojne, X-ray Technician Burkui Hospital the demand of the Madhya Pradesh Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh that he should be given Technical Gr 'B' is JUSTIFIED and the same shall be effective from 1st January, 1979. Ordered accordingly

In view of the final hearing in the case at Bombay, the W C Ltd authorities to pay Rs 200 (Rupees Two hundred only) as cost to the Secretary Madhya Pradesh Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh (INTUC)

11. Before parting with the case, I would like to record my appreciation of the full co-operation received from both the parties

BOMBAY,

Dated the 31st October 1980

H. G BHAVE, Arbitrator

[No L-22013/1/79-D IV(B)]

HARBANS BAHADUR, Desk Officer

New Delhi, the 18th November, 1980.

S.O 3375 —In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of India, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th November, 1980

967 GI/80—5

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No 25 of 1978

PARTIES:

Employers in relation to the management of Bank of India, Bombay,

AND

Their Workmen

APPEARANCES

On behalf of Employers—Mr K K. Sarkar, Industrial Relations Officer.

On behalf of Workmen—Mr J M Paranjpe, Asstt. General Secretary, Federation of Bank of India Staff Unions, & Mr. Krishna Das, Secretary, Bank of India Employees' Union, Gauhati

STATE Assam INDUSTRY : Banking

AWARD

By Order No L-12011/67/77-D II A dated 25th February, 1978 the Government of India, Ministry of Labour, sent an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Bank of India, Bombay and their workmen, to this Tribunal for adjudication The dispute mentioned in the Schedule to the order of Reference reads:

> "Whether the action of the management of Bank of India in discontinuing payment of temporary emergency allowance in respect of their workmen employed in their Gauhati and Shillong Branches with effect from 1-11-1976 is proper and justified? If not, to what relief are these workmen entitled?"

2. A joint petition of compromise has been filed in this case duly signed by Mr S. N Ghosh, Regional Manager, Eastern Region of the Bank of India and on the side of the workmen by Mr. J M. Paranjpe, Assistant General Secretary of the Federation of Bank of India Staff Unions and by Mr. Krishna Das, Secretary of Bank of India Employees Union, Gauhati Unit, District Kamrup, Assam. Mr. K. K. Sarkar, Industrial Relations Officer of the Bank of India is present and Mr. Paranjpe and Mr. Das are also present on behalf of the workmen. They submit that the dispute involved in this case has been amicably settled as per terms appearing in the copy of the settlement dated 21st April, 1980 between the Indian Banks Association and All India Bank Employees' Association and National Federation of Bank Employees, marked Annexure "A" attached to the application. There is another annexure 'B' which is a copy of a settlement dated 15th July, 1980 between the Indian Banks Association and Indian National Bank Employees Congress. The terms of settlement are the same in both the Annexures Although in the petition for compromise there is a prayer that an award be passed in the case in terms of both the annexures relating to Assam allowance but as the terms are the same, it is submitted before me on behalf of both the parties that an award may be passed in terms of the settlement marked Annexure "A" relating to the Assam allowance. I have gone through the petition of compromise and the terms of settlement It appears the terms are reasonable, fair and legal.

3 As prayed for by the parties, an award is passed as per terms appearing in Annexure "A" attached to the joint petition of compromise connected with and relevant for Assam allowance The said Annexure "A" shall form part of this award

4 I understand that the Bank has made arrangement for the journies of the Assistant General Secretary of the Federation of Bank of India Staff Unions as well as of the Secretary, Bank of India Employees Union Gauhati, District Kamrup, Assam for both ways and also for special leave connected therewith I therefore, do not think it necessary to pass any order in this respect

Dated, Calcutta the 29th, October, 1980

R BHATTACHARYA, Presiding Officer.

[No. L-12011/67/77-D. II(A)]

ANNEXURE 'A

Memorandum of Settlement dated 21st April, 1980 between Indian Banks' Association and All India Bank Employees' Association and National Confederation of Bank Employees

Name of the parties	58 Banks
Representing the Employees	1 Shri K Vankatachari 2 Shri N. Veghul On behalf of the Indian Banks' Association
Representing the Workman	1 Shri D P Chadha 2. Shri K K Mandul 3. Shri Prabhat Kar 4 Shri Tarakeshwar Chakraborti 5. Shri N. Sampath on behalf of All India Bank Employees' Association 1. Shri D. P. Gupta 2. Shri C L. Rajaratnam 3 Shri C. R Chandrasakaran 4 Shri N C. Choudhuty on behalf of National Confederation of Bank Employees

Preamble—Whereas the Goa Allowance and Assam Allowance paid/payable to the workmen were under discussion between the parties during the Bipartite negotiations

And whereas, there are cases also pending before Tribunals in respect of these allowances

It is now agreed by and between the parties as under :—

(1) Goa Allowance—(a) Till 31st August, 1978 Goa Allowance will be payable to all employees in all banks which were paying Goa allowance at the rates obtaining in the respective Banks

(b) From 1st September, 1978—

(i) CCA would be payable in the urban agglomeration of Panaji and Marmugao

(ii) HRA will be payable in accordance with Bipartite Settlement at the Places in Goa eligible for the same

(iii) In respect of employees covered by (a) above and who continue to be in Goa as on the date of this Settlement, if the aggregate of the HRA and CCA falls short of the Goa allowance payable to them, such shortfall will be continued to be paid to them from time to time as Goa allowance.

(2) Assam Allowance—(a) All employees who were working prior to 31st March, 1980 in the Banks where Assam Allowance (by any name) was being paid, the Assam Allowance will be paid till 31st March, 1980 at the respective rates

(b) From 1st April, 1980 those employees will continue to draw the allowance at the same rates

(c) In all other cases, in all banks, the allowance will be paid at a flat rate of Rs 10 from 1st April, 1980

(d) It is understood that Assam Allowance shall be paid as per clauses (a), (b) and (c) above in other States, viz. Manipur, Tripura, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram where the said allowance (by any name) was being paid till special area allowances payable in these areas are settled in respect of workmen in these areas

In respect of the proceedings now pending before the Tribunals in respect of 'Goa Allowance' and 'Assam Allowance', this Agreement will be submitted to the respective Tribunals with the request for a 'Consent Award' on these terms

For Indian Banks' Association

K Venkatachari Sd/

N Vaghul Sd/-

For ALL INDIA BANK EMPLOYEES' ASSOCIATION,

B P Chadha Sd/-

Tarakeswar Chakraborty Sd/

For NATIONAL CONFEDERATION OF BANK EMPLOYEES

C L Rajaratnam Sd/-

C R Chandrasekaran Sd/-

Witnesses

1 M Ram Mohan Rao Sd/

2 N Sampath Sd/-

3 R Sivagyanam Sd/-

Dated April 21st, 1980

Place Madras.

Copy to (1) Conciliation Officer (Central), Madras

(2) Regional Labour Commissioner (Central) Madras

(3) Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi

(4) The Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi

S O. 3376 —In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th November, 1980

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CALCUTTA

Reference No 77 of 1980

PARTIES

Employers in relation to the management of Punjab National Bank.

AND

Their Workmen

APPEARANCES

On behalf of Employers—Mr J Bag, Regional Manager

On behalf of Workmen—Mr P K. Biswas, General Secretary Punjab National Bank Shramik Union

STATE West Bengal INDUSTRY Banking

AWARD

This reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 was sent to this Tribunal by the Government of India, Ministry of Labour under Order No L-12012/44/80-D II A dated 20th September, 1980 for adjudication The Schedule to the order of reference reads

"Whether the action of the management of Punjab National Bank, 18A, Brabourne Road, Calcutta-700001 in terminating the services of Shri Ram Narayan Singh, temporary Sub staff of the Bara Bazar Branch of the Bank Calcutta with effect from 12-12-79 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2 A joint petition of compromise was filed in this case on 27-10-1980 on behalf of Punjab National Bank and also their workman represented by the General Secretary, Punjab National Bank Shramik Union along with a Memorandum of Settlement marked Annexure "A" thereto Both the petition and the memorandum of settlement are signed by

Mr. J. Bag, Regional Manager on behalf of the Bank and Mr. P. K. Biswas, General Secretary of the Shramik union already mentioned.

3. To-day the Regional Manager of the Bank and the General Secretary of the Union appeared before and moved the said joint petition of compromise and they prayed that an award may be passed in terms of the memorandum of settlement, Annexure "A" to the petition. I have gone through the petition of compromise and the terms of settlement and I find that the compromise is legal and the terms are reasonable.

3. As prayed for by the parties, I pass an award on the submission of the parties treating the said joint petition of compromise with the Memorandum of Settlement, Annexure "A" thereto as part thereof.

Dated, Calcutta,
The 31st October, 1980.

R. BHATTACHARYA, Presiding Officer.

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CALCUTTA

In the matter of :

Government of India, Ministry of Labour, Order No. L-12012/44/80-D. IIA dated 20th September 1980.

AND

In the matter of :

Reference No. 77 of 1980

BETWEEN

The Employers in relation to the management of Punjab National Bank .

AND

Their Workmen

The Humble Joint Petition of Punjab National Bank and their workmen represented by the General Secretary, Punjab National Bank Shramik Union, 135 Biplol Rash Behari Basu Road, Calcutta-1.

Most Respectfully sheweth :

1. By the above Reference the Govenment of India referred the following issue for adjudication by this Hon'ble Tribunal :

"Whether the action of the management of Punjab National Bank, 18A, Brabourne Road, Calcutta-700001 in terminating the services of Shri Ram Narayan Singh, temporary Sub-staff to the Bara Bazar Branch of the Bank, Calcutta with effect from 12-12-79 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. The Parties have come to an amicable settlement of this dispute and a signed copy of the Settlement dated 16-9-80 is attached and marked Annexure "A".

3. The Parties pray that an award may be passed in terms of the Settlement.

For and on behalf of
Punjab National Bank

Sd/-
(J. BAG)

For and on behalf of
Punjab National Bank
Shramik Union

Dated 27-10-80

(P. K. BISWAS, General Secy.

Memorandum of settlement entered U/s 2(P) read with sec 18(1) of the ID Act, 1947 as amended between Punjab National Bank and PNB Sramik Union, Calcutta in the matter of Sri RN Singh, Ex-Casual Labour, PNB Barabazar Calcutta

PARTIES :

(1) Regional Manager
Punjab National Bank
Calcutta.

(1.) Sri P. K. Biswas
General Secretary
PNB Sramik Union.

(2) Sri RN Singh
Workman concerned.

SHORT RECITAL OF THE CASE

Sri Singh was appointed as a casual labour on 1-9-76 on daily wages of Rs. 3 per day and his appointment was continued upto 12-12-79. PNB Sramik Union raised an industrial dispute before the ALC, Calcutta demanding re-instatement of Sri Singh in the subordinate cadre and full wages for the period of his temporary appointment. The conciliation proceedings ended in failure. However, the matter was discussed between the parties and the following settlement has been arived at on 16th September, 1980 at Calcutta.

Terms of Settlement

(1) The Bank, without prejudice to the stand taken by it before the ALC agrees to appoint Sri R. N. Singh as probationary Peon|Cleaner in a sanctioned vacancy in any of the offices in Calcutta. He will be paid starting salary as admissible to the subordinate cadre in terms of the Bipartite Settlement. He will be considered for confirmation after completion of the prescribed probationary period, subject to satisfactory report on his work and conduct. Sri Singh shall report for receiving the letter of appointment within 15 days of signing the settlement.

(2) The Union and the workman on their part agree to give up their claim for full wages to Sri Singh for the period of his casual employment and also for the period intervening between his termination and appointment as probationer in the subordinate cadre.

(3) It is agreed that this is in full and final settlement of all the demands of the Union and the workman in respect of the temporary appointment of Sri Singh and also the period intervening between his termination and appointment as probationer and neither the Union nor the workman will raise any demand, monetary or otherwise before any forum in future.

(4) This settlement has been arrived at having regard to the peculiar circumstances of the case and shall not be quoted as precedent by any parties at any forum.

DATED : 16/9/1980

Sd/-

(1) (P. K. BISWAS)
GENERAL SECRETARY
PNB SRAMIK UNION

Sd/-

(2) (RAM NARAYAN SINGH)

WITNESS :

Sd/-

(1) (RAJARAM MUKHERJEE)

Sd./-

(2) (ALOK KUMAR DAS)

Sd/-
(J. BAG)
for Regional Manager.

[No. L-12012/44/80-D-II(A)]
S. S. MEHTA, Desk Officer.

New Delhi, the 21st November, 1980

S.O. 3377 .—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Central Railway Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th November, 1980.

BEFORE SHRI JITENDRA NARAYAN SINGH PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/5 of 1979

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of the Central Railway, Bombay.

AND

Their Workman

APPEARANCES :

For the Employers—Shri P. R. Pai, Advocate.

For the Workman—Shri D. V. Gangal, Advocate.

INDUSTRY : Railways STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 28th October, 1980

AWARD

The Government of India, in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred to this Tribunal the following industrial dispute for adjudication by order No. L-41012(6)/78-D.II(B) dated 29-3-1979 :—

"Whether the action of the management of the Central Railway, Bombay in removing Shri Mana Dondibe Supekar, Driver, from service as their No. T/102/P/143/75-76 dated the 29th March, 1977 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

According to the workman he was appointed as a Yard Khalasi on 4-8-1944 by the Central Railway and was promoted as Driver 'C' in 1963. His work was all along satisfactory and he discharged his duties honestly and efficiently. It is then stated that he was booked on V-35 Down Goods Train on 16-2-1976 when he was over hours on duty. He requested for a relief driver but the same was refused. He however performed his duties as Driver on 16-2-1976 on the aforesaid train.

It is further stated that a chargesheet dated 9-4-1976 was issued against him alleging that while functioning as Driver 'C' of V-35 Down Goods train on 16-2-1976 he committed serious neglect of duty by violating GR 76(a) and SR 76-2(b) of G & SR and passed Anakai Station all stop Signals in the 'ON' position

The workman denied the charge and there was an enquiry conducted against him under the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules 1968. Shri Athevale was appointed as an Enquiry Officer to enquire into the charge framed against the worman. The Enquiry Officer held the enquiry and came to the conclusion that the workman was not responsible in case. It is submitted that inspite of innocence of the workman being established the Senior Divisional Mechanical Engineer, Central Railway, Bhusaval issued a Memo. dated 7-9-1976 asking the workman to show cause why his basic pay should not be reduced by two stages for one year (non-cumulative). The workman showed cause but without giving any reason for disagreeing with the finding of innocence recorded by the Eunquiry Officer, the Senior Divisional Mechanical Engineer reduced the basic pay of the workman to Rs. 464 by his order dated 23-9/1/10-1976.

Thereafter on 24/30-12-1976 the Chief Operating Superintendent issued yet another Memo. under Rule 25 of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules 1968 asking the workman why he should not be removed from service. The workman was shocked to find that he was being punished though he was innocent. The workman submitted a representation to the Chief Operating Superintendent. The Chief Operating Superintendent by his order dated 29-3-1977 enhanced the punishment from reduction in pay by two stages to that of removal from service and his finding was that the workman has passed the Signal in the ON position and there was an attempt to hush up the incident. It is submitted that the latter part of the charge i.e attempt to hush up the incident was never asked to show cause on the aforesaid charge and therefore it is illegal on the part of the Chief Operating Superintendent to hold the workman guilty on an unfounded charge. He had no power to add to a charge while imposing the punishment.

The workman, however, forwarded an appeal to the General Manager, which was also rejected and he was not given any personal hearing. It is stated that he was not found guilty of the charges by the Enquiry Officer but the Senior Divisional Mechanical Engineer without assigning any reason disagreed with the finding of the Enquiry Officer and inflicted the punishment of reduction in the basic pay of the workman from Rs. 488 to Rs. 464 illegally and the Chief Operating Superintendent enhanced the punishment to that of removal from service. It is submitted that the workman has been removed from service on a charge not framed or proved against him and the order passed by the Senior Divisional Mechanical Engineer as also the Chief Operating Superintendent are illegal and not in accordance with law. It is also submitted that priciples of natural justice has been violated as the workman has been punished on a charge which was never framed against him, and the order disagreeing with the finding of the Enquiry Officer is without any reason and most unjustified. The workman has challenged the order of removal as illegal, mala fide, capricious and unjustified and has prayed that he be reinstated in service with full back wages.

The Railway has contested the case and filed their written statement. It is stated that the fact finding Enquiry Committee of three Assistant Officers held the workman responsible for violation of GR 76(a) and SR. 76-2(b) of the G. and S. Rules while working as Driver of V-35 Down Goods train disregarded all stop signals in ON position with excessive speed and entered into block section of Ankai Killa Station without proper authority on 16-2-1976. After the fact finding enquiry a D.A.R. enquiry was conducted in this case to comply with the provisions of Article 309 but the Enquiry Officer did not hold him guilty of the charges levelled against him. The Senior Divisional Mechanical Engineer Bhusaval did not agree with the finding of the D.A.R. Enquiry on the ground that the Enquiry was not conducted properly and issued show cause and considering the reply to show cause he inflicted the punishment as mentioned by the workmen but the Chief Operating Superintendent took a review of adequacy of punishment on the driver and removal him from service after issue of a show cause notice. It is submitted that the order passed by the aforesaid two officers are legal and valid and in accordance with law and reasonable opportunity was given to the workman to defend himself. Other allegations as made by the workman have been totally denied.

Point for consideration is whether the action of the management of the Central Railway, Bombay in removing Shri Nana Dhondiba Supekar from service is justified.

The learned Advocate for the workman has contended that this Tribunal should first decide the preliminary issue whether the domestic enquiry has violated the principles of natural justice and whether the orders passed by the competent authority are legal and valid and thereafter if it is held against the workmen then the case should be decided on merit. In this regard he has relied on the ruling reported in 1979, II, LLJ page 194 (Shankar Chakravarti Vs. Britannia Biscuit Co. and another). The aforesaid ruling lays down that when a case of dismissal or discharge of an employee is referred for industrial adjudication the Labour Court should first decide as a preliminary issue whether the domestic enquiry has violated the principles of natural justice or not and on that decision being pronounced it will be for the management to decide whether it will adduce any evidence before the Labour Court.

It is therefore to be seen as to whether the principles of natural justice has been followed in this case.

The learned Advocate for the workman has raised the following points :—

(1) In spite of the fact that the Enquiry Officer found the workman not guilty, the Senior Divisional Mechanical Engineer disagreed with the finding and inflicted the punishment by reducing his pay by two stages and but no reason has been assigned for disagreeing with the finding of the Enquiry Officer.

(2) Though only one charge was framed against the concerned worman, the Chief Operating Superintendent while reviewing the case enhanced the punishment and held that there was an attempt by the workman to hush up the incident though there was no charge against the workman regarding the item 'attempt to hush up the incident'

It is submitted that the above facts clearly indicate that the principles of natural justice has been violated and that the workman has been penalised even for charge which was never framed against him.

It is therefore to be seen as to whether the grounds raised on behalf of the workman are tenable and justified. For this we have to look into the original enquiry proceedings and other relevant papers. The Enquiry proceedings show that only one charge was framed against the concerned workman and it reads as follows :—

"Charges framed against Dzl Driver Puntamba—
Shri Nana Dhondi while working V/5 Dn Goods Ex-PB to NGN on 15/16-2-76 passed all stop signals of Ankai station in ON position and violated GR. 76/9 and SR 76(2)(b) of G&SR vide annexure I/article I and thus disregarded the stop signals and committed serious neglect of duty vide annexure II on the stren of witnesses mentioned in Annexure IV."

Thus it will appear that there was a single charge against the workman to the effect that he passed all stop signals of Ankai Station in ON position against rules. There was absolutely on charge against him to the effect that he made any attempt to hush up the incident. The Enquiry was held by Shri Athavale, whose finding is as follows :—

"On having considered all the evidence on record, I do not find that the article of charge framed against Shri Nana Dondiba Driver 'C' PB vide Memorandum SF. 5 No. BSL-T-106|PS-1 dated 9-4-76 is established and hence he is not held responsible in this case."

The aforesaid finding was recorded after examining the witnesses at the enquiry stage. The Enquiry Officer sent his report to the Senior Divisional Mechanical Engineer who was the competent authority. The Senior Divisional Mechanical Engineer did not agree with the finding of the Enquiry Officer and issued a show cause against the concerned workman stating as to why his pay should not be reduced by two stages for one year.

It will be appropriate to refer to Rule 10(53) of Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, which provides that the disciplinary authority shall, if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge; if the evidence on record, is sufficient for the purpose. It is therefore to be seen as to whether the Senior Divisional Mechanical Engineer who was the disciplinary authority gave any reason for disagreeing with the finding of the Enquiry Officer. It will be appropriate to quote his own words from the order of the Senior Divisional Mechanical Engineer :

"I do not agree with the findings of the Sr. LI. MMR Shri J. D. Athawale, the Enquiry Officer appointed in this case. He has based his findings on rules not being followed after the driver has passed signals at ON position. Whereas the fact of the case is that the driver guard and Station Master has not reported the case and, therefore, the rules laid down were not followed. During Asstt. Officer's enquiry it was established that the Driver has passed signal in 'ON' position."

From a perusal of the aforesaid order it will appear that he has not recorded his own finding on the basis of any evidence nor assigned any reason while disagreeing with the finding of the Enquiry Officer. The only ground taken by him is that during Asstt. Officer's enquiry it was established that the Driver has passed signal in 'ON' position.

It may be mentioned at this very stage that prior to Enquiry mentioned above there was a fact finding Enquiry which was held by three officers of the Railway. The said finding of the fact finding Enquiry is on record, but the fact finding officers were not examined before the Enquiry Officer and the evidence on which this finding was based were not brought before the Enquiry Officer and the workman did not get any opportunity to go through it or cross-examine the members of Fact Finding Enquiry. In any way there was absolutely no evidence to show on what material the Fact Finding Enquiry had held the concerned workman guilty of disregarding the signal in ON position The Senior Divisional Mechanical Engineer has passed his finding as mentioned above on the report of the Fact Finding Enquiry but there was no evidence during the enquiry stage as to what was the basis of the finding of the Fact Finding Enquiry. If the Senior Divisional Mechanical Engineer wanted to rely on the report of the Fact Finding Committee he should have directed the Enquiry Officer to examine the members of the Fact Finding Committee and should have given opportunity to the workman to cross-examine them and scrutinise the evidence tendered against him before the Fact Finding Enquiry. This has not been done. Thus there has been utter disregard to the principles of natural justice. In fact it is clear that the Senior Divisional Mechanical Engineer had no evidence at all before him to hold the workman guilty.

Then let us consider the order of the Chief Operating Superintendent. In this connection it is appropriate to refer to Rule 9 of the Railway Servants (discipline and Appeal) Rules 1968. Rule 9(3)(i) provides that the disciplinary authority shall draw the substance of the imputation of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge. According to this rule the charge must be definite and distinct.

As mentioned earlier there was only one single charge which was 'disregarding the signal in ON position'. There was no charge against him to the effect 'an attempt to hushup the incident'. On this particular single charge levelled against him he was found not guilty by the Enquiry Officer but the Senior Divisional Mechanical Engineer disagreeing with the finding of the Enquiry Officer held him guilty and inflicted the punishment of reduction of his basic pay by two stages for one year. The order of the Chief Operating Superintendent passed under Rule 6(viii) of the aforesaid rule has gone further. Para 2 of his order is as follows :—

"I have gone through the entire proceedings of the case and have shifted all the evidence available to me and also representations made by you and your A.R.E. on 14-3-1977 and 21-2-1977 and I came to the conclusion that the charges made against you viz. "that you had passed the signal in the ON position and there was an attempt to hush up the incident" stand proved.

On fails to understand as to how the Chief Operating Superintendent has come to the conclusion that there was two charges against the workman when in fact there was only one charge to the effect that he passed the signal in the ON position. There was no charge against him to the effect that there was an attempt to hush up the incident. In order to enhance the punishment the Chief Operating Superintendent added this charge when no such charge was framed against the workman. Thus the order of removal passed by the Chief Operating Superintendent is without any evidence and also the second charge was never framed against the workman.

The order of removal passed by the Chief Operating Superintendent is illegal, without any evidence and against the principles of natural justice. It is clear that the principles of natural justice has been violated and the workman has been punished for a charge for which there was no evidence at all before the Enquiry Officer and that one of the charge had also not framed against him.

It is therefore held that the enquiry held against the workman is not in accordance with the rules and it has violated the principles of national justice.

The next question, however, is as to whether the management of Central Railway can be permitted to adduce any fresh evidence before this Tribunal to prove the charge of misconduct against the workman. No such prayer has been made either in the written statement or at any stage or even at the time of argument and therefore the question of allowing the Railway to adduce any fresh evidence does not arise. To support this view reliance is placed on the ruling reported in 1979, II, III, page 194 already mentioned above.

Considering these I hold that the order of removal passed by the Railway against the workman is illegal and not in accordance with law and therefore he is entitled to reinstatement with full back wages.

Award is made accordingly.

No order as to costs.

JITENDRA NARAYAN SINGH, Presiding Officer

[No. L-41012(6)/78-D.II (B)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer

New Delhi, the 25th November, 1980

S.O. 3378 .—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Saunda Colliery of Ceptral Coalfields Limited Post Office Saunda, District Hazaribagh and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th November, 1980.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 46 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Saunda Colliery of Central Coalfields Ltd., P. O. Saunda, District Hazaribagh.

AND

Their workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri T. P. Chowdhury, Advocate.
For the Wormen—Shri D. Narsingh, Advocate.

INDUSTRY : Coal. STATE : Bihar.

Dated, the 21st October, 1980

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 have referred the following dispute to this Tribunal for adjudication their Order No. L-20012/15/78-DIII(A) dated 3rd June 1978.

SCHEDULE

"Keeping in view the claim of (1) Rusana (2) Chunka (3) Bishwanath Singh (4) Hanif No. 1 (5) Asraf (6) Razaq (7) Suresh Dube (8) Md. Zahid and (9) Mustakim for being placed in Category V, whether the action of the management of Central Saunda Colliery, P. O. Saunda, District Hazaribagh of Central Coalfields Ltd., in placing (1) Tarkeshwar (2) Hanif No. 2 and (3) Sukhlal in Category V with effect from 28th June 1976, is justified? If not, to what relief are the workmen entitled?"

2. The 9 concerned workmen herein have raised this industrial dispute through the Union Koyla Khatra Janata Mazdoor Sangh (K.K.J.M.S) questioning the propriety of the action of the management in promoting the 3 workmen Tarkeshwar, Hanif No. 2 and Sukhlal (hereinafter referred to as promotees) to Category V ignoring their seniority. The facts of the case are that the 9 concerned workmen and the 3 promotees are Haulage Khalasis. The concerned workmen claim to be seniors to the promotees. They submit that the management was not justified in promoting the 3 promotees ignoring their seniority. They pray that they may be promoted to Category V with effect from the date of promotion of their juniors (promotees).

3. The management in their written statement question the competency of the union to sponsor this dispute. They say that the present dispute has been settled as early as in 1975 in consultation with the operating union Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh and United Coal Workers Union The sponsoring union was not in existence by that date. They submit that a dispute that has been thus settled should not be allowed to be reopened in the interests of industrial peace. They further state that in 1975 the existing haulages at Hatidhari and Nakari inclines were replaced by haulages of 175 Hp. To operate these new haulages the senior most Khalasis were invited. When they declined the invitation the 3 promotees and 3 others not concerned with this dispute who were already operating these new haulages were allowed to continue to do so. After watching their performance for 8 months and as per the wishes of the two operating unions the promotees were upgraded to Category V with effect from 28th June 1976. They also contend that they are within their right to straightway promote Khalasis from Category III to Category V.

4. The union in their rejoinder contends that they have the necessary locus-standi to sponsor the cause of the workmen herein They deny the averment that the concerned workmen refused to as Haulage Khalasis soon after the installation of the haulages of 175 HP. They say the plea of the management that their demand, if accepted, would unsettle the arrangement already made is not tenable. The several other pleas raised in the Management's written statement are also denied.

5. The management in their rejoinder while denying the several averments made in the workmen's written statement of claim say that the concerned workmen had no experience of operating haulages of more than 125 HP. They say that having regard to the circumstances of the case their action is justified.

6. On the above pleadings the issues that arise for consideration are :

(1) Whether the union in question has no locus-standi to sponsor the cause of the workmen herein ?

(2) Whether the demand of the concerned workmen that the promotion of the 3 workmen to Category V with effect from 28th June 1976 over-looking their seniority should be interfered with by the Tribunal is tenable ?

(3) To what relief ?

7. Issue (1).—The concerned 9 workmen and the 3 other workmen (hereinafter called promotees) are some of the haulage Khalasis working in the Central Saunda Colliery of M/s. Central Coalfields Ltd. The concerned workmen were all placed in Category IV and the promotees Sukhlal and Hanif No. 2 were said to be in Category III and Tarkeshwar in Category IV. Admittedly the 3 promotees are junior to the concerned workmen in service. MW-1 was the Manager of the colliery during the relevant period 1975 and 1976. During his tenure of office there were 6 productive inclines and 2 Pits in this colliery. These productive inclines were equipped with haulages of 75 to 105 HP. The management replaced the existing haulages at Hatidhari and Nakari inclines by 175 HP haulages. According to the recommendations of the Coal Wage Board, Khalasis operating haulageas of 75 to 125 HP should be placed in Category IV and those operating haulages of more than 125 HP in Category V. The work of installing higher horse power haulages at the 2 Inclines in question was completed by the middle of 1975. To operate these haulages the management decided to post Khalasis according to their seniority. The haulage Khalasis who were required to be shifted on account of this decision were not willing to change their places of work. The 2 Unions Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh and United Coal Workers Union that were the only unions then operating in the field also represented that the persons who were already working in these inclines before the change of haulages should not be disturbed. To maintain peaceful industrial relations the management allowed the 3 Khalasis (whose promotion is in question) and 3 others to continue to work at these inclines operating the new haulages. After judging their work for a period of 8 months they were promoted to Category V with effect from 28th June 1976. Immediately after this promotion the concerned workmen submitted the representation Ext. W-11 dated 7th August 1976 complaining that their juniors were promoted ignoring their seniority and thereafter sent the reminders Exts. W-1, W-2 and W-10. Admittedly they tried to raise an industrial dispute in this regard through their Unions Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh and United Coal Workers Union who declined to oblige After the formation of this Koyla Khetra Janata Mazdoor Sangh the workmen herein got this dispute sponsored by them. It may be noted that WW-1 Sri Jagannath Singh, Secretary of this union was a whole time worker of the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh during the relevant years 1975 and 1976

8. It is contended on behalf of the management that the union in question has hardly and following in this colliery and that the concerned workmen were not members of the same. On behalf of the management a memo dated 30th October, 1979 is filed calling upon the union to file a copy

of its constitution, Registration Certificate, original membership register, original resolution register and counterfoils of receipts of membership fee in respect of Central Saunda Colliery. The union filed the Registration certificate and 2 counterfoils of the receipts for membership fees paid by the workmen Suresh Dube (WW-2) for the year 1978 and the workman Biswanath Singh for the year 1977. On 22nd December 1979 a reply was filed to this memo stating that as the management had removed the entire property of the union from its (union's) premises they were unable to produce the documents in question "at best for the time being". They said a complete search of its available record was necessary to trace out the documents required and as the office bearers were busy with the Lok Sabha Election they required some time. The union failed to produce the other documents. WW-1, the Secretary of the union deposed that he had filed a private complaint before the Hazaribagh Magistrate Court regarding the forceful occupation of their office premises by the management. A certified copy of the complaint is not filed. He has not said a word regarding the loss of any of the documents called for from the union in the course of his evidence. Nor has he offered any other explanation for the non-production of those documents. In the absence of the same it cannot be ascertained if any of the workmen in the Central Saunda Colliery are members of this union and whether the union has been duly authorised by a resolution of its members to raise this dispute on behalf of the concerned workmen. Sri Narsingh for the workmen contends that the management should not be permitted to raise this objection at such a belated stage. Before the A.L.C. during the conciliation proceedings they have not raised this objection. They have also discussed with this very union the present demand of the workmen as can be seen from item 30 of the minutes of discussion Ext. W-6. There is some force in this argument. Hence Issue No. 1 found for the workmen.

9. Issue (2).—The management says that when they asked the senior workmen to shift from their places of work to operate the new haulages at Hatidhari and Nakari inclines they refused to do so. Therefore they had to ask the Khalasis (the promotees) already working there to operate the new 175 HP haulages. This case is spoken to by MW-1 the then Mines Manager. One of the workmen Suresh Dube as WW-2 stated that they were never asked to shift to the 2 Inclines in quesion to operate the high power haulages. But the fact remains that for 8 months after the promotees began operating the new haulages there was never any demand on their part to be posted there. Only after their juniors (promotees) were promoted to Category V with effect from 28th June 1976 they put forward their claim. WW-2 went to the extent of saying that the promotees never worked at the Hatidhari and Nakari Inclines before they were asked to operate the new haulages. I prefer to accept the evidence of MW-1 the Manager of the Mine during the relevant period when he says that the promotee Khalasis were working at the inclines in question even before the installation of the 175 HP haulages. In the written statement of claim or rejoinder the case of the management that the promotee Khalasis were already there by the date of the installation of the new haulages is not denied. I also accept the evidence of MW-1 to the effect that the senior Khalasis were offered a chance to operate the new haulages of 175 HP and only when they declined the offer, the management allowed the existing Khalasis (promotees) to operate them. It is also the management's case that the promotees also insisted on their being allowed to continue at these 2 Inclines and operate the high power haulages and this demand of theirs was supported by the 2 unions operating in the area. This is also spoken to by MW-1 and in support of that case he files Ext. M-1 a copy of the letter addressed by the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh's Branch Secretary to the Superintendent of the colliery and marked to the colliery office. This letter supports the management's case.

10. Further an industrial dispute should not be allowed to be raised in a casual manner. May be all the concerned workmen are senior to the Khalasis whose promotion is now questioned. Unless the dispute is raised on behalf of all the haulage Khalasis senior to the ones promoted, who are affected by the promotion of the latter, it may not be possible to interfere with the management's action. Piecemeal adjudication of such a dispute may lead to a multiplicity of similar industrial disputes and conflicting decisions. It is not the workmen's case that there are no Khalasis senior to them or that the other senior Khalasis have no interest in the dispute. When questioned about this, Sri Narsingh for the workmen stated that there might be other Khalasis senior to the promotees and if they also felt aggrieved there was nothing to prevent them from raising another industrial dispute. Without the entire picture being placed before the Court, no effective solution satisfactory to the workmen concerned and the management can be found.

11. It is then submitted by Sri T. P. Chowdhury for the management that Labour Courts should not encourage this opportunistic and unprincipled way of sponsoring the cause of the workmen by Trade Unions to obtain a foot hold in the area. During the relevant years 1975 and 1976 there were only 2 unions working in this field viz. Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh and United Coal Workers Union. The concerned workmen were the members of one or the other of the said 2 unions. It is the management's case that these 2 Trade Unions represented to them that the Khalasis already working at the 2 Inclines Hatidhari and Nakari should be retained there and allowed to operate the more powerful haulages. Ext. M-1 is a copy of a letter addressed by Sri Sharma, Secretary of the Central Saunda Branch of the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh to the Superintendent of the Mine requesting him to select from among the Khalasis working on the new haulages suitable persons for promotion to Category V after judging their performance. This copy Ext. M-1 was marked to the colliery office and MW-1 files that copy to show that the action of the management in promoting the 3 Khalasis had the support of the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh. WW-1 the Secretary of the Janata Khetra Union says that the signature of the Secretary Sri Sharma on Ext. M-1 is a forgery. This witness (WW-1) was a whole time worker of the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh during the relevant period, who has now formed the present union in 1977. That the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh supported the action of the management is evident from the fact they refused to raise an industrial dispute on behalf of the concerned workmen. This probablises the genuineness of Ext. M-1. Further when Ext. M-1 was got marked through MW-1, its genuineness was not questioned on behalf of the workmen though WWs-1 and 2 were present in the Court that day. The explanation that because Ext. M-1 was filed on the very day MW-1 was examined they could not examine the signature of the Secretary appearing thereon is not convincing. The other union United Coal Workers Union also seems to have supported the action of the management as can be seen from the fact that it declined to question the promotions at the instance of the rival Khalasis claiming seniority over them. Thus for one year the 2 Unions agreed to abide by the action of the management. In November, 1977 the present Union under the leadership of WW-1 is trying to reopen the issue. So long as WW-1 was in the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh he did not question the promotions of the 3 promotee Khalasis. Soon after forming the new union he tried to unsettle the existing position by raising this dispute. I agree with Mr. T. P. Chowdhury that this light hearted way of raising industrial disputes to reopen a settled issue hould not be encouraged.

12. It is argued by Sri Narsingh that there is no question of unsettling anything that is settled. They do not want the promotion of their juniors to be cancelled. The workmen are merely praying that they may also be promoted to Category V with effect from the same date as their juniors (promotees) were promoted. They also claim difference in wages from the date of the promotion of the juniors (28th June 1976) till the date of their promotion. I do not agree with Mr. Narsingh's contention that this does not result in unsettling the existing arrangements.

13. For the aforesaid reasons Issue (2) held against the workmen.

14. Issue (3).—In view of the finding on Issue (2), this Reference is answered against the workmen.

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer.

[No. L-20012|15|78-D.III(A)]

S. H. S. IYER, Desk Officer.

श्रम

नई दिल्ली,

का०आ० 3719 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 36 के अनुसरण में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1978-79

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

परिशिष्ट

कर्मचारी राज्य

31 मार्च, 1979 को समाप्त

व्यय

पिछला वर्ष (1977-78)	लेखा शीर्ष	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
	1. बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को हितलाभ		
	क. चिकित्सा हितलाभ		
44,46,64,850	(i) चिकित्सा देखरेख तथा प्रसूति सुविधाओं की व्यवस्था पर होने वाले खर्च में निगम के शेयर के रूप में राज्य सरकारों को अदायगियां।	क. 49,90,29,859	
2,64,08,246	(ii) चिकित्सा देखरेख तथा प्रसूति सुविधाएं (निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किया गया व्यय)	2,97,00,515	
47,10,73,096	जोड़-क-चिकित्सा हितलाभ		52,87,30,374
	ख. नकद हितलाभ		
27,09,36,456	1. बीमारी हितलाभ	ख 33,50,40,591	
2,62,66,978	2. विस्तारित बीमारी हितलाभ	3,14,41,961	
6,54,211	3 परिवार नियोजन के लिए वर्धित बीमारी हितलाभ	6,08,336	
1,73,39,589	4 प्रसूति हितलाभ	1,73,89,593	
	5 अपंगता हितलाभ		
5,01,33,495	(क) अस्थायी	6,45,53,267	
1,48,69,252 ग	(ख) स्थायी (पूंजीकृत मूल्य)	6,38,60,000	
1,67,90,647 घ	6. आश्रितजन हितलाभ (पूंजीकृत मूल्य)	1,44,68,000	
9,52,448	7 अन्त्येष्टि हितलाभ	9,70,536	
39,79,43,077	जोड़ ख नकद हितलाभ		52,83,32,281
86,90,16,173	आगे ले जाया गया जोड़		1,05,70,62,655

क. अनुबन्ध 1 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 1.1 देखिए।

ख अनुबन्ध 1 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 1.2 देखिए।

ग अनुबन्ध 1 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 1.3 देखिए।

घ अनुबन्ध 1 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 1.4 देखिए।

मंत्रालय

7 मई, 1980

सम्बन्धी परीक्षित लेखे तथा उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट आम सूचना के लिए प्रकाशित की जाती है।

के 1978-79 वर्ष के लेखे

क

बीमा निगम

वर्ष का आय-व्यय लेखा

आय

पिछला वर्ष (1977-78)	लेखा शीर्ष		राशि	जोड़
रुपये			रुपये	रुपये
	अंशदान			
1,31,11,81,105	नियोजक तथा कर्मचारियों के शेयर	(क)	1,45,78,73,675	
25,97,022	केवल नियोजकों का शेयर	(ख)	17,57,264	
48,90,539	केवल कर्मचारियों का शेयर	(ख)	71,05,946	
5,97,322	अंशदाओं पर ब्याज		8,57,102	
1,31,92,65,978	कुल अंशदान			1,46,75,93,978
	निगम द्वारा चिकित्सा हितलाभ पर प्रारम्भ में किए गए व्यय में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों का शेयर			
39,77,000			1,10,49,500	
				1,10,49,500
1,32,32,42,988	आगे ले जाया गया जोड़			1,47,86,43,487

(क) 1-7-73 से पहले नियोजकों का विशेष अंशदान तथा कर्मचारियों का अंशदान "केवल नियोजकों का शेयर" तथा "केवल कर्मचारियों का शेयर" उपशीर्षों के अन्तर्गत अलग-अलग दर्ज किए गए थे। क. रा. बी. अधिनियम, 1948 के अध्याय 5 के निरसन के परिणामस्वरूप अब "नियोजकों का शेयर तथा कर्मचारियों का शेयर" उपशीर्ष के अधीन इकट्ठे अंशदान दिखाए जा रहे हैं। अंशदान आय में वृद्धि तथा बकाया की बेहतर वसूली के कारण हुई है। सितम्बर, 1975 से लागू क.रा.बी अधिनियम की धारा 85-ख के परिशोधित उपबन्धों के तहत हर्जाने लगाने की शीघ्र कार्रवाई के अच्छे परिणाम निकले हैं और नियोजकों द्वारा बेहतर अनुपालन हो रहा है।

(ख) 1-7-73 से पहली अवधि के बकाया की वसूली की सूचक है।

पिछला वर्ष (1977-78)	लेखा शीर्ष	राशि	जोड़
रुपए		रुपए	रुपए
86,90,16,173	पीछे से लाया गया जोड़		1,05,70,62,655
	ग—अन्य हितलाभ		
49,849	(क) अंशत: बीमाकृत व्यक्तियों के पुनर्वास पर व्यय	28,424	
3,50,931	(ख) चिकित्सा मंडल तथा अपील अधिकरण	3,74,438	
	(ग) बीमाकृत व्यक्तियों को अदायगियां		
2,89,537	1. सवारी खर्च तथा/या मजदूरी की हानि	3,42,560	
67,980	2. परिवार नियोजन के अन्तर्गत प्रासंगिक व्यय	50	
5,82,252	(घ) विविध	क. 6,42,799	
13,40,549	जोड़-ग-अन्य हितलाभ		13,88,271
87,03,56,722	बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को कुल हितलाभ		1,05,84,50,926
	2. प्रशासन व्यय :		
	क—अधीक्षण		
53,382	1. निगम, स्थायी समिति, क्षेत्रीय मंडल आदि	54,960	
2,35,188	2. प्रधान अधिकारी	2,04,345	
55,36,025	3. अन्य अधिकारी	58,29,336	
2,72,91,379	4. लिपिकवर्गीय स्थापना	3,00,47,548	
46,23,122	5. ग्रुप घ स्टाफ	50,26,425	
95,16,932	6. आकस्मिक व्यय	1,03,09,418	
4,72,56,028	जोड़-क-अधीक्षण		5,14,72,032
	ख—क्षेत्रीय कार्य		
11,88,453	1. अधिकारी	14,64,847	
2,73,31,185	2. लिपिकवर्गीय स्थापना	2,97,84,952	
42,75,294	3. ग्रुप घ स्टाफ	45,52,562	
30,72,174	4 आकस्मिक व्यय	39,10,651	
3,58.67,106	जोड़ ख-क्षेत्रीय कार्य		3,97,13,012
95,34,79,856	आगे ले आया गया जोड़		1,14,96,35,970

क. इसमें बीमाकृत व्यक्तियों की शव-परीक्षा के लिए दी गई फीस तथा रोजगार चोट आदि के मामलों में निर्णय लेने के लिए पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य विवरण प्राप्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों को देय प्रभारों सहित विविध व्यय शामिल हैं।

पिछला वर्ष (1977–78)	लेखा शीर्ष		राशि	राशि
रुपये			रुपये	रुपये
1,32,32,42,988	पीछे से लाया गया जोड़			1,47,86,43,487
	अन्य राजस्व शीर्ष			
8,00,73,589	ब्याज तथा लाभांश		5,28,26,924(ङ)	
25,88,748	क्षतिपूर्ति	घ	42,33,772	
	किराया, महसूल तथा कर			
6,57,269	(1) निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टर्स सहित)		7,26,478	
3,48,62,153	(2) अस्पताल, डिस्पेन्सरियां तथा स्टाफ क्वार्टर		3,55,53,611	
26,18,074	शुल्क, जुर्माना तथा समपहरण		∴ 30,07,792	
14,05,209	विविध		छ 15,56,277	
12,22,05,042	अन्य राजस्व शीर्षों का जोड़			9,79,04,854
1,44,54,48,030	आगे ले जाया गया जोड़			1,57,65,48,341

घ. "क्षतिपूर्ति" के अधीन क० रा० बी० अधिनियम की धारा 58(2) के उपबन्धों के तहत राज्य सरकारों से वसूल की गई उस राशि की सूचक है जो किसी राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी अदायगियों का व्यय-भार अखिल भारतीय औसत से अधिक हो जाने पर वसूल की जाती है।

∴ इसमें नियोजकों से फ्रीकिंग मशीनों के इस्तेमाल के लिये प्राप्त लाइसेंस फीस तथा निगम को देय राशि की अदायगी न करने पर नियोजकों पर लगाए गए हर्जाने और/या ब्रंशदान कार्ड समय पर जमा न करने पर लगाए गए जुर्माने भी शामिल हैं।

छ इसमें यूनीफार्म पहचान कार्डों की लागत, अधिक अदायगियों तथा लेखा परीक्षा में नामंजूर की गई राशि की वसूली, छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान की वसूली, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की धारित कर्मचारियों के अंशदान से आय तथा अन्य आय शामिल है।

ङ अनुबन्ध II में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2 ० देखें।

पिछला वर्ष (1977-78)	लेखा शीर्ष		राशि	राशि
रुपये			रुपये	रुपये
95,34,79,856	पीछे से लाया गया जोड़			1,14,96,35,970
	ग—अन्य खर्चे			
4,04,612	(1) कानूनी खर्चे		5,13,116	
45,170	(2) बीमा न्यायालय		67,752	
63,055	(3) प्रचार तथा विज्ञापन खर्चे		1,05,851	
9,79,849	(4) बैंक लेखे रखने के लिए खर्चे	क.	8,45 465	
2,07,587	(5) लेखा परीक्षा फीस		2,55,430	
93,310	(6) छुट्टी, वेतन तथा पेंशन अग्रदान		1,38,869	
3,01,400	(7) कार्यालय भवन/स्टाफ कार का मूल्यह्रास		3,54,834	
7,50,325	(8) कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण		9,66,332	
	(9) सेवा निवृत्ति हितलाभ			
59,84,424	(क) निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन आरक्षित निधि		12 44,042	
2,62,181	(ख) क० रा० बी० निगम भविष्य निधि में निगम का अंशदान		2,58,737	
29,39,240	(ग) क० रा० बी० निगम भविष्य निधि में दिया गया ब्याज		34,24,462	
1,64,098	(घ) प्रोत्साहन बोनस		24,261	
31,000	(10) अनुकंपा आरक्षित निधि		35,000	
1,00,000	(11) भविष्य निधि जमा से जुड़ी बीमा निधि		80,000	
8,000	(12) हानियां		12	
83,055	(13) विविध		4,227	
1,24,17,306	जोड़ ग—अन्य खर्चे			83,18,390
	जोड़ शीर्ष 2—			
9,55,40,440	प्रशासन व्यय			9,95,03,434
96,58,97,162	आगे से ले आया गया जोड़			1,15,79,54,360

क. अनुबन्ध 1 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 1.5 देखिये।

ख. अनुबन्ध 1 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 1.6 देखिये।

ग. अनुबन्ध 1 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 1.7 देखिये।

पिछला वर्ष (1977-78)	लेखा शीर्ष	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,44,54,18,030	पीछे से लाया गया जोड़		1,57 65 48,341
1,44,54,48,030	आगे ले जाया गया जोड़		1,57,65,48,341

पिछला वर्ष (1977-78)	लेखा शीर्ष		राशि	जोड़
रुपये			रुपये	रुपये
96,58,97,162	पीछे से लाया गया जोड़			1,15,79,54,360
	3 चिकित्सालय और औषधालय			
31,53,779	(1) चिकित्सालय भवनों के मूल्यह्रास के लिये धन व्यवस्था जो निधि में अन्तरित की गई।		36,44,523	
91,00,566	(2) चिकित्सालयों/औषधालयों की मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए धन व्यवस्था जो निधि में अतरित की गई।		1,05,69,117	
1,22,54,345	जोड़ शीर्ष-3 चिकित्सालय तथा औषधालय			1,42,13,640
	4. पूंजीगत निर्माण/आपात आरक्षित निधि			
13,19,26,600	(1) पूंजीगत निर्माण	क.	14,67,59,400	
6,70,73,985	(2) आपात आरक्षित निधि	ख.	5,15,24,188	
19,90,00,585	जोड़ शीर्ष 4—पूंजीगत निर्माण/आपात आरक्षित निधि			19,82,83,588
1,17,71,52,092	राजस्व लेखों पर कुल व्यय			1,37,04,51,588
26,82,95,938	व्यय से अधिक आय को तुलन पक्ष मे ले जाना			20,60,96,753
1,44,54,48,030	कुल जोड़			1,57,65,48,341

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई, 1979

क. निगम की स्थायी समिति के 1-2-1974 के निर्णय के अनुसार नियोजकों तथा कर्मचारियों के अंशदान से प्राप्त कुल राजस्व का 10 प्रतिशत भाग चिकित्सालय/औषधालय/अन्य चिकित्सा संस्थान तथा कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिये पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि में जमा किया जाता है।

ख. यह 17 मार्च, 1973 को हुई अपनी बैठक में लिए गए निगम के निर्णय के अनुसार आपात आरक्षित निधि में अंतरण की सूचक है। निगम ने निर्धारित किया है कि व्यय से अधिक आय का 20 प्रतिशत भाग (जब आधिक्य 1 करोड़ रुपये से कम हो तो सम्पूर्ण राशि) आपात आरक्षित निधि में जमा किया जाना चाहिये।

पिछला वर्ष (1977-78)	लेखा शीर्ष	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,44,54,48,030	पीछे से लाया गया जोड़		1,57,65,48,341
1,44,54,48,030	कुल जोड़		1,57,65,48,341

ह०
(एम० एल० सौबती)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

परिशिष्ट

कर्मचारी राज्य

31 मार्च, 1979 को

पिछला वर्ष (1977-78)	देयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
	व्यय से अधिक आय का अतिशेष		
1,09,52,56,496	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,36,35,52,434	
26,82,95,938	वर्ष के दौरान संचयन	20,60 96,753	
1,36,35,52,434			1 56,96,49,187
	आरक्षित निधियां		
	1 पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि		
43,73,52,629	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	58 65,21,536	
13,19,26,600	जोड़ें—वर्ष में की गई धन व्यवस्था	14,67,59,400	
1,72,42,307	निवेशों से प्राप्त ब्याज	1,56,85,195	
58,65,21,536			क, 74,89,66,131
	2 स्थायी (आंशिक तथा पूर्ण) अपंगता हितलाभ आरक्षित निधि		
18,51,87,173	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	17,43,15,231	
6,96,93,000 ख.	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	6,38,60,000	
95,13,980	निवेशों से प्राप्त ब्याज	89,54,711	
(–) 5,48,23,748 ग.	घटाये-मूल्यांकन पर पांचवी पंचवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अतिशेष	—	
20,95,70,405	इस शीर्ष का आगे ले जाया गया जोड़	24,71,29,942	
1,95,00,73,970	आगे ले जाया गया जोड़		2,31,86,15,318

क. विवरण क में आय तथा अदायगी लेखा देखिये।

ख इसमे 1-10-1977 से स्थायी अपंगता हितलाभ की दरो मे वृद्धि के कारण एक समय की अतिरिक्त लागत के रूप मे 1,76,00,000रुपये की राशि शामिल है।

ग. मूल्यांकन पर पांचवीं पंचवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अतिशेष 1977-78 में समायोजित किया गया।

ख

बीमा निगम

स्थिति का तुलनपत्र

पिछला वर्ष (1977-78)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
	भूमि तथा भवन (निगम के पूर्ण स्वामित्व में)		
	क० निगम कार्यालयों के लिए भवन		
1,80,57,416	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	2,00,22,893	
19,65,477	वर्ष के दौरान वृद्धि	1,09,48,278	
2,00,22,893	जोड़ (क)	3,09,71,171	
	(ख) चिकित्सालय तथा औषधालय		
29,79,95,923*	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	32,32,08,822	
2,52,12,899	वर्ष के दौरान वृद्धि	10,73,59,190	
32,32,08,822@	जोड़ (ख)	43,05,68,012	
34,32,31,715			46,15,39,183 छ
	भूमि तथा भवन (निगम तथा राज्य सरकारों के संयुक्त स्वामित्व में) निगम का शेयर चिकित्सालय तथा औषधालय		
9,26,807	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	9,26,807	
—	वर्ष के दौरान वृद्धि	—	
9,26,807			9,26,807
34,41,58,522	आगे ले जाया गया जोड़		46,24,65,990

* अनुबन्ध 2 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2.1 देखिये।

@ अनुबन्ध 2 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2.2 देखिये।

छ सामान्य रोकड़ शेष में से बनाई गई परिसम्पत्तियों की सूचक 23,56,31,423/- रुपये की राशि शामिल है।

पिछला वर्ष (1977-78)	वेयताए	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,95,00,73,970	पीछे से लाया गया जोड़		2,31,86,15,318
20,95,70,405	इस शीर्ष का पीछे से लाया गया जोड	24,71,29,942	
(—) 3,52,55,174	घटाए—वर्ष मे की गई अदायगिया	(-) 6,08,44,036	
17,43,15,231			18,62,85,906
	3. आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि		
8,26,77,671	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	9,57,86,859	
2,30,25,000*	वर्ष मे की गई धन व्यवस्था	1,44,68,000	
40,59,767	निवेशो से प्राप्त ब्याज	49,20,649	
	घटाएं—मूल्याकन पर पाचवी पंचवार्षिक		
(—) 62,34,353	रिपोर्ट के अनुसार अतिशेष	--	
(—) 77,41,226	घटाए—वर्ष मे की गई अदायगियां	(-) 1,00,68,768	
9,57,86,859			10,51,06,740
	4 कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि		
3,58,92,828	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,12,24,332	
	जोडे—वर्ष मे जमा की गई राशि		
99,50,538	1 कर्मचारियो का अंशदान	1,23,56,746	
2,62,181	2 निगम का अशदान	2,65,372	
29,39,240	3 कर्मचारी तथा निगम के शोधरो पर ब्याज	34,24,462	
1,64,098	4. प्रोत्साहन बोनस	24,261	
4,92,08,885	इस शीर्ष का आगे ले जाया गया जोड़	5,72,95,173	
2,22,01,76,060	आगे ले जाया गया जोड़		2,61,00,07,964

*इसमें 1-10-77 से अपंगता हितलाभ की दरो में वृद्धि के कारण एक समय की अतिरिक्त लागत के रूप में 1,04,00,000/-रुपये की राशि शामिल है।

पिछला वर्ष (1977-78)		परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये			रुपये	रुपये
34,41,58,522		पीछे से लाया गया जोड़		46.24,65,990
		पूंजीगत व्यय के लिए दी गई राशि		
		(क) सामान्य रोकड़ शेष में से दी गई राशि		
4,95,54,760		पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,54,36,075	
—		जोड़ें—वर्ष में की गई अवायगियां	54,469	
(–) 41,18,685		घटाएं—समायोजन तथा वसूलियां	(–) 50,95,498	
4,54,36,075	(क)	जोड़—(क)	(क) 4,03,95,046	
		(ख) पूंजीगत निर्माण		
		आरक्षित निधि में से दी गई राशि		
13,41,76,637		पिछले तुलनपत्र के अनुसार	19,18,99,835	
8,23,26,026		जोड़ें—वर्ष में की गई अवायगियां	8,05,49,149	
(–) 2,46,02,828		घटाएं—समायोजन तथा वसूलियां	(–) 11,36,79,267	
19,18,99,835		जोड़—(ख)	15,87,69,716	
23,73,35,910				19,91,64,762
		स्टाफ कारें		
5,31,617		पिछले तुलनपत्र के अनुसार	5,65,196	
33,579		जोड़ें—वर्ष के दौरान संचयन	—	
5,65,196				5,65,196
58,20,59,628		आगे ले जाया गया जोड़		66,21,95,948

(क) 1970-71 में पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि की स्थापना पहले क०रा०बी० परियोजनाओं की मरम्मत व अनुरक्षण के लिए मूल रूप से दी गई अग्रिम राशि की सूचक है। यह भी देखा गया कि किए गए निर्माण कार्यों में कुछेक मदें पूंजीगत स्वरूप की शामिल थी। अतः उन्हें वर्ष के दौरान इस शीर्ष में समायोजित किया गया।

पिछला वर्ष (1977-78)	वेयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
2,22,01,76,060	पीछे से लाया गया जोड़		2,61,00,07,964
4,92,08,885	उपशीर्ष का पीछे से लाया गया जोड़	5,72,95,173	
(–) 79,60,565	घटाएं—वर्ष में की गई अदायगियां	(–) 84,26,704	
4,12,48,320			
	घटाएं—निम्नलिखित में अंतरित राशि		
(–) 23,988	1. पेंशन आरक्षित निधि	(–) 6,635	
—	2. अदायी जमा राशि	(–) 6,908	
4,12,24,332			4,88,54,926
	5. भविष्य निधि जमा से जुड़ी बीमा निधि		
50,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	75,063	
1,00,000	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	80,000	
—	निवेशो से प्राप्त ब्याज तथा लाभ	3,853	
(–) 74,937	घटाएं—वर्ष में की गई अदायगियां	(–) 50,434	
75,063			1,08,482
	6. कर्मचारी राज्य बीमा निगम—ग्रुप बीमा निधि		
—	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	—	
—	वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	3,15,880	
—	निवेशों से प्राप्त ब्याज तथा लाभ	—	
	घटाएं—जीवन बीमा निगम को दिया गया प्रीमियम	(–) 2,40,000	
—			75,880
2,26,14,75,455	आगे ले जाया गया जोड़		2,65,90,47,252

पिछला वर्ष (1977–78)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
58,20,59,628	पीछे से लाया गया जोड़		66,21,95,948
28,597	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	20,358	
1,24,138	जोड़ें—वर्ष में की गयी अदायगियां	1,16,471	
(–) 1,32,377	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां	(–) 108,282	
20,358			28,547
	निगम के कर्मचारियों को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ते की अग्रिम अदायगी		
91,683	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	79,236	
1,73,663	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	1,78,346	
(–) 1,86,110	घटाएं—वर्ष मे की गई वसूलियां	(–) 1,62,518	
79,236			95,064
58,22,37,988	आगे ले जाया गया जोड़		66,24,06,470

पिछला वर्ष (1977-78)	देयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
2,26,14,75,455	पीछे से लाया गया जोड़		2,65,90,48,252
	7 निगम कार्यालय के भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि		
26,43,052	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	30,73,809	
2,58,732	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	3,33,218	
1,72,025	निवेशों से प्राप्त ब्याज तथा लाभ	1,57,884	
30,73,809			35,64,911
	8. चिकित्सालय भवनों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
2,91,12,568	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	3,44,63,168	
31,53,779	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	36,44,523	
21,96,821	निवेशों से प्राप्त ब्याज	17,70,467	
3,44,63,168			3,98,78,158
	9. स्टाफ कारों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
5,04,613	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	5,95,318	
42,668	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	21,616	
48,037	निवेशों से प्राप्त ब्याज	28,848	
—	घटाएं—वर्ष में की गई अदायगियां	(−) 33,580	
5,95,318			6,12,202
2,29,96,07,750	आगे ले जाया गया जोड़		2,70,31,02,523

पिछला वर्ष 1977-78	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
58,22,37,988	पीछे से लाया गया जोड़	रुपए	66,24,06,470
	निगम के कर्मचारियों को वाहन खरीदने के लिए पेशगी		
8,78,529	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	10,40,844	
7,58,516	जोड़े—वर्ष में की गई अदायगियां	9,86,490	
(-) 5,96,201	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां	(-) 6,72,607	
10,40,844			13,54,727
	निगम के कर्मचारियों को विविध पेशगियां' (त्यौहार पेशगियां, बाढ़ पेशगियां तथा पंखा पेशगियां)		
8,46,031	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	6,69,672	
8,51,071	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	*32,94,188	
(-) 10,27,430	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां	(-) 10,65,131	
6,69,672			28,98,729
	गृह निर्माण पेशगी		
67,24,154	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	83,81,477	
26,22,991	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	27,57,935	
(-) 9,65,668	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां	(-) 11,82,352	
83,81,477			99,57,060
	राज्य सरकारों की ओर से अग्रिम अदायगियां		
8,643	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,463	
1,994	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	2,358	
(-) 9,174	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां	(-) 2,494	
1,463			1,327
59,23,31,444	आगे ले जाया गया जोड़		67,66,18,313

*अनुबन्ध 2 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2.3 देखिये।

पिछला वर्ष (1977-78)	देयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
2,29,96,07,750	पीछे से लाया गया जोड़		2,70,31,02,523
	10. निगम कार्यालयों के भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मरम्मत व अनुरक्षण आरक्षित निधि		
48,31,089	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	49,41,497	
7,50,325	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	9,66,332	
1,05,983	निवेशों से प्राप्त ब्याज	1,43,929	
(–) 7,45,900	घटाएं—व्यय के प्रमाणित विवरणों की प्राप्ति पर समायोजित राशि	(–) 4,39,062	
49,41,497			क. 56,12,696
	11. चिकित्सालय भवनों की मरम्मत व अनुरक्षण आरक्षित निधि		
6,13,81,189	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	7,13,44,246	
91,00,566	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	1,05,69,117	
28,19,239	निवेशों से प्राप्त ब्याज	24,76,467	
(–) 19,56,748	घटाएं—व्यय के प्रमाणित विवरणों की प्राप्ति पर समायोजित राशि	(–) 24,08,509	
7,13,41,246			ख. 8,19,81,321
2,37,58,93,493	आगे ले जाया गया जोड़		2,79,06,96,540

क. विवरण ख में आय तथा अदायगी लेखा देखिये।

ख. विवरण ग में आय तथा अदायगी लेखा देखिये।

पिछला वर्ष (1977-78)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
59,23,31,444	पीछे से लाया गया जोड़		67,66,18,313
	अस्पतालो/औषधालयो/निगम के कार्यालयो तथा स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत तथा अनुरक्षण की बाबत राज्य सरकार/राज्य लोक निर्माण विभाग आदि को दी गई राशि ।		
	(क) निगम के कार्यालय		
24,87,105	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	21,37,929	
3,35,194	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	10,48,311	
(–) 6,84,370	घटाएं—नकद वापसियां	(–) 3,85,694	
21,37,929			28,00,546
	(ख) अस्पताल/औषधालय/अनैक्सियां		
1,65,93,609	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	2,31,36,821	
74,47,292	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	64,54,893	
(–) 9,03,080	घटाएं—नकद वापसियां	(–) 15,73,718	
2,31,36,821	*विविध पेशगियां		2,80,17,996
17,73,656	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	20,82,545	
22,19,743	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	15,04,776	
(–) 19,10,854	घटाएं—वर्ष मे प्राप्तियां	(–) 20,38,313	
20,82,545			15,49,008
61,96,88,739	आगे ले जाया गया जोड़		70,89,85,863

*अनुबन्ध 2 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2.4 देखिए

पिछला वर्ष (1977-78)	देयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
2,37,58,93,493	पीछे से लाया गया जोड़		2,79,06,96,540
	12. निगम के कर्मचारियों के लिए आरक्षित निधि		
6,90,24,383	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	7,85,80,959	
57,06,876	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	51,71,765	
42,93,580	निवेशों से प्राप्त ब्याज	40,36,770	
8,59,938	मूल्यांकन पर पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार समायोजन	(–) 33,66,688	
(–) 13,27,806	घटाएं—वर्ष में की गई अदायगियां	(–) 14,41,702	
	जोड़ें—कर्मचारी राज्य बीमा निगम		
23,988	भविष्य निधि से अन्तरित राशि	6,635	
7,85,80,959			8,29,87,739
	13. आपात आरक्षित निधि		
20,75,09,770	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	28,33,47,207	
6,70,73,985	वर्ष में की गई धन-व्यवस्था	5,15,24,188	
87,63,452	निवेशों पर वसूल किया गया ब्याज	1,45,55,845	
28,33,47,207			34,94,27,240
2,73,78,21,659	आगे ले जाया गया जोड़		3,22,31,11,519

पिछला वर्ष (1977-78)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
61,96,88,739	पीछे से लाया गया जोड़		70,89,85,863
	क राज्य सरकारों को कर्जे		
2,92,63,430	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	2,73,23,100	
—	जोड़ें—वर्ष में की गई अग्रदायगियां	—	
(–) 19,40,330	घटाएं—राज्य सरकारों द्वारा लौटाई गई राशि	(–) 25,17,133	
2,73,23,100			2,48,05,967
	प्रेषण		
	ख नकद प्रेषण		
(–) 36,95,754	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	6,00,419	
2,58,38,85,748	जोड़ें—वर्ष में डेबिट	2,97,53,81,683	
(-) 2,57,95,89,575	घटाएं—वर्ष में क्रेडिट	(–) 2,97,82,27,992	
6,00,419			(–) 22,45,890
	अन्य प्रेषण		
	ग. विनिमय लेखा		
(–) 183	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	36,745	
8,97,66,093	जोड़ें—वर्ष में डेबिट	8,92,65,278	
(–) 8,97,29,165	घटाएं—वर्ष में क्रेडिट	(–) 8,93,62,424	
36,745			(–) 60,401
64,76,49,003	आगे ले जाया गया जोड़		73,14,85,539

क महाराष्ट्र सरकार को राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा परियोजनाओं के निर्माण और विस्तार के लिये 1977-78 से पहले दिए गए कर्जों की सूचक है।

ख. अनुबन्ध 2 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2.5 देखिये।

ग. अनुबन्ध 2 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2.6 देखिये।

पिछला वर्ष (1977-78)	वेयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
2,73,78,21,659	पीछे से लाया गया जोड़		3,22,31,11,519
	14. निगम के कर्मचारियों के लिए अनुकंपा आरक्षित निधि		
10,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	10,000	
31,000	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	35,000	
—	निवेशों से प्राप्त ब्याज	521	
(−) 31,000	घटाए—वर्ष में की गई अदायगियां	(−) 17,753	
10,000			27,768
	जमा राशि		
	प्रतिभूतियों की जमा राशि		
3,55,615	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	3,85,964	
2,76,355	जोड़े—वर्ष में जमा राशि	5,33,608	
(−) 2,46,006	घटाएं—वर्ष में लौटाई गई जमा राशि	(−) 3,25,558	
3 85,964			5,94,014
	अन्य पार्टियों को देय बिलों से कटौती		
62,581	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	31,755	
12,49,025	जोड़े—वर्ष में जमा की गई राशि	(−) 14,08,355	
(−) 12,79,851	घटाएं—वर्ष में की गई अदायगियां	(−) 13,82,732	
31,755			57,378
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि में अदावी जमा राशि		
41,961	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	50,706	
9,330	जोड़ें—वर्ष में जमा की गई राशि	6,908	
(−) 585	घटाएं—वर्ष में की गई अदायगियां	(−) 32,361	
50,706			25,253
2.73,83,00,084	आगे ले जाया गया जोड़		3,22,38,15,932

पिछला वर्ष (1977-78)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
64,76,49,003	पीछे से लाया गया जोड़		73,14,85,539
	लागत पर निवेश		
	1. पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि		
21,27,31,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	30,53,29,804	
9,32,43,804	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	5,89,58,851	
	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता		
(−) 9,45,000	या बिक्री पर वसूली	∴ —	
30,53,29,804			36,42,83,655
	2. स्थाई (आंशिक तथा पूर्ण) अपंगता हितलाभ आरक्षित निधि		
18,51,86,072	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	17,43,15,230	
2,54,03,758	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	1,19,70,676	
	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता		
(−) 3,62,74,600	या बिक्री पर वसूली	∴ —	
17,43,15,230			18,62,85,906
	3. आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि		
8,26,77,106	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	9,57,86,859	
2,71,15,753	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	93,19,881	
(−) 1,40,06,000	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	∴ —	
9,57,86,859			10,51,06,740
1,22,36,80,696	आगे ले जाया गया जोड़		1,38,71,66,840

∴ अनुबंध 2 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2.7 देखिये।

पिछला वर्ष (1977-78)	देयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
2,73,83,00,084	पीछे से लाया गया जोड़		3,22,38,15,932
	परिवार नियोजन परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से प्राप्त जमा राशि		
—	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	—	
5,00,000	जोड़ें—वर्ष में जमा राशि	7,00,000	
(–) 5,00,000	घटाएं—अपरिवार नियोजन परियोजना को की गई अदायगियां	(–) 7,00,000	
—	क. विविध जमा राशि		—
14,36,216	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	28,12,557	
62,50,102	जोड़ें—वर्ष में प्राप्त जमा राशि	29,95,780	
(–) 48,73,761	घटाएं—वर्ष में लौटाई गई जमा राशि	(–) 52,22,729	
28,12,557			5,85,608
2,74,11,12,641	आगे ले जाया गया जोड़		3,22,44,01,540

क. अन्यत्र वर्गीकृत न की गई जमा राशियों की सूचक हैं।

पिछला वर्ष (1977-78)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,22,30,80,896	पीछे से लाया गया जोड़		1,38,71,66,840
	4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि		
3,58,88,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,12,24,332	
1,19,89,732	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	76,30,594	
(-) 66,53,400	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	∴ —	
(-) 4,12,24,332			4,88,54,926
	5. भविष्य निधि जमा से जुड़ी बीमा आरक्षित निधि		
—	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	75,063	
75,063	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	33,419	
—	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	∴ —	
75,063			1,08,482
	6. ग्रुप बीमा निधि		
—	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	∴ —	
—	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	75,880	
—	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	—	
—			75,880
1,26,43,80,291	आगे ले जाया गया जोड़		1,43,62,06,128

∴*अनुबन्ध 2 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2.7 देखिये।

पिछला वर्ष (1977-78)	देयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
2,74,11,12,641	पीछे से लाया गया जोड़		3,22,44,01,540

2,74,11,12,641	आगे ले जाया गया जोड़	3,22,44,01,540

पिछला वर्ष (1977-78)	परिसम्पत्तियां		राशि	जोड़
रुपये			रुपये	रुपये
1,26,43,80,291	पीछे से लाया गया जोड़			1,43,62,06,128
	7. निगम के कार्यालय भवनो (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मूल्यह्रास आरक्षित निधि			
26,41,400	पिछले तुलनपत्र के अनुसार		30,73,808	
12,13,406	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश		4,91,103	
(–) 7,81,000	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	∴	—	
30,73,808				35,64,911
	8. चिकित्सालय भवनों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि			
2,91,12,525	पिछले तुलनपत्र के अनुसार		3,44,63,168	
1,19,88,643	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश		54,14,990	
(–) 66,38,000	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	∴	—	
3,44,63,168				3,98,78,158
	9 स्टाफ कारों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि			
5,02,935	पिछले तुलनपत्र के अनुसार		5,61,738	
78,803	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश		50,464	
(–) 20,000	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	∴	—	
5,61,738				6,12,202
1,30,24,79,005	आगे ले जाया गया जोड़			1,48,02,61,399

∴अनुबन्ध 2 व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2.7 देखिये ।

पिछला वर्ष (1977-78)	वेयनाएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
2,74,11,12,641	पीछे से लाया गया जोड़		3,22,44,01,540

2,74,11,12,641	आगे ले जाया गया जोड़	3,22,44,01,540

पिछला वर्ष (1977-78)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,30,24,79,005	पीछे से लाया गया जोड़		1,48,02,61,399
	10. निगम के कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मरम्मत व अनुसरण आरक्षित निधि		
23,43,545	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	28,03,568	
12,96,023	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	8,582	
(—) 8,36,000	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	∴ —	
28,03,568			28,12,150
	11. चिकित्सालय भवनों की मरम्मत व अनुरक्षण आरक्षित निधि		
4,47,87,593	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,82,07,426	
1,87,40,833	जोड़ें-वर्ष में किए गए निवेश	57,55,899	
(—) 1,53,21,000	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	∴ —	
4,82,07,426			5,39,63,325
1,35,34,89,999	अगले ले जाया गया जोड़		1,53,70,36,874

∴ अनुबन्ध 2 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2.7 देखिये

पिछला वर्ष (1977-78)	देयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
2,74,11,12,641	पीछे से लाया गया जोड़		3,22,44,01,540
2,74,11,12,641	आगे ले जाया गया जोड़		3,22,44,01,540

पिछला वर्ष (1977-78)	परिसम्पत्तियां		राशि	जोड़
रुपये			रुपये	रुपये
1,35,34,89,999	पीछे से लाया गया जोड़			1,53,70,36,874
	12. निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन आरक्षित निधि			
6,84,29,455	पिछले तुलनपत्र के अनुसार		7,85,80,959	
4,39,11,504	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश		44,06,780	
(—) 3,37,60,000	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	∴	—	
7,85,80,959				8,29,87,739
	13. आपात आरक्षित निधि			
20,75,00,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार		28,33,47,207	
9,18,47,207	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश		6,60,80,033	
(—) 1,60,00,000	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	∴	—	
28,33,47,207				34,94,240
1,71,54,18,165	आगे ले जाया गया जोड़			1,96,94,51,853

∴ अनुबन्ध 2 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2.7 देखिये ।

पिछला वर्ष (1977-78)	वेयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
2,74,11,12,641	पीछे से लाया गया जोड़		3,22,44,01,540
2,74,11,12,641	कुल जोड़		3,22,44,01,540

नई दिल्ली,

दिनांक : 31 मई, 1979

पिछला वर्ष (1977-78)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,71,54,18,165	पीछे से लाया गया जोड़		1,96,94,51,853
	14. अनुकम्पा आरक्षित निधि		
—	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	9,999	
9,999	जोड़ें वर्ष में किए गए निवेश	17,769	
—	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	∴ —	
9,999			27,768
	सामान्य रोकड़ शेष		
72,83,10,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार निवेश	95,95,31,370	
45,42,21,370	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	50,45,98,079	
(—) 22,30,00,000	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	(—) 27,23,56,000	
95,95,31,370			1,19,17,73,449
26,98,063	हाथ रोकड़	32,90,768	
6,34,55,044	बैंकरों के पास रोकड़	5,98,57,702	
6,61,53,107			क. 6,31,48,470
1,02,56,84,477	कुल रोकड़ शेष		1,25,49,21,919
2,74,11,12,641	कुल जोड़		3,22,44,01,540

∴ अनुबन्ध 2 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2.7 देखिए ।

क. अनुबन्ध 2 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2.8 देखिए ।

एम० एल० सोबती,
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अनुबंध-1

आय व्यय लेखे पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1.1 पृष्ठ (ii) पर 'क'

इस राशि में अस्पतालो के लिए प्रारम्भिक उपस्कर की खरीद पर व्यय में निगम का शेयर शामिल है । कृपया तुलन-पत्र पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के पैरा 2.1 तथा 2.2 भी देखिये ।

1.2 पृष्ठ (ii) पर 'ख'

व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से अतिरिक्त व्याप्ति, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 49 के तहत किसी बीमाकृत व्यक्ति को देय बीमारी हितलाभ की अवधि 1-5-1977 से किन्ही दो लगातार अवधियो मे 56 दिन से बढ़ाकर 91 दिन करने तथा मजदूरी में वृद्धि के परिणामस्वरूप हितलाभ की औसत दैनिक दर की राशि में वृद्धि के कारण हुई है ।

1.3 पृष्ठ (ii) पर 'ग'

मूल्यांकन पर पांचवीं पंचवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 5,48,23,748/- रुपये का अतिशेष 1977-78 मे समायोजित किया गया था । 1977-78 की धन-व्यवस्था में स्थायी अपंगता हितलाभ की दरो मे वृद्धि के कारण एक समय की अतिरिक्त लागत (1,76,00,000 रुपये) शामिल थी ।

1.4 पृष्ठ (ii) पर 'घ'

मूल्यांकन पर पांचवी पंचवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 62,34,353/- रुपये का अतिशेष 1977-78 में समायोजित किया गया था । 1977-78 की धन व्यवस्था में आश्रितजन हितलाभ की दरों में वृद्धि के कारण एक समय की अतिरिक्त लागत (1,04,00,000) रुपये शामिल थी ।

पृष्ठ (vi) पर 'क'

1.5 इसमें अंशदान टिकटों की बिक्री के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों द्वारा लिए गए बैंक अभरण पर तार खर्च तथा कमीशन शामिल है ।

1.6 पृष्ठ (vi) पर 'ख'

इसमे 5,61,035 रुपये की राशि शामिल नहीं है जो निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं से सम्बन्धित है और '1-क (11) चिकित्सा हितलाभ' के अन्तर्गत शामिल की गयी है क्योंकि यह राशि दिल्ली प्रशासन के साथ व्यय में शेयर की जानी है । (ख) पेंशन आरक्षित निधि के अन्तर्गत 33,66,688/- रुपये का अतिशेष व्यय में कटौती के रूप में समायोजित किया गया है ।

1.7 पृष्ठ (vi) पर 'ग'

इसमें 5,82,390/- रुपये की राशि शामिल नही है जो निदेशालय (चि०) दिल्ली के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं से सम्बन्धित है और 'क (11) चिकित्सा हितलाभ' के अन्तर्गत शामिल की गई है क्योंकि यह राशि दिल्ली प्रशासन के साथ व्यय में शेयर की जानी है ।

अनुबंध-2

तुलन-पत्र पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां

2.1 पृष्ठ (xi)*

इसमें 1970-71 (बिहार) और 1972-73 (पश्चिमी बंगाल) के दौरान अस्पतालों के लिए प्रारम्भिक उपस्कर पर विशेष आदेश के अन्तर्गत व्यय की गई 49,542/- रुपये और 25,35,343/- रुपये की राशि का व्यय शामिल है ।

2.2 पृष्ठ (xi) पर*

अस्पतालों के लिए उपस्कर पर व्यय '1-क चिकित्सा हितलाभ (1) चिकित्सा उपचार तथा प्रसूति सुविधाओं की व्यवस्था पर किए गए व्यय में निगम के शेयर के रूप में राज्य सरकारों आदि को अदायगी' शीर्ष के अन्तर्गत बुक किया जा रहा है । अस्पतालों के लिए प्रारम्भिक उपस्कर की व्यवस्था पर किये गये व्यय का पूंजीकरण राज्य सरकारों और लेखा परीक्षा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व के परामर्श से निगम के विचाराधीन है ।

2.3 पृष्ठ (xi) पर छ

'विविध पेशगियां' शीर्ष के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू शर्तों पर आवास सहायता के लिए दी गयी पेशगियों के कारण हुई है ।

2.4 पृष्ठ (xix) पर :

इसमें से शामिल है –

(1) लेखन सामग्री के नियंत्रक कलकत्ता को पेशगियां ।

(2) लोक निर्माण विभागों को पेशगियां ।

(3) राज्य सरकारों के मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभागों को पेशगियां ।

(4) निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अन्य कार्यालयों को पेशगियां ।

(5) नगरपालिका, स्थानीय निकायों आदि को पेशगियां ।

(6) कानूनी प्रभारों के लिए पेशगियां ।

(7) निगम की विभागीय कैंटीनों को पेशगियां ।

(8) अन्य वर्गीकृत न की गई अन्य पेशगियां ।

2.5 पृष्ठ (xxi) पर 'ख'

'नकद प्रेषण' शब्द का अर्थ एक लेखा मण्डल से दूसरे तथा दूसरे से पहले में निधियों (नकद) के अन्तरण से है। निगम का राजस्व भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी बैंकों के माध्यम से टिकटों की बिक्री/नकद वसूली करके एकत्र किया जाता है। प्राप्त अंशदान सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के लेखा सं० 1 (संग्रह लेखा) तथा अन्त में मुख्यालय के लेखा सं० 1 (केन्द्रीय) में अन्तरित किये जाते हैं। प्रशासनिक व्यय तथा बीमाकृत व्यक्तियों को हितलाभ की अदायगियों के लिए निधियां लेखा सं० 1 (मुख्यालय) से अन्तरण करके क्षेत्रीय कार्यालयों/स्थानीय कार्यालयों को भेजी जाती हैं। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को निधियों के अन्तरण से सम्बन्धित इस तरह के सभी लेन-देन को 'नकद प्रेषण' कहा जाता है।

'नकद प्रेषण' शीर्ष के अन्तर्गत 22,15,890/- रुपये का माइनस शेष निगम के लेखों में कुछेक के जमा राशियों के समायोजन का सूचक है जिसके लिए बैंक से डेबिट सूचना न होने के कारण दूसरी ओर डेबिट नहीं दिखाया जा सका।

2.6 पृष्ठ (xxi) पर 'ग'

'अन्य प्रेषण विनिमय लेखा' शब्द का अर्थ निगम के एक कार्यालय से दूसरी के बीच तथा दूसरे से पहले के बीच पुस्तक समायोजन से है निगम के एक कार्यालय से प्रारम्भ होने वाले तथा दूसरे निगम के कार्यालय की पुस्तकों में समायोजित किये जाने वाले लेन-देन विनिमय लेखा द्वारा अन्तरित किए जाते हैं।

'अन्य प्रेषण—विनिमय लेखा' शीर्ष के अन्तर्गत 60,401/- रुपए की राशि का माइनस शेष निगम के लेखों में कुछेक जमा राशियों के समायोजन का सूचक है जिसके लिए 1978-79 के लेखे बन्द करने से पहले दूसरी ओर डेबिट (तदनुरूपी मद) नहीं दिखाया जा सका।

2.7 पृष्ठ (xiii), (xxv), (xxvii), (xxix) तथा (xxxiii) पर :

'ब्याज तथा लाभांश के अन्तर्गत' आय में कमी 1 अक्तूबर, 1976 से भारतीय स्टेट बैंक की पुनर्निवेश योजना के अन्तर्गत आवधिक निवेश किए जाने के कारण है जिसके अधीन देय होने वाला ब्याज निवेशों की परिपक्वता पर निगम के लेखे में जमा किया जाएगा। इसके अलावा 1977-78 वर्ष तक सामान्य रोकड़ शेष में विनिधान की गई प्रतिभूतियां ऐसी थी जिन पर मासिक ब्याज मिलता था। चालू वित्तीय वर्ष से सामान्य रोकड़ शेष तथा अन्य आरक्षित निधियों में आनुपातिक आधार पर ब्याज के वितरण की परणोधित पद्धति आरम्भ किए जाने से सामान्य रोकड़ शेष में ब्याज की आय कम हो गई है। लेकिन सामान्य रोकड़ शेष में ब्याज की अन्य आरक्षित निधियों में ब्याज की अधिक आय द्वारा पूरा किया गया है।

2.8 पृष्ठ (xxxiii) पर 'क

बैंकरों के पास नकद धनराशि में निम्नलिखित शामिल है :–

	(लाख रुपयों में)
(i) क्षेत्रीय कार्यालय लेखा सं० 1 (संग्रह खाता) में शेष	134.96

क्षेत्रीय कार्यालय के लेखा संख्या 1 (संग्रह लेखा) में उपलब्ध नकद धनराशि 30 तथा 31 मार्च 1979 को प्राप्त अंशदानों की सूचक है। इसका निवेश अप्रैल, 79 के पहले सप्ताह में किया गया।

(ii) प्रशासनिक व्यय और दिल्ली में चिकित्सा देखरेख पर व्यय को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/निवेशालय (चि०) दिल्ली के लेखा संख्या 2 में शेष	159.73

क्षेत्रीय कार्यालय लेखा संख्या 2 में 159.73 लाख रुपये की राशि 2-4-79 को वेतन संवितरण तथा महीने के पहले 3 सप्ताह के दौरान प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित थी । 303.87

(iii) स्थानीय कार्यालयों के लेखा सं० 2 में शेष

बीमाकृत व्यक्तियों को नकद हितलाभों की साप्ताहिक अदायगी 1 करोड़ रुपये से अधिक होती है । स्था० का० के लेखा सं० 2 में 303 87 लाख रुपये का शेष उनकी तीन सप्ताह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित था ।

विवरण—क

31 मार्च, 79 की स्थिति के अनुसार 1978-79 वर्ष का पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि का प्राप्ति तथा अदायगी लेखा ।

	रु०	रु०		रु०	रु०
आदि शेष	58,65,21,536		पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि से उत्पन्न परिसम्पत्तियां	22,56,07,769	
वर्ष के दौरान अंशदान	14,67,59,400		निर्माण एजेंसियों को दी गई पेशगियां	15,87,69,716	
निवेशों पर ब्याज	1,56,85,195		निधि में उपलब्ध राशि	36,42,88,655	
		74,89,66,131			74,89,66,131

विवरण—ख

निगम के कार्यालयों के भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मरम्मत तथा अनुरक्षण आरक्षित निधि का प्राप्ति तथा अदायगी लेखा

	रु०	रु०		रु०	रु०
आदि शेष	49,41,497		निगम के कार्यालयों के मरम्मत तथा अनुरक्षण की बाबत राज्य सरकारों/राज्य लोक निर्माण विभागों को दी गई राशि	'क' 36,25,302	
वर्ष में की गई धन व्यवस्था	9,66,332				
निवेशों पर ब्याज	1,43,929		निधि में उपलब्ध राशि	28,12,150	
राज्य सरकारों/राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा उपयोग न की गई पेशगियों की नकद वापसी	3,85,694				
		64,37,452			64,37,452
			'क' राज्य सरकारों को दी गई पेशगियां		36,25,302
			घटायें—प्रयोग न की गई पेशगियों की नकद वापसी	3,85,694	
			घटायें—प्रमाणित व्यय विवरण की प्राप्ति पर समायोजित राशि ।	4,39,062	
					8,24,756
			तुलनपत्र के अनुसार शेष (पृष्ठ 4183)		28,00,546

विवरण—ग

अस्पताल भवनों/औषधालयों/अनैक्सियों आदि की मरम्मत तथा अनुरक्षण आरक्षित निधि का प्राप्ति तथा अदायगी लेखा

	रु०	रु०		रु०	रु०
आदि शेष	7,13,44,246		अस्पतालों/औषधालयों/अनैक्सियों की मरम्मत तथा अनुरक्षण की बाबत राज्य सरकारों/राज्य लोक निर्माण विभागों को दी गई राशि	3,20,00,223	
वर्ष में की गई धन व्यवस्था	1,05,69,117				
निवेशों पर ब्याज	24,76,467		निधि में उपलब्ध राशि	5,39,63,325	
राज्य सरकारों/राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा उपयोग न की गई पेशगियों की नकद वापसी	15,73,718				
		8,59,63,548			8,59,63,548

'क' राज्य सरकारों को दी गई पेशगियां	रु०	रु० 3,20,00,223
घटायें—प्रयोग न की गई पेशगियों की नकद वापसी	15,73,718	
घटायें—प्रमाणित व्यय विवरण की प्राप्ति पर समायोजित राशि	24,08,509	
		39,82,227
तुलनपत्र के अनुसार शेष (पृष्ठ 4183)		2,80,17,996

हितलाभों आदि की अदायगी की तुलना में प्रशासनिक लागत

	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
			(रुपयों में)			
1. कुल प्रशासनिक लागत	7,31,57,795	6,60,69,976	7,77,62,505	8,77,45,918	9,55,10,440	9,95,03,434
2. अंशदान :						
(1) नियोजकों तथा कर्मचारियों के शेयर	20,37,86,214	60,34,74,995	73,15,86,339	1,23,61,94,824	1,31,11,81,105	1,45,78,73,675
(2) केवल नियोजकों का शेयर . .	21,41,95,502	2,16,80,542	1,78,07,427	93,97,151	25,97,022	17,57,264
(3) केवल कर्मचारियों का शेयर .	22,76,57,964	1,00,74,058	1,00,09,537	1,07,22,754	48,90,539	71,05,946
(4) ब्याज . .	—	—	—	1,78,865	5,97,322	8,57,102
जोड़ .	64,56,39,680	63,52,29,595	75,94,03,303	1,25,64,93,594	1,31,92,65,988	1,46,75,93,987
3. राजस्व लेखे पर कुल व्यय	59,90,70,572	62,49,05,056	75,58,05,845	1,01,91,84,702	1,17,71,52,092	1,37,04,51,588
4 कुल हितलाभ .	45,14,88,325	46,45,26,360	57,23,86,508	70,85,36,816	87,03,56,722	1,05,84,50,926
निम्नलिखित के साथ प्रशासनिक लागत की प्रतिशतता :						
प्रशदान . .	7.72%	10.40%	10.24%	6.98%	7.24%	6.78%
राजस्व लेखे में व्यय .	8.32%	10.57%	10.29%	8.61%	8.12%	7.26%
हितलाभ . .	10.04%	14 22%	13.59%	12.38%	10.98%	9.40%

का शेष

टिप्पणी :—4 में राज्य सरकारों द्वारा किये गये चिकित्सा हितलाभ व्यय का शेयर शामिल नहीं है ।

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 1978-79 वर्ष के पूर्ववर्ती लेखाओं तथा 31 मार्च, 1979 को तुलन-पत्र की जांच कर ली है और सभी अपेक्षित सूचना और अपेक्षित स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए है और संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं यह प्रमाणित करता हू कि मेरी राय मे और मेरी सर्वोत्तम जानकारी और मुझे किए गए स्पष्टीकरण और निगम की बहियों मे किए गए उल्लेख के अनुसार यह लेखे और तुलनपत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए है और निगम के कार्य-कलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते है ।

किशोरी चरण दास, निदेशक लेखा परीक्षा,
केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली,
दिनांक : 31 दिसम्बर, 1979

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 1978 79 वर्ष के लेखाओं की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

1. सामान्य

(1) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अक्तूबर, 1948 में हुई थी । यह अधिनियम कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1951, 1966 तथा 1975 द्वारा संशोधित किया गया तथा मौसमी कारखानों के अलावा उन सभी कारखानों पर लागू किया गया जो विद्युत-शक्ति का प्रयोग करते है तथा जहां मजदूरी के लिये 20 या 20 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं अथवा काम करते थे । 1000 रुपये तक मासिक पारिश्रमिक पाने वाले सभी कर्मचारी योजना के अन्तर्गत शामिल है ।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(5) के अन्तर्गत स्थापनाओं के निम्नलिखित वर्गों पर योजना का उत्तरोत्तर विस्तार किया जा रहा है, यानी :--

(क) विद्युत्-शक्ति का प्रयोग करने वाले छोटे कारखाने जिनमें 10 से 19 व्यक्ति काम करते है तथा विद्युत्-शक्ति का प्रयोग न करने वाले कारखाने जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते है ।

(ख) दुकाने, सिनेमा, थियेटर, होटल और रेस्तरां, सड़क मोटर परिवहन तथा समाचार पत्र संस्थापनाएं जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते है । आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों और चंडीगढ़, दिल्ली, माही, गोवा, दमन और दीव तथा पांडीचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न केन्द्रों पर योजना लागू थी ।

(3) 1978-79 वर्ष के दौरान 9744 कारखानों/स्थापनाओं पर अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार किया गया जिनमें 2.73 लाख कर्मचारी योजना के अन्तर्गत आ गये । 31 मार्च, 1979 की स्थिति के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत आये कारखानों/स्थापनाओं की संख्या 59,051 थी जिनमें 58.16 लाख कर्मचारी थे (31 मार्च, 1978 को कारखानों/स्थापनाओं की संख्या 49,310 थी जिनमें 55 43 लाख कर्मचारी थे)।

(4) 1977-78 तथा 1978-79 वर्षों में निगम की आय-व्यय का विश्लेषण नीचे दिया गया है :--

आय			व्यय		
	1977-78	1978-79		1977-78	1978-79
	(लाख रुपयों में)			(लाख रुपयों में)	
नियोजकों तथा कर्मचारियों का अंशदान	1,31,12	1,45,79	1. बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को हितलाभ ।		
केवल नियोजकों का अंशदान	26	17	क. चिकित्सा हितलाभ	44,47	49,90
कर्मचारियों का अंशदान	49	71	(1) चिकित्सा उपचार की व्यवस्था पर होने वाले खर्च में निगम के शेयर के रूप में राज्य सरकारों आदि को अदायगी ।		
अंशदान पर ब्याज	6	9			
चिकित्सा हितलाभ की बाबत शुरू में निगम द्वारा किये गये व्यय में राज्य सरकारों का शेयर	40	1,10	(2) चिकित्सा उपचार तथा देख-रेख तथा प्रसूति हितलाभों पर निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किये गये खर्चे	2 64	2,97
ब्याज तथा लाभांश	8,01	5,25	ख. बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप में दिये गये नकद एवं अन्य हितलाभ	39 93	52,97
विविध	4,21	4,51	2 प्रशासनिक खर्चे		
			क. अधीक्षण	4,73	5,15
			ख. फील्ड कार्य	3,59	3,97
			ग. अन्य खर्चे	1,24	83
			3. अस्पताल एवं औषधालय	1,23	1,42
			4. पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि	13.19	14,68
			5. आपात आरक्षित निधि	6.71	5,15
			6. व्यय से अधिक आय का अतिशेष	26,83	20,61
	1,44,55	1,57,65		1,44,55	1,57,65

2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तार के लिये परिप्रेक्ष्य योजना अपर्याप्त व्याप्ति।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा करने पर संसद की प्राक्कलन समिति ने अपनी 123वी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि योजना द्वारा की गई कुल व्याप्ति लक्ष्य से बहुत कम हुई है और परिप्रेक्ष्य योजना के लिये एक पुनरीक्षण समिति के गठन करने की सिफारिश की। तदनुसार 1972 में परिप्रेक्ष्य योजना समिति का गठन किया गया। इस समिति ने (1) कर्मचारी राज्य बीमा योजना का तीन चरणों में विस्तार करने के बारे में एक पचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना (2) स्थापनाओं तथा कारखानों के व्याप्ति के लिये एक चरणबद्ध कार्यक्रम तथा (3) 1977-78 में समाप्त 5 वर्ष की अवधि के लिये लक्ष्यों की सिफारिश की।

योजना के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक प्रारम्भिक व्यवस्था पूरी न होने के कारण चरणबद्ध कार्यक्रम 1974-75 में (एक वर्ष देर से) शुरू हुआ। निर्धारित लक्ष्य की तुलना में रोजगार के नये सैक्टरों में व्याप्ति निम्न प्रकार थी:--

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धियां (आंकड़े अनन्तिम बताये गए हैं)
1973-74	4 लाख	कुछ नहीं
1974-75	7 लाख	1.15 लाख
1975-76	9 लाख	0.76 लाख
1976-77	9 लाख	1.83 लाख
1977-78	9 लाख	0.85 लाख
1978-79	--	1.39 लाख
	38 लाख	6.28 लाख

निगम ने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के निम्नलिखित कारण बताये (सितम्बर, 1979):--

(1) चिकित्सा देख-रेख प्रदान करने के लिये राज्य सरकारों के पास वास्तविक तथा वित्तीय साधनों का न होना।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2(12) में संशोधन किये बिना खानों को कारखानों के रूप में नहीं माना जा सकता।

(3) अप्रैल, 1976 में श्रम मंत्रालय ने कहा कि बैंक तथा बीमा स्थापनाओं (9.53 लाख) पर योजना के विस्तार के बारे में खान तथा बागान (17.55 लाख) के साथ बाद में विचार किया जाये।

(4) सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रम (तेल रिफाइनरियां/एच०ई०सी०) तथा सयंत्र (टिस्को, इस्को, आदि) कामगारों के कड़े विरोध के कारण व्याप्ति से मुक्त रखे गये। अतः निगम परिप्रेक्ष्य योजना समिति द्वारा सुझाये गये लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कोई अनुमानित तारीखें बताने की स्थिति में नहीं था।

3. वार्षिक लेखे : तुलन-पत्र

(क) विविध जमा.

31-3-79 की स्थिति के अनुसार "उचन्त लेखा--विविध जमा" के अन्तर्गत 5.86 लाख रुपये (अवर्गीकृत जमा) का एक क्रेडिट शेष अप्रमायोजित पड़ा हुआ था। वर्षवार ब्यौरे निम्न प्रकार है:--

वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
1974-75	(--)0.25
1975-76	(--)0.08
1976-77	0.21
1977-78	1.07
1978-79	4.91

(ख) उपस्कर की लागत को न दिखाना:--

जैसा कि 1977-78 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया जा चुका है, अस्पतालों तथा औषधियों को शुरू में दिये गये उपस्कर पर किया गया 277.07 लाख रुपये का व्यय, 25.85 लाख की राशि के अलावा तुलन-पत्र में नहीं दिखाया गया था। निगम ने बताया (अक्तूबर 1979) कि मामला अभी भी विचाराधीन है।

(ग) परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का मूल्यांकन

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 37 के अनुसार निगम की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का मूल्यांकन प्रत्येक पांच वर्ष बाद किया जाना अपेक्षित है। हालांकि 1973-74 की समाप्ति पर अपेक्षित पंच वार्षिक रिपोर्ट स्थायी समिति ने दिनांक 28-5-79 को हुई अपनी बैठक में स्वीकार कर ली थी लेकिन अभी यह निगम द्वारा स्वीकार की जानी है (नवम्बर, 1979)। इसी दौरान 31-3-79 की स्थिति के अनुसार निगम की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का छठा पंचवार्षिक मूल्यांकन आवश्यक हो गया है।

(घ) स्टाफकारों की मूल्य ह्रास आरक्षित निधि:

स्टाफकारों की मूल्य ह्रास आरक्षित निधि (6.12 लाख रुपये) 31-3-1979 को तुलन-पत्र के अनुसार स्टाफकारों की लागत (5.65 लाख रुपये) से अधिक थी। निगम ने बताया कि स्टाफकारों की लागत में वृद्धि को देखते हुए आरक्षित निधि अभी भी काफी पर्याप्त नहीं थी और मामले की आगे जांच की जा रही थी।

(ङ) हर्जानो का समुचित रूप मे लेखाओं में न दिखाया जाना

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85(ख)(1) के अन्तर्गत कर्मचारियो से वसूल किये गये हर्जाने जनवरी, 1977 से आय और व्यय लेखा मे उप-शीर्ष "फीस जुर्माने और जब्तियां" के अधीन वर्गीकृत किये गये थे । इस मद में वस्तुतः वसूल की गई राशि जैसा कि नीचे दिखाया गया है वर्ष 1977-78 और 1978-79 के लिये उपरोक्त उप-शीर्ष के अधीन आय और व्यय लेखा में दिखाई गई राशि से मेल नही खाती थी :--

वर्ष	वसूल की गई राशि	लेखाओं में परिलक्षित राशि	अन्तर
	रु०	रु०	रु०
1977-78	33,45,764	26,18,074	7,27,690
1978-79	32,72,959	29,93,978	2,78,981

अन्तर का अभी तक मिलान नही किया गया है ।

4. पेशगियां

(1) राज्य-सरकारो/राज्य-लोक निर्माण विभागों को अस्पताल, औषधालय तथा अन्य इमारतों के निर्माण तथा चिकित्सा योजनाओं के लिये पूंजीगत स्वरूप के अस्पताल उपस्कर खरीदने के लिये दी गई राशियों मे से 31 मार्च, 1979 को 19,91.65 लाख रुपये (वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है) की राशि असमायोजित रही :--

वर्ष जिस मे पेशगी दी गई	31 मार्च, 1979 की स्थिति के अनुसार असमायोजित रही राशि	
	(लाख रुपयों मे)	
1970-71 तक	4,21.20	*2.65 लाख रुपये केरल, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु सरकार द्वारा वापिस किये गये बताये गये लेकिन परियोजनाओं के ब्यौरे प्रस्तुत नही किये गये ।
1971-72	61.50	
1972-73	51.23	
1973-74	31.83	
1974-75	1,06.26	
1975-76	85.47	
1976-77	2,30.52	
1977-78	4,02.51	
1978-79	6,03.78	
जोड़	19,94.30	
घटाये वापिसी	2.65*	
शेष	19,91.65	

निगम ने उपर्युक्त राशि मे से 69.98 लाख रुपये जून, 1979 तक समायोजित कर लिये गये बताये हैं।

(2) लेखन सामग्री तथा वर्दियां, कानूनी खर्चे आदि के लिये तथा विभागीय कैन्टीनों को दी गई राशियों मे से 31-3-1979 की स्थिति के अनुसार 15.49 लाख रुपये (वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है) असमायोजित रहे :--

किस वर्ष में पेशगी दी गई	30-11-79 की स्थिति के अनुसार असमायोजित राशि
	(लाख रुपयों मे)
1970-71 तक	5.92
1971-72	0.46
1972-73	0.39
1973-74	0.11
1974-75	1.62
1975-76	0.84
1976-77	0.32
1977-78	2.54
1978-79	3.29
	15.49

(3) राज्य सरकारों/राज्य लोक निर्माण विभागों को पूर्णत. निगम के स्वामित्व में आने वाले अस्पतालों, औषधालयों तथा अन्य भवनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिये दी गई राशियों में से 31 मार्च, 1979 को 3,08 19 लाख रुपये(वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है) की राशि असमायोजित रही :—

वर्ष जिसमें पेशगी दी गई		31 मार्च, 1979 की स्थिति के अनुसार असमायोजित रही राशि
		(लाख रुपयों में)
		70.52
1974-75 तक		39.01
1975-76		
1976-77		55 21
1977-78		66.02
1978-79		79.43
	जोड़	3,08 19

निगम ने बताया (अक्तूबर, 1979) कि बकाया पेशगियों के शीघ्र निपटान के लिये सशक्त प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

5. कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, नरानगढ़ (उड़ीसा) के जारी रहने पर निष्फल व्यय ·

नरानगढ़ (उड़ीसा) में एक फाउन्ड्री के कर्मचारियों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 29-3-62 से 57 रुपये मासिक किराये पर भवन लेकर एक कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय खोला गया था । तालाबन्दी के कारण मार्च, 1973 में फाउन्ड्री को बन्द कर दिया गया तथा उसके कर्मचारियों को अप्रैल, 1974 से चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया । लेकिन औषधालय चलता रहा और नवम्बर, 1974 तथा जनवरी, 1976 में केन्द्रीय चिकित्सा भण्डार से क्रमशः 2,906.63 रुपये तथा 575 46 रुपये की दवाइया दी गई । चिकित्सा अधिकारी को अक्तूबर, 1977 में वापिस बुला लिया गया लेकिन सपोर्टिंग स्टाफ बराबर चलता रहा । औषधालय बिना किसी कार्य के चालू रहने के कारण 1.43 लाख रुपये का खर्चा हुआ तथा निगम द्वारा प्रतिपूर्ति की गई अपने 7/8 शेयर की राशि 1.28 लाख रुपये बनी । निगम ने बताया (दिसम्बर 1979) कि बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिये उड़ीसा सरकार के जिम्मेवार होने तथा परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर औषधालय को बन्द करना एक प्रशासनिक कार्रवाई होने के कारण निगम की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है ।

6 अंशदान की देर से अदायगी के लिये दण्डिक हर्जाने लगाना।

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 31क के अनुसार यदि कोई नियोजक विनियम 26 में निर्धारित समय के अन्दर अंशदान कार्ड प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जायेगा कि उसने अंशदान की अदायगी समय पर नहीं की है । कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 85(ख)(1) (संशोधन अधिनियम द्वारा 1975 में लागू) द्वारा निगम को हर्जाने वसूल करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं जो देय अंशदानों की समय पर अदायगी न कर सकने वाले नियोजकों से बकाया राशि तक हो सकते है और अधिनियम की धारा 85(ख)(2) के अनुसार ये हर्जाने भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल किये जा सकते हैं ।

निगम के मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार 1976-77 से 1978-79 तक के दौरान प्रत्येक वर्ष हर्जाने लगाये गये, वसूल किये गये और वर्ष की समाप्ति पर प्रगामी बकायों की वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार रही :—

वर्ष	लगाये गये हर्जाने	लगाये गये हर्जाने पिछले वर्ष का बकाया (लाख रुपयों में)	वसूल किये गये हर्जाने	प्रगामी बकाया
1976-77	54.64	54.66	6.56	48.10
1977-78	184.32	232.42	33.46	198.96
1978-79	(अनुपलब्ध)		32.73	(अनुपलब्ध)

31-3-1978 कि स्थिति के अनुसार जिन क्षेत्रों में बकाया हर्जाने 10 लाख रुपये से अधिक थे, उनकी स्थिति निम्न प्रकार रही

क्र०सं०	राज्य/क्षेत्र	राशि (लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	16 87
2.	केरल	19.70
3.	महाराष्ट्र	34.10
4.	पंजाब	25.85
5.	राजस्थान	11.00
6.	पश्चिमी बंगाल	56.00

कुछ क्षेत्रों की नमूना लेखा परीक्षा के परिणाम स्वरूप स्थिति निम्न प्रकार रही :

(1) आंध्र प्रदेश

1976-77 से 1978-79 के दौरान 3008 मामलों में हर्जाने लगाये गये । लेकिन यह बताया गया कि लगाये गये हर्जानों की राशि उपलब्ध नहीं है । तथापि जिन मामलों में लगाये गये हर्जानों की राशि 50 हजार रुपये से अधिक थी, उनमें प्रत्येक मामले के संबंध में प्रस्तुत की गई सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	देरी के मामलों की संख्या	अंशदान की अदायगियों की राशि	लगाये गये हर्जाने		वसूल किये गये हर्जाने		हर्जानों में छूट		31-3-79 की स्थिति के अनुसार बकाया हर्जाने	
			सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि
					(लाख रुपयों में)					
1976-77	5	24.05	5	4.07	—	—	1	2.15	4	1.92
1977-78	7	20.91	7	2.99	—	—	2	0.91	5	2.06
1978-79	4	3.96	4	1.40	—	—	3	1.39	अंतिम राशि वसूल कर ली गई ।	

(2) असम

सितम्बर, 1975 से मार्च, 1979 तक की अवधि में हर्जानों के बकायों तथा वसूली की स्थिति निम्न प्रकार रही —

विलम्बित अंशदान	प्रस्तावित हर्जाने	हर्जानों में छूट	कम किये गये हर्जाने	लगाये गये हर्जाने	वसूल किये गये हर्जाने	बकाया हर्जाने
			(लाख रुपयों में)			
28.31	7.94	1.64	4.08	2.22	0.99	1.23

बकाया हर्जानों के मामलों में से 0.35 लाख रुपये की राशि से संबंधित 24 मामले वसूली के लिये कलक्टर को भेजे गये बताये गये हैं और इस तरह 0.88 लाख रुपये की राशि से संबंधित 7 मामले बचे हैं जिन्हें कलक्टर को भेजा जाना है ।

(3) दिल्ली :

1976-77 से 78-79 के दौरान प्रत्येक वर्ष लगाये गये वसूल किये गये तथा वर्ष के अन्त में बकाया हर्जानों की स्थिति निम्न प्रकार रही :—

वर्ष	पिछला बकाया	वर्ष के दौरान लगाये गये हर्जाने	कुल हर्जाने	वर्ष के दौरान वसूल किये गए हर्जाने	31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया हर्जाने
				(लाख रुपयों में)	
1976-77	उपलब्ध नहीं	0.51	0.51	0.15	0.36
1977-78	0.36	3.03	3.39	1.54	1.85
1978-79	1.85	8.54	10.39	1.84	8.55

वार्षिक हर्जाने लगाने के लिये पुनरीक्षित मामलों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं थी । उगाही योग्य हर्जानों से संबंधित सूचना क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई । तथापि 16 मामलों में अंशदान कार्डों की नमूना जांच से पता चला कि कार्ड देर से प्राप्त होने के कारण 14.11 लाख रुपये के हर्जाने उगाही योग्य थे लेकिन चूककर्ता नियोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई (अक्तूबर, 1979) ।

(4) गुजरात :

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगाये गये, वसूल किये गये तथा बकाया हर्जानों आदि की स्थिति निम्न प्रकार रही

वर्ष	देर से अदायगी के मामलों की संख्या	लगाये गये हर्जाने मामलों की की संख्या	राशि	वसूल किये गये हर्जाने	31-3-79 तक हर्जानों में छूट	31-3-79 की स्थिति के अनुसार बकाया हर्जाने
			(लाख रुपयों में)			
1976-77	1056	769	6.00	—	—	—
1977-78	1887	1453	7.12	3.25	—	—
1978-79	980	996	10.40	1.14	1.64	17.50

उगाही योग्य वार्षिक हर्जानों से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की जा सकी क्योंकि यह बताया गया कि स्वत: स्पष्ट आदेश पास होने के बाद उसमें अन्तर हो सकते हैं । जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, छोड़े गये तथा बकाया हर्जाने 31 मार्च 1979 की स्थिति के अनुसार 1976-77 से 1978-79 वर्षों की प्रगामी स्थिति के सूचक हैं । लगाये जाने के बाद हर्जाने छोड़ने के कारण स्पष्ट नहीं किये गये ।

(5) महाराष्ट्र

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किये गये कारण बताओ नोटिस और उगाहे गये तथा वसूल किये गये हर्जानों की स्थिति निम्न प्रकार रही :

वर्ष	जारी किये गये कारण बताओ नोटिस		जारी किये गये स्वत स्पष्ट आदेश		वसूल किये गये हर्जाने
	संख्या	उगाही योग्य हर्जाने	संख्या	लगाये गये हर्जाने	
					(लाख रुपयों में)
1976-77	2,353	71.90	161	0.98	1.02
1977-78	2,717	1,51.99	535	4.11	2.68
1978-79	2,541	257.80	1,126	9.33	4 22

यह देखा गया है कि 10 मामलों में स्वत. स्पष्ट आदेश जारी करने में 14 से 28 महीने की देरी हुई । कारण बताओ नोटिसों के अनुसार 17 39 लाख रुपये की राशि के हर्जानों से संबंधित 10 अन्य मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने के 12 से 33 महीने के बाद भी स्वत: स्पष्ट आदेश जारी नहीं किये गये थे । 51.06 लाख रुपये के हर्जानों से संबंधित 7 मामलों में बकाया को समाप्त करने के लिये स्थापनाओं को किश्त सुविधा दिये जाने या पहली अवधियों के बारे में जारी किये गये कारण बताओ नोटिसों का अंतिम निपटान न किये जाने के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किए गए। यह बताया गया कि जारी किये गये कारण बताओ नोटिसों की संख्या बहुत अधिक है और इसके अलावा इन मामलों पर कार्रवाई चरणबद्ध रीति से की जाती है ।

(6) तमिलनाडु.

मामलों की संख्या तथा देरी से अदायगियों की राशि उगाही योग्य, लगाये गये, छोड़े गये तथा बकाया हर्जानों से संबंधित वर्षवार ब्यौरे क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे । 1976 77 से 1978 79 के दौरान दांडिक हर्जानों के रूप में 2.19 लाख रुपये की राशि वसूल की गई बताई गई । लेकिन कोयम्बतूर (16) तथा मद्रास (3) से संबंधित देरी से अदायगी की 19 फाइलों की नमूना जांच करने पर निम्नलिखित पता चला:

वर्ष	देरी से मामलों की संख्या	अदायगियां बकाया अंशदान	उगाही योग्य हर्जाने	लगाये गये हर्जाने		30-9-79 तक वसूल किये गए हर्जाने		30-9-1979 की स्थिति के अनुसार बकाया हर्जाने	
				मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1976-77	90	44 49	12.43	60	1.72	35	0.27	25	1.45
1977-78	50	23.01	12 21	33	2.50	22	0 55	11	1.95
1978-79	11	5.26	4.26	3	0.36	2	0.07	1	0.29

देरी से अदायगियों के 51 मामलों में से 96 मामलों में दांडिक हर्जाने लगाये गए तथा 1 मामले में छूट दी गई । बाकी 54 मामलों में दांडिक हर्जाने लगाने की कार्रवाई अभी तक रुकी हुई थी (अक्तूबर, 1979) । निगम के क्षेत्रीय निदेशक ने बताया (अक्तूबर, 1979) कि दांडिक हर्जानों की उगाही में देरी पदों को मंजूरी देर से मिलने तथा दांडिक हर्जाने लगाने के लिये कार्यविधिक संबंधी औपचारिकताओं के अनुपालन में समय लगने के कारण हुई ।

(7) कर्नाटक :

संबंधित फाइलों आदि की नमूना जांच से पता चला कि कर्नाटक क्षेत्र में 31 मार्च, 1979 तक 989 मामलों में चूककर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जानी थी । 30-6-1979 की स्थिति के अनुसार अंशदानों की अदायगी में देरी से संबंधित 10,84.485 रुपये के हर्जानों की वसूली के 134 मामले राजस्व अधिकारियों के पास रुके हुए थे । 169 मामले ऐसे थे जिनमें 31 जुलाई, 1979 तक दांडिक हर्जाने लगाने के अंतिम आदेश दिये गये थे लेकिन इन्हें अभी (सितम्बर, 1979) संग्रह के लिये राजस्व प्राधिकारियों को भेजा जाना था । यह बताया गया कि इन मामलों से संबंधित हर्जाने की कुल राशि तुरन्त उपलब्ध नहीं है । क्षेत्रीय कार्यालय में ऐसा कोई रजिस्टर/रिकार्ड नहीं रखा गया जिससे उगाही योग्य, लगाये गये, छोड़े गये या कम किये गये, वसूली किये गये तथा वसूली के लिये बकाया हर्जानों के नियोजक-वार ब्यौरों का पता चल सके । क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निगम के मुख्यालय को प्रस्तुत मासिक विवरणी से भी वसूल किए गए के अलावा हर्जानों के ब्यौरों का पता नहीं चलता ।

967 GI/80—11

7. अंशदानों के बकाया :

31 मार्च, 1979 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 1978 को समाप्त अवधि के 24,61 45 लाख रुपये की राशि के अंशदान 14,655 कारखानों के नियोजकों तथा कर्मचारियों से वसूली के लिये बाकी थे (वर्ष वार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं) :

वर्ष	नियोजकों का अंशदान	कर्मचारियों का अंशदान	नियोजकों से प्राप्त नियोजकों तथा कर्मचारियों का संयुक्त अंशदान (1-7-1973 से शुरू)	जोड़
	(लाख रुपयों में)			
दिसम्बर, 1971 तक	4,75 55	1,66 84	--	6,42.39
1-1-1972 से 31-12-1972	1,37 66	55.45	--	1,93.11
1-1-1973 से 31-12-1973	1,51.96	78 08	37.75	2,67.79
1-1-1974 से 31-12-1974	--	--	1,24.53	1,24-53
1-1-1975 से 31-12-1975			2,03.87	2,03.87
1-1-1976 से 31-12-1976	--	--	,3,50.18	3,50.18
1-1-1977 से 31-12-1977	--	--	4,81.68	4,81.68
1-1-1978 से 31-3-1978	--	--	1,97.90	1,97.90
जोड़	7,65.17	3,00.37	13,95.91	24,61.45

वसूली के लिये 100.00 लाख रुपये से अधिक बकाया वाले क्षेत्र बिहार (1,25.49 लाख रु०) दिल्ली (1,51.21 लाख रुपये), कर्नाटक (1,37.36 लाख रुपये), केरल (1,50.89 लाख रुपये), मध्य प्रदेश (1,70.34 लाख रुपये), बम्बई (3,04.08 लाख रुपये), पंजाब (1,00.04 लाख रुपये), तमिलनाडु (1,35.93 लाख रुपये), उत्तर प्रदेश (2,41.58 लाख रुपये) तथा पश्चिमी बंगाल (5,35.66 लाख रुपये) हैं।

31 मार्च, 1979 की स्थिति के अनुसार जिन 14,656 कारखानों पर 31 मार्च, 1978 को समाप्त अवधि के अंशदान बाकी थे उनमें से 552 कारखानों पर प्रत्येक से 0.50 लाख रुपये से अधिक बताया था। निगम ने बताया (सितम्बर, 1979) कि 18,81.98 लाख रुपये की बकाया राशि को वसूल करने के लिये कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है तथा 3,81.53 लाख रुपये से संबंधित मामलों में कार्रवाई विचाराधीन चल रही है और शेष 197 94 लाख रुपये की बकाया के लिये न्यायालय आदेश/आदेशों या कारखाने परिसमापन के अन्तर्गत आने या उनकी व्यक्ति विवादास्पद होने के कारण कानूनी कार्रवाई करना संभव नहीं है। निगम ने बकाया दिसम्बर, 1979) कि 31-3-1979 की स्थिति के अनुसार 27,43.58 लाख रुपये (इसमें 30-9-1978 तक 7 क्षेत्रों के बकाया के कारण 11,30.95 लाख रुपये शामिल है) बकाया थे।

8. कारखानों/स्थापनाओं का बकाया निरीक्षण :

कारखानों के निरीक्षण के अनुदेशों की पुस्तिका में दिये गये अनुदेशों के अनुसार निश्चित रूप से योजना के अन्तर्गत आये सभी कारखानों का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाना तथा योजना के अन्तर्गत न आये कारखानों का प्रत्येक दो लगातार वर्षों में एक बार सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है।

31-3-1979 की स्थिति के अनुसार कलेंडर वर्ष 1988 तक 5,565 कारखानों/स्थापनाओं का निरीक्षण बकाया था (वर्ष वार ब्यौरे नीचे दिये गये है) :—

वर्ष	किये जाने वाले निरीक्षण	किये गये निरीक्षण	31-3-1979 की स्थिति के अनुसार बकाया निरीक्षण
1973 तक	--	--	37
1974	30,453	30,381	72
1975	31,645	31,521	124
1976	36,299	35,735	564
1977	47,104	45,626	1,478
1978	54 660	49,095	5,565*

*इनमें वे कारखाने/स्थापनायें शामिल है जिनका पूर्ववर्ती वर्षों में निरीक्षण नहीं किया जा सका।

(2) योजना के अन्तर्गत न आये ऐसे कारखानों/स्थापनाओं की संख्या 9,744 थी जिनका 31-3-1979 तक सर्वेक्षण किया जाना अपेक्षित था। इनमें से 31-12-1978 तक 5,044 कारखानों/स्थापनाओं का सर्वेक्षण नहीं किया गया। लेकिन इसमें लक्ष्य के अलावा आन्ध्र प्रदेश (447), पंजाब (433) तथा पश्चिमी बंगाल (435) में सर्वेक्षण किये गये 1315 कारखाने/स्थापनायें शामिल नहीं हैं। जिन राज्यों में अनुपालन 50% से कम रहा है, वे बिहार (7%), गुजरात (27%) तथा मध्य प्रदेश (32%) है।

(3) जिन कारखानों/स्थापनाओं के संबंध में सर्वेक्षण/निरीक्षण रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं उनमें से 6,575 कारखानों/स्थापनाओं (ब्यौरे नीचे दिये गये हैं) को व्यष्टि की सही तारीख अंतिम रूप से निश्चित नहीं की गई है ।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अंतिम व्यक्ति के लिये बकाया मामलों की संख्या	निम्नलिखित अवधि तक स्थिति
1.	आन्ध्र प्रदेश	187	अप्रैल, 1979
2.	असम	71	फरवरी, 1979
3.	बिहार	275	अप्रैल, 1979
4.	दिल्ली	835	फरवरी, 1979
5.	कर्नाटक	69	मई, 1979
6.	केरल	33	मई, 1979
7.	मध्य प्रदेश	226	सितम्बर, 1979
8.	महाराष्ट्र	2,068	अप्रैल, 1979
9.	नागपुर	कुछ नहीं	जुलाई, 1979
10.	पूना	772	मार्च, 1979
11.	उड़ीसा	3	अप्रैल, 1979
12.	पंजाब	1,167	अप्रैल, 1979
13.	राजस्थान	289	मई, 1979
14.	तमिलनाडु	338	मार्च, 1979
15.	उत्तर प्रदेश	292	मई, 1979
	जोड़	6,575	

गुजरात तथा पश्चिमी बंगाल के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए । निगम बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब तथा तमिलनाडु के संबंध में बकाया मामलों की वर्षवार स्थिति प्रस्तुत नहीं कर सका ।

9 वसूल न हुई डिक्री राशि :

(1) कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालयों ने उन नियोजकों के खिलाफ डिक्रियां जारी की जिन्होंने निगम को अंशदान जमा नहीं किया । 31-3-79 तक वसूल न हुई 31.17 लाख रुपये की डिक्रियों में से 31-3-1979 की स्थिति के अनुसार 30.85 लाख रुपये की डिक्रियां (वर्षवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं) अनिष्पादित रहीं ।

डिक्री का वर्ष	लाख रुपये
1974-75 तक	23.59
1975-76	0.84
1976-77	4.68
1977-78	1.55
1978-79	0.19
जोड़	30.85

(2) 31-3-1979 की स्थिति के अनुसार एक लाख रुपये से अधिक की डिक्री राशि के राज्य-वार आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

राज्य	लाख रुपयों में
गुजरात	2.74
मध्य प्रदेश	8.54
महाराष्ट्र	2.99
पंजाब	1.79
राजस्थान	1.72
तमिलनाडु	1.76
उत्तर प्रदेश	5.63
पश्चिमी बंगाल	2.62

जहां तक वसूली न होने का संबंध है, निगम ने बताया (सितम्बर, 1979) कि डिक्रियों की वसूली निष्पादन न्यायालयों में नियमित निष्पादन कार्यवाहियां फाइल करके की जाती है । इस कार्य में देरी न केवल न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली लम्बी और कठिन कार्यविधि के कारण होती है बल्कि निर्णीत ऋणियों द्वारा अपनाये जाने वाले हथकंडों के कारण भी होती है । यह भी बताया गया कि डिक्रियों का निष्पादन पूर्णतः राज्य सरकार के तंत्र पर निर्भर होने के कारण निगम का इस मामले में कोई प्रत्यक्ष हाथ नहीं है ।

किशोरी करण दास,
निदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली
दिनांक 31 दिसम्बर, 1979

[सं० जैड०-16016/3/79-एच०आई०]
हंसराज छाबड़ा, उप-सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 7th May, 1980

S. O. 3379.—In pursuance of section 36 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the audited accounts of the Employees' State Insurance Corporation, together with audit report thereon, for the year, 1978-79, are hereby published for general information.

ACCOUNTS OF THE EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION FOR THE YEAR 1978-79

APPENDIX

EMPLOYEES, STATE

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

EXPENDITURE

Previous year (1977-78)	Heads of Account		Amount	Total
Rs.			Rs.	Rs.
	1. Benefits to Insured Persons & their families.			
	A. Medical Benefits.			
	(i) Payments to State Govts. as Corporation's Share of the expenses on providing medical treatment and maternity facilities etc.			
44,46,64,850		A	49,90,29,859	
2,64,08,246	(ii) Medical care and maternity facilities (expenses incurred direct by the Corporation).		2,97,00,515	
47,10,73,096	Total A— Medical Benefit.			52,87,30,374
	B. Cash Benefits.			
27,09,36,456	1. Sickness Benefit.	B	33,50,40,594	
2,62,66,978	2. Extended Sickness Benefit.		3,14,41,961	
6,54,211	3. Enhanced Sickness Benefit for Family Planning		6,08,336	
1,73,39,589	4. Maternity Benefit.		1,73,89,593	
	5. Disablement Benefit.			
5,01,33,495	(a) Temporary		6,45,53,267	
1,48,69,252 C	(b) Permanent (Capitalised Value)		6,38,60,000	
	6. Dependants' Benefit.			
1,67,90,647 D	(Capitalised Value)		1,44,68,000	
9,52,449	7. Funeral Benefit.		9,70,530	
39,79,43,077	Total B— Cash Benefits.			52,83,32,281
86,90,16,173	Total Carried Over			1,05,70,62,655

Note :—A. See paragraph 1.1 of the explanatory notes in Annexure I.

B. See paragraph 1.2 of the explanatory notes in Annexure I.

C. See paragraph 1.3 of the explanatory notes in Annexure I.

D. See paragraph 1.4 of the explanatory notes in Annexure I.

A

INSURANCE CORPORATION

FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 1979

INCOME

Previous year (1977-78)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs	Rs.
	1. Contributions.		
1,31,11,81,105	Employers' and Employees' Shares.	1,45,78,73,675	
25,97,022	Employer's Share only.	" " 17,57,264	
48,90,539	Employee's share only.	" " 71,05,946	
5,97,322	Interest on Contributions.	8,57,102	
1,31,92,65,988	Total Contributions.		1,46,75,93,987
39,77,000	State Government/Union Territories share towards medical benefits initially incurred by the Corporation.	1,10,49,500	
39,77,000			1,10,49,500
1,32,32,42,988	Total Carried over.		1,47,86,43,487

1 Prior to 1-7-73 the Employers' Special Contribution and Employees' Contribution were booked separately under the sub-heads "Employers' share only" and "Employees' share only". Consequent on the repeal of Chapter V of the Employees' State Insurance Act, 1948, the combined contributions are now being shown under the sub-head "Employers' & Employees' shares". The increase in contribution income is mainly due to increase in coverage and better realisation of arrears. Prompt action for levy of damages under the amended provisions of Section 85-B of the Employees' State Insurance Act which came into effect in September, 1975, is yielding results by way of better compliance from the employers.

" " Represents recoveries of arrears for the period prior to 1-7-73.

Previous year (1977-78)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
86,90,16,173	Total Brought Forward		1,05,70,62,655
	C—Other Benefits		
49,849	(a) Expenditure on the Rehabilitation of Disabled Insured Persons	28,424	
3,50,931	(b) Medical Boards & Appeal Tribunals	3,74,438	
	(c) Payments to Insured Persons		
2,89,537	(i) Conveyance charges and/or loss of wages	3,42,560	
67,980	(ii) Incidental charges under Family Planning	50	
5,82,252	(d) Miscellaneous	A 6,42,799	
13,40,549	Total C—Other Benefits		13,88,271
87,03,56,722	Total Benefits to Insured Persons & their families		1,05,84,50,926
	2. Administration Expenses		
	A. Superintendence		
53,382	1. Corporation, Standing Committee, Regional Boards etc	54,960	
2,35,188	2. Principal Officers	2,04,345	
55,36,025	3. Other Officers	58,29,336	
2,72,91,379	4. Ministerial Establishment	3,00,47,548	
46,23,122	5. Group D Staff	50,26,425	
95,16,932	6. Contingencies	1,03,09,418	
4,72,56,028	Total A—Superintendence		5,14,72,032
	B—Field work		
11,88,453	1. Officers	14,64,847	
2,73,31,185	2. Ministerial Establishment	2,97,84,952	
42,75,294	3. Group D Staff	45,52,562	
30,72,174	4. Contingencies	39,10,651	
3,58,67,106	Total B—Field work		3,97,13,012
95,34,79,856	Total Carried Over		1,14,96,35,970

A. This includes miscellaneous expenses including fee paid for post mortem examination of insured persons and charges payable to police authorities for obtaining police reports and other statements for deciding cases of employment injuries etc.

Previous year (1977-78)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,32,32,42,988	Total Brought Forward		1,47,86,43,487
	Other Heads of Revenue		
8,00,73,589	Interest & Dividends	5,28,26,924@	
25,88,748	Compensations	$42,33,772	
	Rents, Rates and Taxes		
6,57,269	(i) Offices of the Corporation (including Staff Quarters)	7,26,478	
3,48,62,153	(ii) Hospitals, Dispensaries and Staff Quarters	3,55,53,611	
26,18,074	Fees, Fines & Forfeitures	%10,07,792	
14,05,209	Miscellaneous	£ 15,56,277	
12,22,05,042	Total of other Heads of Revenue		9,79,04,854
1,44,54,48,030	Total Carried Over		1,57,65,48,341

$ The receipts under 'Compensations' represent the amount recovered from the State Governments under the provisions of Section 58(2) of the Employees' State Insurance Act, in cases where the incidence of sickness payments to insured persons in any State is found to exceed the All India average.

% This includes receipts on account of licence fee from the employers for use of franking machines by them and also damages levied on the employers for failure to pay dues of the Corporation and/or non-submission of contribution cards in time.

£ This includes receipts on account of cost of duplicate identity cards, recoveries of over payments and disallowances in audit, recoveries of leave salary and pension contributions, employees' contribution towards Central Government Health Scheme and other receipts.

@ See Paragraph 2.7 of the explanatory notes in Annexure-II.

Previous year (1977-78)	Heads of Account		Amount	Total
Rs.			Rs.	Rs.
95,34,79,856	Total Brought Forward			1,14,96,35,970
	C—Other Charges			
4,04,612	1. Legal Charges		5,13,116	
45,170	2. Insurance Courts		67,752	
63,055	3. Publicity & Advertisement Charges		1,05,851	
9,79,849	4. Charges for maintaining Banking Accounts	A	8,45,465	
2,07,587	5. Audit Fees		2,55,430	
93,310	6. Leave Salary & Pension Contributions		1,38,869	
3,01,400	7. Depreciation of Office Buildings/Staff Cars		3,54,834	
7,50,325	8. Repairs & Maintenance of Office Buildings		9,66,332	
	9. Retirement Benefits			
59,84,424 C	(a) Pension Reserve Fund for the employees of the Corporation	B	12,44,042	
2,62,181	(b) Corporation's Contribution towards Employees' State Insurance Corporation Provident Fund		2,58,737	
29,39,240	(c) Interest paid to ESIC Provident Fund		34,24,462	
1,64,098	(d) Incentive Bonus		24,261	
31,000	10. Compassionate Reserve Fund		35,000	
1,00,000	11. Provident Fund Deposit-Linked Insurance Fund		80,000	
8,000	12. Losses		12	
83,055	13. Miscellaneous		4,227	
1,24,17,306	Total C– Other Charges			83,18,390
9,55,40,440	Total Head 2—Administration Expenses			9,95,03,434
96,58,97,162	Total Carried Over.			1,15,79,54,360

A. See paragraph 1.5 of the explanatory notes in Annexure I.
B. See paragraph 1.6 of the explanatory notes in Annexure I.
C. See paragraph 1.7 of the explanatory notes in Annexure I.

Previous year (1977-78)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,44,54,48,030	Total Brought Forward		1,57,65,48,341

1,44,54,48,030	Total Carried over	1,57,65,48,341

Previous year (1977-78)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
96,58,97,162	Total Brought Forward.		1,15,79,54,360
	3. Hospitals and Dispensaries.		
31,53,779	1. Provision for depreciation of Hospital Buildings transferred to fund.	36,44,523	
91,00,566	2. Provision for Repair & Maintenance of Hospitals/Dispensaries transferred to fund.	1,05,69,117	
1,22,54,345	Total Head 3—Hospitals & Dispensaries.		1,42,13,640
	4. Capital Construction/Emergency Reserve Fund.		
13,19,26,600	1. Capital Construction.	@14,67,59,400	
6,70,73,985	2. Emergency Reserve Fund.	@@5,15,24,188	
19,90,00,585	Total Head 4—Capital Construction/Emergency Reserve Fund.		19,82,83,588
1,17,71,52,092	Total Expenditure on Revenue Account.		1,37,04,51,588
26,82,95,938	To excess of Income over Expenditure carried over to Balance Sheet.		20,60,96,753
1,44,54,48,030	GRAND TOTAL		1,57,65,48,341

New Delhi,
Dated 31st May, 1979.

@ As per decision dated 1-2-1974 of the Standing Committee of the Corporation 10% of the total revenue derived from Employers' and Employees' contribution is credited to the Capital Construction Reserve Fund for construction of hospitals/dispensaries/ other medical institutions and office buildings/staff quarters.

@@ This represents transfers to Emergency Reserve Fund as per decision of the Corporation in its meeting held on 17th March, 1973. The Corporation has laid down that 20% of the excess of income over expenditure (whole of the amount when excess is less than rupees one crore) should be credited to the Emergency Reserve Fund.

Previous year (1977-78)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,44,54,48,030	Total Brought Forward		1,57,65,48,341
1,44,54,48,030	GRAND TOTAL		1,57,65,48,341

(M. L. SOBTI)
Financial Adviser &
Chief Accounts Officer,
Employees' State Insurance Corporation

APPENDIX

EMPLOYEES' STATE

Balance Sheet as at

Previous year (1977-78)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
	Balance of excess of Income over Expenditure.		
1,09,52,56,496	As per last Balance Sheet.	1,36,35,52,434	
26,82,95,938	Addition during the year.	20,60,96,753	
1,36,35,52,434			1,56,96,49,187
	RESERVE FUNDS.		
	1. Capital Construction Reserve Fund.		
43,73,52,629	As per last Balance Sheet.	58,65,21,536	
13,19,26,600	ADD provision made during the year.	14,67,59,400	
1,72,42,307	Interest received from Investments.	1,56,85,195	
58,65,21,536			A 74,89,66,131
	2. Permanent (Partial & Total) Disablement Benefit Reserve Fund.		
18,51,87,173	As per last Balance Sheet.	17,43,15,231	
6,96,93,000B	Provision made during the year.	6,38,60,000	
95,13,980	Interest received from Investments.	89,54,711	
(—)5,48,23,748C	LESS surplus as per fifth Quinquennial Report on Valuation	—	
20,95,70,405	Total carried over of this Head.	24,71,29,942	
1,95,00,73,970	Total carried over		2,31,86,15,318

A. See Receipt and Payment Account in Statement A.

B. This includes Rs. 1,76,00,000/- as one time additional cost on account of the increase in the rates of Permanent Disablement Benefit with effect from 1-10-77.

C. The surplus as per 5th Quinquennial Report on Valuation was adjusted in 1977-78.

B

INSURANCE CORPORATION

31st March, 1979

Previous year (1977-78)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
	Lands and Buildings (wholly owned by the Corporation).		
	(a) Buildings for Offices of the Corporation.		
1,80,57,416	As per last Balance Sheet	2,00,22,893	
19,65,477	Additions during the year.	1,09,48,278	
2,00,22,893	Total (a)	3,09,71,171	
	(b) Hospitals and Dispensaries.		
29,79,95,923@	As per last Balance Sheet.	32,32,08,822	
2,52,12,899	Additions during the year.	10,73,59,190	
32 32 08,822@@	Total (b)	43,05,68,012	
34,32,31,715			46,15,39,183£
	Lands and buildings (Jointly owned by the Corporation and State Governments) Corporation's share.		
	Hospitals and Dispensaries.		
9,26,807	As per last Balance Sheet.	9,26,807	
—	Additions during the year.	—	
9,26,807			9,26,807
34,41,58,522	Total Carried Over		46,24,65,990

@ See paragraph 2 1 of the explanatory notes in Annexure II.

@@ See paragraph 2 2 of the explanatory notes in Annexure II.

£ Includes Rs 23,56,31,423/- representing assets created out of General Cash Balance,

Previous year (1977-78)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,95,00,73,970	Total Brought Forward.		2,31,86,15,318
20,95,70,405	Total Brought Forward of this Head.	24,71,29,942	
(—)3,52,55,174	LESS payments made during the year.	(—)6,08,44,036	
17,43,15,231			18,62,85,906
	3. Dependants' Benefit Reserve Fund.		
8,26,77,671	As per last Balance Sheet.	9,57,86,859	
2,30,25,000 @	Provision made during the year.	1,44,68,000	
40,59,767	Interest received from Investments.	49,20,649	
(—)62,34,353	LESS surplus as per 5th Quinquennial Report on Valuation.	—	
(—)77,41,226	LESS payments made during the year.	(—)1,00,68,768	
9,57,86,859	4. Employees' State Insurance Corporation Provident Fund.		10,51,06,748
3,58,92,828	As per last Balance Sheet.	4,12,24,332	
	ADD amount credited during the year.		
99,50,538	(i) Employees' Subscription.	1,23,56,746	
2,62,181	(ii) Corporation's Contribution.	2,65,372	
29,39,240	(iii) Interest on Employee's and Corporation's shares.	34,24 462	
1,64,098	(iv) Incentive Bonus.	24,261	
4,92,08,885	Total carried over of this head.	5,72,95,173	
2,22,01,76,060	Total Carried over.		2,61,00,07,964

@ This includes Rs. 1,04,00,000/- as one time additional cost on account of increase in the rates of Dependants' Benefit with effect from 1-10-977.

Previous year (1977-78)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
34,41,58,522	Total Brought Forward		46,24,65,9
	Amount advanced for Capital expenditure		
	(a) Amount advanced from General Cash Balance		
4,95,54,760	As per last Balance Sheet	4,54,36,075	
	ADD payments made during the year	54,469	
(—)41,18,685	LESS adjustments and recoveries	(—)50,95,498	
4,54,36,075@	Total (a)	@ 4,03,95,046	
	(b) Amount advanced from Capital Construction Reserve Fund		
13,41,76,637	As per last Balance Sheet	19,18,99,835	
8,23,26,026	ADD payments made during the year	8,05,49,148	
(—)2,46,02,828	LESS adjustments and recoveries	(—)11,36,79,267	
19,18,99,835	Total (b)	15,87,69,716	
23,73,35,910			19,91,64,762
	Staff Cars		
5,31,617	As per last Balance Sheet	5,65,196	
33,579	Additions during the year	—	
5,65,196			5,65,196
58,20,59,628	Total Carried Over		66,21,95,948

@ Represents amounts originally advanced for repair & maintenance of E. S. I. Projects before creation of the Capital Construction Reserve Fund in the year 1970-71. It was noticed that the works done included certain items of capital nature, these were thus adjusted under this head during the year.

Previous year (1977-78)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
2,22,01,76,060	Total Brought Forward		2,61,00,07,964
4,92,08,885	Total brought forward of the Sub-Head	5,72,95,173	
(—)79,60,565	LESS payments made during the Year	(—)84,26,704	
4,12,48,320			
	LESS amount transferred to :		
(—)23,988	(i) Pension Reserve Fund	(—)16,635	
—	(ii) Unclaimed Deposit	(—)6,908	
4,12,24,332			4,88,54,926
	5. Provident Fund Deposit-Linked Insurance Fund		
50,000	As per last Balance Sheet	75,063	
1,00,000	Provision made during the year	80,000	
—	Interest and Gain received from Investments	3,853	
(—)74,937	LESS payments made during the year	(—)50,434	
75,063			1,08,482
	6. Employees' State Insurance Corporation-Group Insurance Fund		
—	As per last Balance Sheet	—	
—	Contribution received during the year	3,15,880	
—	Interest and Gain received from Investments	—	
—	LESS Premium paid to Life Insurance Corporation	(—)2,40,000	
—			75,880
2,26,14,75,455	Total Carried Over		2,65,90,47,25

Previous year (1977-78)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
58,20,59,628	Total Brought Forward		66,21,95,948
	Permanent Advance to the Heads of Offices of the Corporation		
64,061	As per last Balance Sheet	78,766	
14,857	ADD payments made during the year	8,385	
(—) 152	LESS recoveries made during the year	(—) 240	
78,766			86,911
	Advance of Pay on transfer to the Employees of the Corporation		
28,597	As per last Balance Sheet	20,358	
1,24,138	ADD payments made during the year	1,16,471	
(—)1,32,377	LESS recoveries made during the year	(—)1,08,282	
20,358			28,547
	Advance of T.A. on transfer to the Employees of the Corporation		
91,683	As per last Balance Sheet	79,236	
1,73,663	ADD payments made during the year	1,78,346	
(—)1,86,110	LESS recoveries made during the year	(—)1,62,518	
79,236			95,064
58,22,37,988	Total Carried Over		66,24,06,470

Previous year (1977-78)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
2,26,14,75,455	Total Brought Forward		2,65,90,47,252
	7. Depreciation Reserve Fund of buildings for the Offices of the Corporation (including staff quarters).		
26,43,052	As per last Balance Sheet	30,73,809	
2,58,732	Provision made during the year	3,33,218	
1,72,025	Interest and Gain received from Investments	1,57,884	
30,73,809			35,64,911
	8. Depreciation Reserve Fund of Hospital buildings		
2,91,12,568	As per last Balance Sheet	3,44,63,168	
31,53,779	Provision made during the year	36,44,523	
21,96,821	Interest received from Investments	17,70,467	
3,44,63,168			3,98,78,158
	9. Depreciation Reserve Fund of Staff Cars		
5,04,613	As per last Balance Sheet	5,95,318	
42,668	Provision made during the year	21,616	
48,037	Interest received from Investments	28,848	
—	LESS payments made during the year	(—)33,580	
5,95,318			6,12,202
2,29,96,07,750	Total Carried Over		2,70,31,02,523

Previous year (1977-78)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
58,22,37,988	Total Brought Forward		66,24,06,470
	Advance for the purchase of Conveyance to the Employees of the Corporation.		
8,78,529	As per last Balance Sheet	10,40,844	
7,58,516	ADD payments made during the year	9,86,490	
(—)5,96,201	LESS recoveries during the year	(—)6,72,607	
10,40,844			13,54,727
	Miscellaneous Advances to the Employees of the Corporation (Festival Advances, Flood Advances and Fan Advances).		
8,46,031	As per last Balance Sheet	6,69,672	
8,51,071	ADD payments made during the year	£32,94,188	
(—)10,27,430	LESS recoveries made during the year	(—)10,65,131	
6,69,672			28,98,729
	House Building Advance		
67,24,154	As per last Balance Sheet	83,81,477	
26,22,991	ADD payments made during the year	27,57,935	
(—)9,65,668	LESS recoveries made during the year	(—)11,82,352	
83,81,477			99,57,060
	Advance payments on behalf of State Governments		
8,643	As per last Balance Sheet	1,463	
1,994	ADD payments made during the year	2,358	
(—)9,174	LESS recoveries made during the year	(—)2,494	
1,463			1,327
59,23,31,444	Total Carried Over		
	See paragraph 2.3 of the explanatory notes in Annexure II.		67,66,18,313

Previous year (1977-78)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
2,29,96,07,750	Total Brought Forward		2,70,31,02,523
	10. Repairs and Maintenance Reserve Fund of buildings for the Offices of the Corporation (including staff quarters).		
48,31,089	As per last Balance Sheet	49,41,497	
7,50,325	Provision made during the year	9,66,332	
1,05,983	Interest received from Investments	1,43,929	
(—)7,45,900	LESS amount adjusted on receipt of certified statements of expenditure	(—)4,39,062	
49,41,497			@56,12,696
	11. Repairs and Maintenance Reserve Fund of Hospital buildings		
6,13,81,189	As per last Balance Sheet	7,13,44,246	
91,00,566	Provision made during the year	1,05,69,117	
28,19,239	Interest received from Investments	24,76,467	
(—)19,56,748	LESS amount adjusted on receipt of certified statements of expenditure	(—)24,08,509	
7,13,44,246			*8,19,81,321
2,37,58,93,493	Total Carried Over		2,79,06,96,540

@ See Receipt and payment Account in Statement B.

* See Receipt and payment Account in Statement C.

Previous year (1977-78)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
59,23,31,444	Total Brought Forward		67,66,18,313
	Amount advanced to State Govt./State P.W.D. etc. towards Repairs and maintenance of Hospitals/Dispensaries/Offices of the Corporation and Staff Quarters.		
	(a) Offices of the Corporation		
24,87,105	As per last Balance Sheet	21,37,929	
3,35,194	ADD payments during the year	10,48,311	
(—)6,84,370	LESS cash refunds.	(—)3,85,694	
21,37,929			28,00,546
	(b) Hospitals/Dispensaries/Annexes		
1,65,92,609	As per last Balance Sheet	2,31,36,821	
74,47,292	ADD payments made during the year	64,54,893	
(—)9,03,080	LESS cash refunds	(—)15,73,718	
2,31,36,821	£ Miscellaneous Advances		2,80,17,996
17,73,696	As per last Balance Sheet	20,82,545	
22,19,743	ADD payments made during the year	15,04,776	
(—)19,10,854	LESS receipts during the year	(—)20,38,313	
20,82,545			15,49,008
61,96,88,739	Total Carried Over		70,89,85,863

£ See paragraph 2.4 of the explanatory notes in Annexure II.

Previous year (1977-78)		Liabilities	Amount	Total
Rs			Rs	Rs
2,37,58,93,493		Total Brought Forward		2,79,06,96,540
	12	Pension Reserve Fund for the Employees of the Corporation		
6,90,24,383		As per last Balance Sheet	7,85,80,959	
57,06,876		Provision made during the year	51,71,765	
42,93,580		Interest received from Investments	40,36,770	
8,59,938		Adjustment as per 5th Quinquennial Report on Valuation	(—)33,66,688	
(—)13,27,806		LESS payments made during the year	( )14,41,702	
23,988		ADD amount transferred from ESIC Provident Fund	6,635	
7,85,80,959				8,29,87,739
	13	Emergency Reserve Fund		
20,75,09,770		As per last Balance Sheet	28,33,47,207	
6,70,73,985		Provision made during the year	5,15,24,188	
87,63,452		Interest realised on Investments	1,45,55,845	
28,33,47,207				34,94,27,240
2,73,78,21,659		Total Carried Over		3,22,31,11,519

Previous year (1977-78)		Assets	Amount	Total
Rs.			Rs.	Rs.
61,96,88,729		Total Brought Forward		70,89,85,863
	@	Loans to State Governments		
2,92,63,430		As per last Balance Sheet	2,73,23,100	
—		ADD payments made during the year	—	
(—)19,40,330		LESS amount refunded by State Governments	(—)25,17,133	
2,73,23,100				2,48,05,967
		Remittances		
	£	Cash Remittances		
(—)36,95,754		As per last Balance Sheet	6,00,419	
2,58,38,85,748		ADD debits during the year	2,97,53,81,683	
(—)2,57,95,89,575		LESS credits during the year	(—)2,97,82,27,992	
6,00,419				(—)22,45,890
		Other Remittances		
	□	Exchange Account		
(—)183		As per last Balance Sheet	36,745	
8,97,66,093		ADD debits during the year	8,92,65,278	
(—)8,97,29,165		LESS credits during the year	(—)8,93,62,424	
36,745				(—)60,401
64,76,49,003		Total Carried over		73,14,85,539

@ Represents loans granted to the Government of Maharashtra prior to 1977-78 for construction and expansion of Employees' State Insurance Projects in the State.

£ See paragraph 2.5 of the explanatory notes in Annexure II.

□ See paragraph 2.6 of the explanatory notes in Annexure II.

Previous year (1977-78)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
2,73,78,21,659	Total Brought Forward		3,22,31,11,519
	14. Compassionate Reserve Fund for the Employees of the Corporation		
10,000	As per last Balance Sheet	10,000	
31,000	Provision made during the year	35,000	
—	Interest received from Investments	521	
(—)31,000	LESS payments made during the year	(—)17,753	
10,000			27,768
	Deposits		
	Deposits of securities.		
3,55,615	As per last Balance Sheet	3,85,964	
2,76,355	ADD deposits during the year	5,33,608	
(—)2,46,006	LESS deposits repaid during the year	(—)3,25,558	
3,85,964			5,94,014
	Deduction from bills payable to other parties		
62,581	As per last Balance Sheet	31,755	
12,49,025	ADD amount credited during the year	14,08,355	
(—)12,79,851	LESS payments made during the year	(—)13,82,732	
31,755			
	Unclaimed Deposits in the ESIC Provident Fund		57,378
41,961	As per Balance Sheet	50,706	
9,330	ADD amount credited during the year	6,908	
(—) 585	LESS payments made during the year	(—)32,361	
50,706			25,253
2,73,83,00,084	Total Carried Over		3,22,38,15,932

Previous year (1977-78)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
64,76,49,003	Total Brought Forward		73,14,85,539
	INVESTMENTS AT COST		
	1. Capital Construction Reserve Fund		
21,27,31,000	As per last Balance Sheet	30,53 29,804	
9,32,43,804	ADD Investments made during the year	5,89,58,851	
(—)6,45,000	Deduct—realisation on maturity or sale of Investments	@ —	
30,53,29,804			36,42,88,655
	2. Permanent (partial and Total) Disablement Reserve Fund		
18,51,86,072	As per last Balance Sheet	17,43,15,230	
2,54,03,758	ADD Investments made during the year	1,19,70,676	
(—)3,62,74,600	LESS realisation on maturity or sale of Investments	@ —	
17,43,15,230			18,62,85,906
	3. Dependants Benefit Reserve Fund		
8,26,77,106	As per last Balance Sheet	9,57,86,859	
2,71,15,753	ADD Investments made during the year	93,19,881	
(—)1,40,06,000	LESS realisation on maturity or sale of Investments	@ —	
9,57,86,859			10,51,06,740
1,22,30,80,896	Total Carried Over		1,38,71,66,840

@ See paragraph 2.7 of the explanatory note in Annexure II.

Previous year (1977-78)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
2,73,83,00,084	Total Brought Forward		3,22,38,15,932
	Deposits from I.L.O. for Family Planning Project		
—	As per last Balance Sheet	—	
5,00,000	ADD deposits during the year	7,00,000	
(—)5,00,000	LESS payments to the Family Planning Project	(—)7,00,000	
—			
	@ Miscellaneous Deposits		
14,36,216	As per last Balance Sheet	28,12,557	
62,50,102	ADD deposits received during the year	29,95,780	
(—)48,73,761	LESS deposits repaid during the year	(—)52,22,729	
28,12,557			5,85,608
2,74,11,12,641	Total Carried Over		3,22,44,01,540

@ Represents deposits not classified elsewhere.

Previous (1977-78)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,22,30,80,896	Total Brought Forward		1,38,71,66,840
	4. Employees' State Insurance Corporation Provident Fund.		
3,58,88,000	As per last Balance Sheet	4,12,24,332	
1,19,87,732	ADD investments made during the year	76,30,594	
(—)66,53,400	LESS realisation on maturity or sale of investments	@ —	
4,12,24,332			4,88,54,926
	5. Provident Fund Deposit Linked Insurance Reserved Fund		
—	As per last Balance Sheet	75,063	
75,063	ADD investments made during the year	33,419	
—	Deduct realisation on maturity or sale of investments	@ —	
75,063			1,08,482
	6. Group Insurance Fund		
—	As per last Balance Sheet	—	
—	ADD investment made during the year	75,880	
—	Less realisation on maturity or sale of investments	@ —	
—			75,880
1,26,43,80,291	Total Carried Over		1,43,62,06,128

@See paragraph 2.7 of the explanatory notes in Annexure II.

Previous year (1977-78)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
2,74,11,12,641	Total Brought Forward.		3,22,44,01,540
2,74,11,12,641	Total Carried Over.		3,22,44,01,540

Previous year (1977-78)	Assets		Amount	Total
Rs.			Rs.	Rs.
1,26,43,80,291	Total Brought Forward			1,43,62,06,128
	7. Depreciation Reserve Fund of buildings for the Offices of the Corporation (including staff quarters).			
26,41,400	As per last Balance Sheet		30,73,808	
12,13,408	ADD investments made during the year		4,91,103	
(—)7,81,000	LESS realisation on maturity or sale of investments	@	—	
30,73,808				35,64,911
	8. Depreciation Reserve Fund of Hospital Buildings			
2,91,12,525	As per last Balance Sheet.		3,44,63,168	
1,19,88,643	ADD investments made during the year.		54,14,990	
(—)66,38,000	LESS realisation on maturity or sale of investments	@	—	
3,44,63,168				3,98,78,158
	9. Depreciation Reserve Fund of Staff Cars			
5,02,935	As per last Balance Sheet.		5,61,738	
78,803	ADD investments made during the year		50,464	
(—)20,000	LESS realisation on maturity or sale of investments	@	—	
5,61,738				6,12,202
1,30,24,79,005	Total Carried Over			1,48,02,61,399

@See paragraph 2.7 of the explanatory notes in Annexure II.

Previous year (1977-78)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
2,74,11,12,641	Total Brought Forward.		3,22,44,01,540

2,74,11,12,641	Total Carried Over	3,22,44,01,540

Previous year (1977-78)	Assets		Amount	Total
Rs.			Rs.	Rs.
1,30,24,79,005	Total Brought Forward.			1,48,02,61,399
	10. Repairs and Maintenance Reserve Fund of buildings for the Offices of the Corporation (including staff quarters).			
23,43,545	As per last Balance Sheet.		28,03,568	
12,96,023	ADD investment made during the year.		8,582	
(—)8,36,000	LESS realisation on maturity or sale of investments.	@	..	
28,03,568				28,12,150
	11. Repairs and Maintenance Reserve Fund of Hospital Buildings.			
4,47,87,593	As per last Balance Sheet.		4,82,07,426	
1,87,40,833	ADD investments made during the year.		57,55,899	
(—)1,53,21,000	LESS realisation on maturity or sale of investments.	@	..	
4,82,07,426				5,39,63,325
1,35,34,89,999	Total Carried Over.			1,53,70,36,874

@ See paragraph 2.7 of the explanatory notes in Annexure II.

Previous year (1977-78)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
2,74,11,12,641	Total Brought Forward.		3 22,44,01,540

2,74,11,12,641	Total Carried Over.	3,22,44,01,540

Previous year (1977-78)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs	Rs.
1,35,34,89,999	Total Brought Forward.		1,53 70 36,874
	12. Pension Reserve Fund for the Employees of the Corporation.		
6,84,29,455	As per last Balance Sheet.	7,85,80,959	
4,39,11,504	ADD investments made during the year.	44,06,780	
(—)3,37,60,000	LESS realisation on maturity or sale of investments. @	..	
7,85,80,959			8,29,87,739
	13. Emergency Reserve Fund.		
20,75,00,000	As per last Balance Sheet.	28,33,47,207	
9,18,47,207	ADD investments made during the year.	6,60,80,033	
(—)1,60,00,000	Deduct—Realisation on maturity or sale of investments. @	..	
28,33,47,207			34,94,27,240
1,71,54,18,165	Total Carried Over.		1,96,94,51,853

@See paragraph 2.7 of the explanatory notes in Annexure II.

Previous year (1977-78)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
2,74,11,12,641	Total Brought Forward.		3,22,44,01,540
2,74,11,12,641	**Grand Total**		**3,22,44,01,540**

NEW DELHI,
Dated : 31st May, 1979.

Previous year (1977-78)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,71,54,18,165	Total Brought Forward		1,96,94,51,853
	14. Compassionate Reserve Fund		
..	As per last Balance Sheet	9,999	
9,999	ADD investments made during the year	17,769	
..	LESS realisation on maturity o r sale of investments @	..	
9,999			27,768
	General Cash Balance.		
72,83,10,000	Investment as per last Balance Sheet	95,95,31,370	
45,42,21,370	ADD investments made during the year	50,45,98,079	
(—)22,30,00,000	LESS realisation on maturity of sale of investments	(—)27,23,56,000	
95,95,31,370			1,19,17,73,449
26,98,063	Cash in hand	32,90,768	
6,34,55,044	Cash with Bankers	5,98,57,702	
6,61,53,107			£6,31,48,470
1,02,56,84,477	Total Cash Balance.		1,25,49,21,919
2,74,11,12,641	GRAND TOTAL		3,22,44,01,540

@ See paragraph 2.7 of the explanatory notes in Annexure II.
£See paragraph 2.8 of the explanatory notes in Annexure II.

(M.L. Sobti)
Financial Adviser &
Chief Accounts Officer,
Employees' State Insurance Corporation

ANNEXURE-I

Explanatory notes on Income and Expenditure Accounts

1.1 **"A" on page ii**

The amount includes Corporation's share of expenditure on the initial equipments purchased for the hospitals. Also see paragraphs 2.1 & 2.2 of the explanatory notes on the Balance Sheet.

1.2 **"B" on page ii**

The increase in expenditure is mainly on account of additional coverage, enhancement of the duration of Sickness Benefit payable to an insured person under Section 49 of the Employees' State Insurance Act, 1948 from 56 days to 91 days in any two-consecutive periods with effect from 1-5-1977 and increase in the amount of average daily rate of benefit consequent on increase of wages.

1.3 **"C" on page ii**

The surplus of Rs. 5,48,23,748 as per 5th Quinquennial Report on Valuation was adjusted in 1977-78. The provision during 1977-78 included one time additional cost (Rs. 1,76,00,000) on account of increase in rates of Permanent Disablement Benefit.

1.4 **"D" on page vii**

The surplus of Rs. 62,34,353 as per 5th Quinquennial Report on Valuation was adjusted in 1977-78. The provision during 1977-78 included one time additional cost (Rs. 1,04,00,000) on account of increase in rates of Dependents' Benefit.

1.5 **"A" on page vi**

This includes telegraphic charges on bank transfers and commission charged by the Associate Banks of the State Bank of India for the sale of contribution stamps.

1.6 **"A" on page vi**

This excludes Rs. 5,61,035 pertaining to pensionary liability of the employees of Directorate (Medical) Delhi which is included under '1-A (ii) Medical Benefits' being shareable expenditure with the Delhi Administration.

1.7 **"C" on page No. vi**

In the 5th quinquennial valuation as on 31st March, 1974, the Value recommended that annual provision for Pension Reserve Fund should be made at the rate of 12 per cent of the emoluments of the employees instead of 14%. The excess provision of 2% together with interest thereon has been adjusted during the year.

ANNEXURE-II

Explanatory Notes on Balance Sheet

2.1 □ On Page No. xi

This includes expenditure of Rs. 49,542 and Rs. 25,35,343 incurred under special orders on initial equipment for hospital during 1970-71 (Bihar) and 1972-73 (West Bengal).

2.2 @ on Page No. xi

The expenditure on equipment for hospitals is being booked under the head '1. A. Medical Benefits (i) payment to State Governments etc. as the Corporation's share of the expenditure incurred on providing medical treatment and maternity facilities'. Capitalisation of expenditure incurred on providing initial equipment for hospitals is under consideration of the Corporation in consultation with the State Governments and the Director of Audit, Central Revenues.

2.3 £ On Page No. xvii

The increase in expenditure under the head 'Miscellaneous Advances', is on account of advances made to Employees' State Insurance Corporation's employees for flood relief on the same terms and conditions as were applicable to the employees of the Central Government.

2.4 $ On Page No. xix

Include— (i) Advances to Controller of Stationery, Calcutta.

(ii) Advances to Public Works Departments.

(iii) Advances to Printing & Stationery Departments of the State Govts.

(iv) Advances to Regional Offices and other offices of the Corporation.

(v) Advances to Municipal Committee Local Bodies etc.

(vi) Advances for legal charges.

(vii) Advances to Corporation's departmental canteens.

(viii) Other advances which are not classified elsewhere.

2.5 £ On Page No. xxi

The term 'Cash Rimittances' denotes transfer of funds (cash) from one Account circle to another and vice versa. The revenue of the Corporation is collected by sale of stamps/cash realisation through the State Bank of India and its Associate Banks. The contributions received are transferred to the accounts of the respective Regional Office Account No. 1 (Collection Account) and finally transferred to Account No. 1 (Central) of the Headquarters Office. Funds for administrative expen-

diture and benefit payments to insured persons are provided to Regional Offices/Local Offices from Central Account No. 1 (Headquarters Office) by making transfers. All such transactions in transferring funds from one office to another are known as 'Cash Remittances'.

The minus balance of Rs. 22,45,890 under the head 'Cash Remittances' represents adjustment of certain credits in the account of the Corporation for which per contra debits could not be effected for want of debit advices from the bank.

2.6 $ On Page No. xxi

The term 'other Remittances—Exchange Account' denotes book adjustments between one office of the Corporation and the other and vice versa. Transactions originating in one office of the Corporation adjustable in the books of another office of the Corporation are transferred through Exchange Account.

The minus balance of Rs. 64,401 under the head 'other Remittances—Exchange Account' represents adjustment of certain credits in the accounts of the Corporation for which per contra debits (Responding items) could not be effected before the close of accounts for 1978-79.

2.7 ¢ On Page No. xxiii, xxv, xxvii, xxix, xxxi, & xxxiii

The decrease in receipts under 'Interest and Dividends' is due to investments being made since 1st October, 1976, in time deposits under 'Re-investment Plan' of the State Bank of India under which interest falling due will be credited to the Corporation's account on maturity of an investment. Further, upto the year 1977-78, the securities allocated to General Cash Balance were those which yielded monthly interest. With the introduction of revised system of distribution of the interest amongst General Cash Balance and other reserve funds on a proportionate basis from the current financial year, the interest receipts in the General Cash Balance have gone down. However, shortfall of interest in General Cash Balance has been compensated by increased receipts of interest under other reserve funds.

2.8 £ On Page No. xxxiii

Cash with bankers comprises the following

	(Rupees in lakhs)
(i) Balances in Regional Office Account No. I (Collection Account)	134.96

Cash available in Account No. 1 of the Regional Office (Collection Account) represents contributions received on 30th & 31st March, 1979. This was invested in the first week of April, 1979.

(ii) Balances in Regional Offices/Directorate (Medical) Delhi Account No. II for meeting Administration expenses & expenditure on medical care in Delhi	159.73

Rs. 159.73 lakhs in Regional Office Account No. II was required for disbursing salary on 2-4-79 and to meet other administrative expenditure during the first 3 weeks of the month.

(iii) Balances in Account No. II of the Local Offices	303.87

Weekly average payment of cash benefits to insured persons is over Rs. 1 crore. The balance of Rs. 303.87 lakhs in Account No. II of Local Offices was required to meet their requirements for 3 weeks.

STATEMENT-A

Receipt and Payment Account of Capital Construction Reserve Fund for the year 1978-79 as at 31st March, 79.

	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
Opening Balance	58,65,21,536		Assets created out of Capital Construction Reserve Fund	22,59,07,760	
Contribution during the year	14,67,59,400		Advances paid to Construction Agencies	15,87,69,716	
Interest on investments	1,56,85,195		Amount available in the Fund	36,42,88,655	
		74,89,66,131			74,89,66,131

STATEMENT-B

Receipt and Payment Account of the Repair and Maintenance Reserve Fund of Buildings for the Offices of the Corporation (including staff quarters).

	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
Opening Balance	49,41,497		Amount advanced to State Governments/State Public Works Departments towards repair and maintenance of offices of the Corporation 'A'	36,25,302	
Provision made during the year	9,66,332		Amount available in the Fund	28,12,150	
Interest on investments	1,43,929				
Cash refunds of unutilised advances made by the State Governments/State Public Works Departments	3,85,694				
		64,37,452			64,37,452
		'A'	Amount advanced to State Govts.		Rs. 36,25,302
			Less Cash refunds of unutilised advances	Rs.3,85,694	
			Less Amount adjusted on receipt of certified statement of expenditure	Rs 4,39,062	
					Rs. 8,24,756
			Balance as per balance sheet (page xix)		Rs. 28,00,546

STATEMENT-C

Receipt and Payment Account of Repair and Maintenance Reserve Fund of Hospital Buildings/Dispensaries/Annexes etc.

	Rs.	Rs.			Rs.	Rs.
Opening Balance	7,13,44,246		Amount advanced to State Governments State Public Works Departments towards repair & maintenance of Hospitals/Dispensaries/Annexes.	A	3,20,00,223	
Provision made during the year	1,05,69,117					
Interest on investments	24,76,467					
Cash refunds of unutilised advances made by the State Governments State Public Works Departments.	15,73,718		Amount available in the Fund.		5,39,63,325	
		8,59,63,548 A				8,59,63,548
			Amount advanced to State Govts.			Rs. 3,20,00,223
			Less Cash refunds of unutilised advances	Rs.	15,73,718	
			Less Amount adjusted on receipt of certified statements of expenditure	Rs.	24,08,509	
						Rs. 39,82,227
			Balance as per balance sheet (page xix)			Rs. 2,80,17,996

Administrative cost compared with Benefits paid etc.

	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
			(In Rupees)			
I. Total Administrative cost.	7,34,57,795	6,60,68,976	7,77,62,505	8,77,45,918	9,55,40,440	9,95,03,434
II. Contribution						
(i) Employers' & Employees' Shares	20,37,86,214	60,34,74,995	73,15,86,339	1,23,61,94,824	1,31,11,81,105	1,45,78,73,675
(ii) Employers' Share only	21,41,95,502	2,16,80,542	1,78,07,427	93,97,151	25,97,022	17,57,264
(iii) Employees' Share only	22,76,57,964	1,00,74,058	1,00,09,537	1,07,22,754	48,90,539	71,05,946
(iv) Interest	..	..	..	1,78,865	5,97,322	8,57,102
Total :	64,56,39,680	63,52,29,595	75,94,03,303	1,25,64,93,594	1,31,92,65,988	1,46,75,93,987
III. Total Expenditure on Revenue Account	59,90,70,572	62,49,05,056	75,58,05,845	1,01,91,84,702	1,17,71,52,092	1,37,04,51,588
IV. Total Benefits	45,14,88,325	46,45,26,360	57,23,86,508	70,85,36,816	87,03,56,722	1,05,84,50,926
Percentage relationship of Administrative cost to :						
Contributions	7.72%	10.40%	10.24%	6.98%	7.24%	6.78%
Expenditure on Revenue Account	8.32%	10.57%	10.29%	8.61%	8.12%	7.26%
Benefits	10.04%	14.22%	13.59%	12.38%	10.98%	9.40%

Note : IV does not include share of Medical Benefit expenditure borne by the State Governments.

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the foregoing accounts for the year 1978-79 and the Balance Sheet as on 31st March 1979 of the Employees' State Insurance Corporation and obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the Audit Report appended, I certify as a result of my audit, that in my opinion these accounts and the Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Corporation according to the best of my information and explanations given to me and as shown by the books of the Corporation.

(K.C. DAS)
DIRECTOR OF AUDIT
CENTRAL REVENUES

New Delhi
Dated 19th December, 1979

CONSOLIDATED AUDIT REPORT
ON THE ACCOUNTS OF THE
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
FOR THE YEAR 1978-79

Audit Report on the accounts of the Employees' State Insurance Corporation 1978-79.

1. General :

(i) The Employees' State Insurance Corporation was set up in October, 1948 under Employees' State Insurance Act, 1948. The Act was amended by the Employees' State Insurance (Amendment) Acts of 1951, 1966 and 1975 and applied to all factories other than seasonal factories which use power and where twenty or more persons are/were employed for wages. All employees getting monthly remuneration up to Rs. 1,000 are covered under the Scheme.

(ii) The Scheme is being extended gradually to the following classes of establishments under Section 1(5) of the Employees' State Insurance Act, 1948, namely—

(a) Smaller power-using factories employing 10-19 persons and non-power using factories employing 20 or more persons.

(b) Shops, cinemas, theatres, hotels and restaurants, road motor transport and newspaper establishments employing 20 or more persons.

The scheme was in operation at different centres in the States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal and Union Territories of Chandigarh, Delhi, Mahe, Goa, Daman and Diu and Pondicherry.

(iii) During 1978-79, the provisions of the Act were extended to 9,744 factories/establishments covering 2.73 lakhs employees. The number of factories/establishments covered by the Act as on 31-3-1979 was 59,054 having 58.16 lakhs employees (49,310 factories/establishments and 55.43 lakhs employees on 31-3-1978).

(iv) An analysis of the income and expenditure of the Corporation for the year 1977-78 and 1978-79 is given below :—

Income			Expenditure	
	1977-78	1978-79	1977-78	1978-79
	(Rupees in lakhs)		(Rupees in lakhs)	
Employees' & Employers Contribution	1,31,12	1,45,79	Benefits to insured persons and their families	
Employers' Contribution only	26	17	A- Medical Benefits	44,47	49,90
Employees' Contribution	49	71	(i) Payment to State Governments etc., as Corporation's share of their expenses on providing medical treatment		
Interest on contribution	6	9			
State Government's share towards medical benefits initially incurred by the Corporation.	40	1,10			
			(ii) Medical treatment and care and maternity benefit expenses incurred directly by the Corporation.	2,64	2,97
Interest & Dividends	8,01	5,28	B—Cash and other benefits to insured persons and their families paid directly by the Corporation	39,93	52,97
Miscellaneous	4,21	4,51			
			2. Administrative Expenses		
			A. Superintendence	4,73	5,15
			B. Field work	3,59	3,97
			C. Other Charges	1,24	83
			3. Hospitals and Dispensaries	1,22	1,42
			4. Capital Construction Reserve Fund	13,19	14,68
			5. Emergency Reserve Fund	6,71	5,15
			6. Excess of income over Expenditure	26,83	20,61
	1,44,55	1,57,65		1,44,55	1,57,65

2. Perspective Plan for extension of E.S.I. Scheme—Inadequate coverage of.

On a review of the progress of E.S.I. Scheme, the Estimates Committee of Parliament mentioned in the 123rd Report that the total coverage achieved by the Scheme was much less than what it should have been and recommended the setting up of a Review Committee for perspective planning. The Committee on Perspective Planning was accordingly set up in 1972. This committee recommended (i) a 5-year Perspective Plan in regard to the extension of ESI Scheme in three phases, (ii) a phased programme for the coverage of establishments and factories, and (iii) targets for the 5 years period ending 1977-78.

The phased programme commenced from 1974-75 (one year late) on account of non-completion of physical arrangements necessary for implementation of the Scheme. The coverage under the new sectors of employment against the target was as under :—

Year	Target	Actual achievement (figures stated to be provisional)
1973-74	4 lakhs	Nil
1974-75	7 lakhs	1.45 lakhs
1975-76	9 lakhs	0.76 lakhs
1976-77	9 lakhs	1.83 lakhs
1977-78	9 lakhs	0.85 lakhs
1978-79	..	1.39 lakhs
	38 lakhs	6.28 lakhs

The Corporation gave (September, 1979) the following reasons for its inability to achieve the targets :—

(i) Non-availability of physical and financial resources with State Governments to provide medical cover.

(ii) Mines could not be deemed as 'Factories' without amendment to Section 2 (12) of the ESI Act.

(iii) Ministry of Labour stated in April 1976 that extension of the Scheme to banks and insurance establishments (9.53 lakhs) might be considered later with mines and plantations (17.55 lakhs).

(iv) Big public sector undertakings (oil refineries/HEC) and plants (TISCO, IISCO etc.) had been left uncovered due to strong opposition from workers.

The Corporation was, therefore, not in a position to indicate approximate dates by which the targets suggested by the Committee on Perspective Planning would be achieved.

3. Annual Accounts : Balance Sheet.

(a) Miscellaneous Deposits :

A credit balance of Rs. 5.86 lakhs (unclassified deposits) was lying unadjusted under "Suspense Account—Miscellaneous Deposits" as on 31-3-1979. The year-wise break up was as under :

Year	Amount (in lakhs of Rupees)
1974-75	(—) 0.25
1975-76	(—) 0.08
1976-77	0.21
1977-78	1.07
1978-79	4.91

(b) Non-exhibition of cost of equipment :

As already pointed out in the Audit Report for 1977-78, the expenditure incurred on the equipment provided initially to the hospitals and annexes amounting to Rs. 2,77.07 lakhs, had not been exhibited in the Balance Sheet except for a sum of Rs. 25.85 lakhs. The Corporation stated (October 1979) that the matter was still under consideration.

(c) Valuation of assets and liabilities :

In term of Section 37 of ESI Act,1948, the valuation of assets and liabilities of the Corporation is required to be done after every five years. The quinquennial valuation report due at close of 1973-74 though adopted by the Standing Committee at its meeting held on 28-5-1979 was yet (November 1979) to be adopted by the Corporation. In the meanwhile, the sixth quinquennial valuation of assets and liabilities of the Corporation as on 31-3-1979 has become due.

(d) Depreciation Reserve Fund of Staff Cars

Depreciation Reserve Fund of Staff Cars (Rs.6.12 lakhs) exceeded the cost of staff cars (Rs. 5.65 lakhs) as per Balance Sheet as on 31-3-1979. The Corporation stated that the reserve fund was still not adequate enough in view of increase in the cost of staff cars and that the matter was being further examined.

(e) Damages not properly accounted for

The damages recovered from employers under Section 85 B (1) of the Employees' State Insurance Act was classified under sub-head 'Fees, fines and forfeitures' in the Income nad Expenditure Account with effect from January 1977. The amount actually recovered on this account did not agree with that shown in the Income and Expenditure Account under the above said sub-head, for the year 1977-78 and 1978-79 as shown below :

Year	Amount Recovered	Amount Reflected in the Accounts	Differences
	Rs.	Rs.	Rs.
1977-78	33,45,764	26,18,074	7,27,690
1978-79	32,72,959	29,93,978	2,78,981

These differences had not been reconciled so far.

4. Advances :

(i) Out of the amounts advanced to State Governments State Public Works Departments for construction of hospitals, dispensaries and other buildings and for purchase of hospital equipments of capital nature for projects, Rs. 19,91.65 lakhs (year-wise analysis given below) remained unadjusted on 31-3-1979.

Year in which advance paid		Amount remaining unadjusted on 31-3-1979 (Rupees in lakhs)	
Upto	1970-71	4,21.20	*Rs. 2.65 lakhs stated to be refunded by Governments of Kerala, Madhya Pradesh and Tamil Nadu without furnishing details of the projects.
	1971-72	61.50	
	1972-73	51.23	
	1973-74	31.83	
	1974-75	1,06.26	
	1975-76	85.47	
	1976-77	2,30.52	
	1977-78	4,02.51	
	1978-79	6,03.78	
	Total	19,94.30	
	Less refund	2.65*	
	Balance	19,91.65	

The Corporation stated that out of the above, Rs. 69.98 lakhs had since been adjusted upto June, 1979.

(ii) Out of the amounts advanced for stationery and liveries, legal charges etc. and to departmental Canteens, Rs. 15.49 lakhs (year-wise details given below) remained unadjusted on 31-3-1979.

Year in which paid		Amount remaining unadjusted on 31-3-1979 (Rupees in lakhs)
Upto	1970-71	5.92
	1971-72	0.46
	1972-73	0.39
	1973-74	0.11
	1974-75	1.62
	1975-76	0.84
	1976-77	0.32
	1977-78	2.54
	1978-79	3.29
	Total	15.49

(iii) Out of the amounts advanced to State Governments/State PWD for repairs and maintenance of hospitals/dispensaries and other office buildings wholly owned by the Corporation, Rs. 3,08.19 lakhs (year-wise details given below) remained unadjusted on 31-3-1979.

Year in which paid		Amount remaining unadjusted as on 31-3-1979 (Rupees in lakhs)
Upto	1974-75	70.52
	1975-76	39.01
	1976-77	53.21
	1977-78	66.02
	1978-79	79.43
	Total	3,08.19

The Corporation stated (October 1979) that vigorous efforts for expeditious settlement of outstanding advances were being made.

5. Infructuous expenditure on the continuance of E. S. I. Dispensary at Narangarh (Orissa)

An E.S.I. Dispensary was opened in a rented building on a monthly rent of Rs. 57 from 29-3-1962 to cater to the medical needs of the employees of a foundary at Narangarh (Orissa). The foundary was closed in March, 1973 on account of lock out and its employees were debarred from availing the medical benefit from April, 1974. The dispensary however, continued to exist and medicines worth Rs. 2,906.63 and Rs. 575 46 were supplied to the dispensary during November, 1974 and January, 1976 respectively from the Central Medical Store. The Medical Officer was withdrawn in October, 1977 but the skeleton staff continued to be retained. The continuance of the dispensary without any functions entailed expenditure of Rs. 1.43 lakhs; the amount reimbursed by the Corporation towards 7/8th share of expenditure worked out to Rs. 1.25 lakhs. The Corporation stated (December 1979) that the Government of Orissa was responsible for the provision of medical treatment of insured persons and their families and the closure of a dispensary when the circumstances so warranted was an administrative action not requiring the sanction of the Corporation.

6. Imposition of penal damages for belated payment of Contribution

According to Regulation 31-A, of the E.S.I. (General) Regulations, 1950, an employer shall be deemed to have not paid the contribution in time if he fails to submit the contribution cards within the time prescribed in Regulation 26. Section 85(B) (1) of the E.S.I. Act, 1948 (introduced in 1975 through an amending Act), empowers the Corporation to recover damages not exceeding the amount of arrears from the employers where they failed to pay the contributions due in time and in terms of Section 85(B) (2) of the Act, these damages may be recovered as arrears of land revenue.

As per records made available by the Headquarters Office of the Corporation, the year-wise position of damages levied, recovered and progressive balances at the close of each year during 1976-77 to 1978-79 was as under :

Year	Damages levied	Damages levied + last year's balance (Rupees in lakhs)	Damages recovered	Progressive balance
1976-77	54.64	54.66	6.56	48.10
1977-78	1,84.32	2,32.42	33.46	1,98.96
1978-79	(Not available)		32.73	(Not available)

The position in respect of the regions where outstanding damages exceeded Rs.10 lakhs as on 31-3-1978 was as under :

S.No.	State/Region	Amount (Rupees in lakhs)
1.	Andhra Pradesh	16.87
2.	Kerala	19.70
3.	Maharashtra	34.10
4.	Punjab	25.85
5.	Rajasthan	11.00
6.	West Bengal	56.00

The position emerging as a result of test audit in some of the regions was as under :

(i) Andhra Pradesh

Damages were levied in 3,008 cases during 1976-77 to 1978-79. The amount of damages levied was, however, stated to be not available. However, information furnished in respect of cases where damages levied exceeded Rs.50,000 in each case was as under :

Year	Belated payments		Damages imposed		Damages recovered		Damages waived		Damages outstanding	
	No. of cases	Amount of contribution	No.	Amount (Rupees in lakhs)	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1976-77	5	24.05	5	4.07	..	..	1	2.15	4	1.92
1977-78	7	20.91	7	2.99	..	..	2	1	5	2.06
1978-79	4	3.96	4	1.40	..	..	3	1.39	Balance recovered	

(ii) Assam

The position of arrears and recovery of damages for the period from September, 1975 to March 1979 was as under :

Delayed Contribution	Damages proposed	Damages waived	Damages reduced	Damages imposed	Damages recovered	Damages outstanding
			(Rupees in lakhs)			
28.31	7.94	1.64	4.08	2.22	0.99	1.23

Of the outstanding damages, 24 cases involving Rs.0.35 lakh were stated to have been referred to the Collector for recovery, leaving 7 cases involving Rs.0.88 lakh yet to be reported to the collector.

(iii) Delhi

The position of the damages levied, recovered and outstanding at the close of each year for 1976-77 to 1978-79 was as under :

Year	Previous balance	Damages levied during the year	Total damages	Damages recovered during the year	Damages outstanding as on 31st March of the year
		(Rupees in lakhs)			
1976-77	Not available	0.51	0.51	0.15	0.36
1977-78	0.36	3.03	3.39	1.54	1.85
1978-79	1.85	8.54	10.39	1.84	8.55

The information regarding the number of cases reviewed for levy of the penal damages was not available. The information regarding damages leviable was not furnished by the regional office. A test check of contribution cards in 15 cases, however, revealed that damages amounting to Rs. 14.11 lakhs were leviable due to late receipt of the cards but no action to issue the show cause notices to the defaulting employers was taken (October, 1979).

(iv) Gujarat

The position of the damages imposed, recovered, outstanding etc. as available, was as under :

Year	No. of cases of belated payments	Damages imposed No. of cases	Damages recovered Amount (Rupees in lakhs)		Damages waived upto 31-3-79	Damages outstanding as on 31-3-1979
1976-77	1,056	769	6.00			..
1977-78	1,887	1,453	7.12	3.25		..
1978-79	980	99	10.40	1.14	1.64	17.50

The information regarding penal damages leviable could not be furnished as the same was stated to be open to variation after passing the speaking orders. Damages waived and outstanding as shown above indicated the progressive position for the years 1976-77 to 1978-79 as on 31st March, 1979. The reasons for waiving the damages after imposition were not explained.

(v) Maharashtra

The position of show cause notices issued, damages levied and recovered during the last three years was as under :

Year	Show cause notices issued		Speaking orders issued		Damages recovered
	No.	Damages leviable (Rupees in lakhs)	No.	Damages levied	
1976-77	2,353	71.90	161	0.98	1.02
1977-78	2,717	1,51 99	535	4.11	2.68
1978-79	2,541	2,57 80	1,126	9.33	4.22

It was observed that in 10 cases there were delays ranging from 14 months to 28 months in issuing speaking orders. In 10 other cases involving damages amounting to Rs 17,39 lakhs as per show cause notices, speaking orders were not issued even after 12 to 33 months after the issue of the shown cause notices In 7 cases involving damages of Rs.51.06 lakhs, show cause notices had not been issued either on the grounds that instalments facility was granted to the establishments to clear the arrears or show cause notices issued for earlier periods had not been finalised. It was stated that the number of show cause notices issued was enormous and the work of processing these cases further was done in a phased manner.

(vi) Tamil Nadu

The year-wise details regarding the number of cases and amount of belated payments, damages leviable, imposed, waived and outstanding were not available in the regional office. A sum of Rs 2.19 lakhs was reported to have been recovered as penal damages during 1976-77 to 1978-77 A test check of 19 files of belated payments relating to Coimbatore (16) and Madras (3), however, revealed the following :

Year	Belated Payments		Damages leviable	Damages imposed		Damages recovered upto 30-9-79		Damages outstanding as on 30-9-79	
	No. of cases	Balance contribution		No of cases	Amount	No. of cases	Amount	No. of cases	Amount
				(Rupees in lakhs)					
1976-77	90	44 49	12.43	60	1.72	35	0.27	25	1 45
1977-78	50	23.01	12 21	33	2.50	22	0.55	11	1.95
1978-79	11	5.26	4.26	3	0 86	2	0.07	1	0.29

Out of 151 cases of belated payments, penal damages were imposed in 96 cases and waived in one case. Action to impose penal damages in the remaining 54 cases was still pending (October 1979). The Regional Director of the Corporation stated (October 1979) that the delay in levy of penal damages was due to the late receipt of sanction to posts and time taken to comply with procedural formalities for levy of penal damages.

(vii) Karnataka

A test check of the relevant files etc. revealed that in Karnataka region action to issue show cause notices to the defaulters was to be taken in 989 cases till 31st March 1979 Recovery of damages amounting to Rs.10,84,485 in 434 cases of delay in payment of contributions was pending with the revenue authorities as on 30-6-1979. There were 169 cases wherein final orders imposing penal damages were passed till 31st July, 1979 but these were yet (September, 1979) to be referred to the revenue authorities for collection. The total amount of damages involved in these cases was stated to be not readily available The regional office did not maintain any register/records to show employer-wise details of damages leviable, damages imposed, waived or reduced, recovered and balance outstanding recovery The monthly return submitted by the regional offices to the Corporation s headquarters also did not show the details of damages except those recovered

7. Arrears of Contributions

As on 31st March, 1979 contributions amounting to Rs 24,61,45 lakhs for the period ending 31st March, 1978 were overdue for recovery from the employers and employees of 14,655 factories (year-wise details given below)

Year	Employers' Contribution	Employees' Contribution	Employers' and Employees' combined Contribution (started w e f 1-7-1973) due from employers	Total
		(Rupees in lakhs)		
Upto December, 1971	4,75 55	1,66 84		6,42 39
1-1-1972 to 31-12-1972	1,37 66	55 45		1,93 11
1-1-1973 to 31-12-1973	1,51 96	78 08	37 75	2,67 79
1-1-1974 to 31-12-1974			1,24 53	1,24 53
1-1-1975 to 31-12-1975			2,03 87	2,03 87
1-1-1976 to 31-12-1976	..	..	3,50 18	350 18
1-1-1977 to 31-12-1977			4,81 68	4,81.68
1-1-1978 to 31-3-1978			1,97 90	1,97 90
Total	7,65 17	3,00 37	13,95 91	24,61.45

The Regions in which the arrear for recovery exceeded Rs.1,00.00 lakhs were Bihar (Rs.1.25.49 lakhs). Delhi (Rs.1,51.21 lakhs), Karnataka (Rs.1.37.36 lakhs) Kerala (Rs.1.50.89 lakhs), Madhya Pradesh (Rs.1,70.34 lakhs). Bombay (Rs.3,04.08 lakhs), Punjab (Rs. 1,00.04 lakhs), Tamil Nadu (Rs.1.35.93 lakhs), Uttar Pradesh (Rs.2,41.58 lakhs) and West Bengal (Rs.5,35.66 lakhs).

Out of 14,656 factories from which contributions for the period ending 31st March 1978 were due as on 31st March, 1979, factories numbering 552 were in default for more than Rs.0.50 lakh each. The Corporation stated (September, 1979) that it had initiated legal action to recover outstanding arrears of Rs.18,81.98 lakhs and action in cases involving Rs.3,81.53 lakhs was under consideration/process and for the remaining arrears of Rs.1,97.94 lakhs legal action was not possible due to court injunction/orders or for the reason that factories had gone into liquidation or had disputed coverage. The Corporation stated (December, 1979) that the arrears as on 31-3-1979 stood at Rs.27,43.58 lakhs (includes Rs.11,30.95 lakhs on account of arrears for seven regions upto 30-9-1978).

8. Factories/Establishments pending Inspection :

According to the instructions contained in the Hand book of Instructions of Inspection of Factories, all definitely covered factories are to be inspected at least once a year and uncovered factories are to be surveyed once in every two consecutive years.

Inspection of 5,565 factories/establishments upto the calendar year 1978 was in arrears as on 31-3-1979 (year-wise details given below) :—

Year upto		Inspection due	Inspection conducted	Inspection in arrear as on 31-3-1979
Upto	1973	..	..	37
	1974	30,453	30,381	72
	1975	31,645	31,521	124
	1976	36,299	35,735	564
	1977	47,104	45,626	1478
	1978	54,660	49,095	5565*

*Includes factories/establishments which could not be inspected in earlier years.

(ii) The number of uncovered factories/establishments required to be surveyed by 31-3-1978 was 9,744 of which 5,044 factories/establishments remained unsurveyed on 31-12-1978. This however, did not include 1,315 factories/establishments surveyed in addition to the targets in Andhra Pradesh (447), Punjab (433) and West Bengal (435). The States in which the performance was less than 50% were Bihar (7%) Gujarat (27%) and Madhya Pradesh (32%).

(iii) Of the factories/establishments in respect of which survey/inspection reports had been received, the exact date of coverage of 6,575 factories/establishments (details given below) had not been determined finally.

Sl.No.	Name of State	No. of cases lying pending final coverage	Position upto
1.	Andhra Pradesh	187	April, 1979
2.	Assam	21	February, 1979
3.	Bihar	275	April, 1979
4.	Delhi	835	February, 1979
5.	Karnataka	69	May, 1979
6.	Kerala	33	May, 1979
7.	Madhya Pradesh	226	September, 1
8.	Maharashtra	2,068	April, 1979
9.	Nagpur	Nil	July, 1979
10.	Pune	772	March, 1979
11.	Orissa	3	April, 1979
12.	Punjab	1,167	April, 1979
13.	Rajasthan	289	May, 1979
14.	Tamil Nadu	338	March, 1979
15.	Uttar Pradesh	292	May, 1979
	Total	6,575	

The figures in respect of Gujarat and West Bengal were not available. The Corporation could not furnish the year-wise position of the pending cases in respect of Bihar, Delhi, Madhya Pradesh, Orissa, Punjab and Tamil Nadu.

9. Unrealised decretal Amount :

(i) Employees' State Insurance Courts issued decrees against employers who failed to deposit the contribution with the Corporation. Out of decrees for Rs.31.17 lakhs remaining unrealised upto 31-3-1979, decrees for Rs.30.85 lakhs (year-wise details given below) remained un-executed as on 31-3-1979.

Year of decree		Lakhs of Rs.
Upto	1974-75	23.59
	1975-76	0.84
	1976-77	4.68
	1977-78	1.55
	1978-79	0.19
	Total	30.85

(ii) The State-wise figures where the decretal amount exceeded one lakh rupees as on 31-3-1979 were as under :

State	Rs. in lakhs
Gujarat	2.74
Madhya Pradesh	8.54
Maharashtra	2.99
Punjab	1.79
Rajasthan	1.72
Tamil Nadu	1.76
Uttar Pradesh	5 63
West Bengal	2.62

As regards non-realisation, the Corporation stated (September 1979) that the decrees were realised by filing regular execution proceedings with the executing Courts, and that the delay was not only due to the lengthy and difficult procedure adopted by the Courts but also because of the tactics adopted by the judgment debtors. It was also stated that as the execution of decress depended mtirely on the State Government machinery, the Corporation had no direct say in the matter.

K C. DAS,

Director of Audit

Central Revenues.

[No.Z-16016/3/79-HI]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

967 GI/80—17.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980